16 जुलाई, 2026 गुरूवार

नई दिल्ली
मूल्य : 01 रुपए
पृष्ठ : 08
वर्ष : 14
अंक : 105

RNI No. DELMUL/2012/47011

अनोखे अंदाज़ और निराले तेवर के साथ इन्साफ की डगर पर

टाइम्स ऑफ़ पीडिया

www.timesofpedia.com Email : timesofpedia@gmail.com

बल्लेबाज हनूमा ने गंभीर पर अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को अवसर देने का आरोप लगाया 07

संक्षिप्त वार्ता

सोनम वांगचुक के अनशन पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त

नई दिल्ली। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की लगातार बिगड़ती सेहत को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने उनके अनशन से जुड़े मामले में तत्काल सुनवाई करते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार से गुरुवार सुबह तक जवाब देने को कहा है। अदालत ने इस मामले को अत्यंत गंभीर बताते हुए जनहित याचिका पर सुनवाई की, जिसमें वांगचुक को तत्काल चिकित्सा सुविधा और जीवनरक्षक उपचार उपलब्ध कराने की मांग की गई है।

सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पिछले 18 दिनों से दिल्ली के जंतर-मंतर पर राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में कथित अनियमितताओं के विरोध में और शिक्षा मंत्री प्रमोद प्रधान के इस्तीफे की मांग के समर्थन में भूख हड़ताल पर हैं।

अभिजीत दीपके के लिए जंतर-मंतर पर धमकी देने लगा शख्स

नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स अभिजीत दीपके को कोई नुकसान होने पर पूरे दिल्ली एनसीआर में आग लगाने की धमकी दे रहा है। लोग दिल्ली पुलिस से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दिल्ली के जंतर-मंतर पर 20 जून से प्रदर्शन कर रही कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) भले ही अपनी अपेक्षा के मुताबिक भीड़ नहीं जुटा पा रही है, लेकिन बड़ी संख्या में यूट्यूबर और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स वहां अपने लिए वायरल वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

विश्वप्रसिद्ध जगन्नाथ रथयात्रा की शुरूआत आज से

10 लाख से अधिक भक्तों के पहुंचने की उम्मीद

ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्वप्रसिद्ध रथयात्रा 16 जुलाई से शुरू होकर 24 जुलाई तक चलेगी। इस नौ दिवसीय धार्मिक उत्सव में देश-विदेश से 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। रथयात्रा को लेकर पुरी में तैयारियों का दौर अंतिम चरण में हैं, तो वहीं होटल और लॉज महीनों पहले ही पूरी तरह बुक हो चुके हैं। ऐसे में प्रोफेसर डॉ शेख मकबूल इस्लाम की चर्चा भी हो रही है, जो कठोपनिषद् के प्रसिद्ध श्लोक का हवाला देते हुए कहते हैं कि जब शरीर स्वयं रथ है, बुद्धि सारथी है और आत्मा उसका स्वामी है, तो अलग रथ की आवश्यकता नहीं।

वेब वार्ता, पुरी

विश्वप्रसिद्ध रथ यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को लेकर जिला प्रशासन का कहना है, कि इस वर्ष फरवरी से ही होटल बुकिंग शुरू हो गई थी। मंदिर और रथयात्रा मार्ग के आसपास स्थित होटलों की सर्वाधिक मांग रही है। खासकर जिन होटलों की बालकनी या खिड़कियां रथयात्रा मार्ग की तरफ खुलती हैं, उनके कमरे सबसे पहले बुक हो गए। जैसे ही मांग बढ़ी वैसे ही किराए में भी भारी उछाल आ गया। सामान्य दिनों में 1,500 से 2,000 रुपये प्रतिदिन से मिलने वाले कमरे रथयात्रा के दौरान तीन दिनों के लिए 50 हजार रुपये तक में बुक किए जा रहे हैं। पूरे पुरी शहर में लगभग 1,200 होटल और लॉज हैं, जिनमें अधिकांश पहले से बुक हो चुके हैं।

हावड़ा की रथयात्रा ने खींचा ध्यान

इसी बीच पश्चिम बंगाल के हावड़ा की एक अनोखी रथयात्रा भी लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है। दरअसल यहां न तो विशाल रथ बनाया जाता है और न ही उसे रस्सियों से खींचा जाता है। बल्कि कोलकाता के सेंट पॉल कैथेड्रल मिशन कॉलेज के बांग्ला विभाग के प्रोफेसर डॉ. शेख मकबूल इस्लाम भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन के विग्रह को अपनी गोद में लेकर करीब 400 मीटर की परिक्रमा करते हैं। इस अनूठी यात्रा में हिंदू, मुस्लिम और ईसाई समुदाय के लोग समान रूप से भाग लेते हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार डॉ. शेख मकबूल इस्लाम वर्ष 1992 से भगवान जगन्नाथ पर शोध कर रहे हैं और इस विषय पर 14 से अधिक पुस्तकें लिख चुके हैं। वर्ष 1996 से उनके घर में भगवान जगन्नाथ का विग्रह स्थापित है, जबकि 2009 से वे हर वर्ष इस विशेष परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं।

इस अनूठी परंपरा का आधार है कठोपनिषद् का प्रसिद्ध श्लोक

वे अपनी परंपरा का आधार कठोपनिषद् के प्रसिद्ध श्लोक आत्मानं रथिनं विद्धि, शरीरं रथमेव तुङ्ग को बताते हैं। उनके अनुसार, जब शरीर स्वयं रथ है, बुद्धि सारथी है और आत्मा उसका स्वामी है, तो अलग रथ की आवश्यकता नहीं। डॉ. इस्लाम पूरी तरह शाकाहारी हैं और पुरी की परंपरा के अनुसार भगवान जगन्नाथ को 35 प्रकार के सात्विक भोग अर्पित करते हैं। उनकी यह पहल धार्मिक समरसता और सांस्कृतिक एकता का अनूठा उदाहरण मानी जाती है।

छतरपुर गोलीकांड: बाबा बागेश्वर के भाई शालिग्राम को पुलिस ने किया गिरफ्तार

किसान पर गोली चलाने का है आरोप

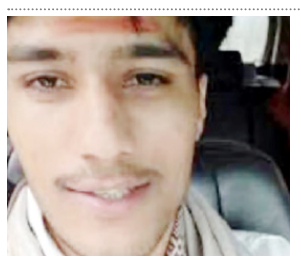

राजनगर थाना क्षेत्र में गौशाला के पीछे स्थित जमीन को लेकर हुए विवाद के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों में से दो को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिगराम गर्ग और अंकित मिश्रा शामिल हैं। मामले में एक नामजद आरोपी समेत एक अन्य आरोपी अब भी फरार है।

वेब वार्ता, छतरपुर

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, छतरपुर जिले के राजनगर थाना क्षेत्र के ग्राम कोड़ा में मंगलवार को फायरिंग का मामला सामने आया। पीड़ित किसान मोतीलाल कुशवाहा ने आरोप लगाया कि बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग ने उन्हें गोली मारी। घायल किसान का दावा है कि क्षेत्र के किसानों पर जमीन बेचने का दबाव बनाया जा रहा है। उनका आरोप है कि जो किसान जमीन बेचने से इनकार करते हैं, उन्हें धमकाया और मारपीट की जाती है। मोतीलाल कुशवाहा के अनुसार, इसी विवाद के दौरान उन पर गोली चलाई गई, जिससे वे घायल हो गए।

क्या कहा बाबा बागेश्वर ने?

पूरे मामले को लेकर बाबा बागेश्वर ने कहा कि शालिग्राम से उनका कोई लेना-देना नहीं है और यह बात वे तीन साल पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं। उन्होंने अपील की कि हर घटना में उनका नाम नहीं जोड़ा जाए। बाबा बागेश्वर ने कहा कि उनका परिवार केवल जैविक परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरा समाज और पूरा विश्व ही उनका परिवार है। वे समाज, राष्ट्र और सनातन धर्म के लिए कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि छतरपुर जिला और उनका परिवार बहुत बड़ा है, इसलिए कहीं न कहीं घटनाएं होती रहती हैं। ऐसे मामलों को व्यक्तिगत रूप से उनसे जोड़ना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस किसी ने भी अपराध किया है, उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो दोषी है, उसे कानून कठोर से कठोर दंड दे और भगवान भी उसे दंड दें। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरे मामले की विस्तृत जानकारी नहीं है, इसलिए वे तथ्यों पर टिप्पणी नहीं करेंगे।

भारत के 150 राफेल का चक्रव्यूह

वेब वार्ता, नई दिल्ली। भारत के संभावित 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के सौदे ने पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञों के बीच गहरी चिंता पैदा की है। मौजूदा 36 राफेल विमानों के साथ, यह अधिग्रहण भारतीय वायुसेना के बेड़े में कुल 150 राफेल जेट लाएगा, इससे इस्लामाबाद में रणनीतिक हलकों में बेचैनी साफ देखी जा सकती है। पाकिस्तानी विशेषज्ञ इस बात पर गहन चर्चा कर रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में राफेल का शामिल होना क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को कैसे प्रभावित करेगा। उनका मानना है कि इस खरीद से भारत की कई मोर्चों पर ऑपरेशनल क्षमताएं काफी मजबूत होंगी और लॉजिस्टिक्स व मेंटेनेंस की क्षमताएं भी बेहतर होंगी।

पाकिस्तानी सेना और हुकमरान खौफ : चीनी जे-10-सीई पर गहराया संकट

पाकिस्तान वायुसेना ने ऐतिहासिक रूप से भारत का मुकाबला करने के लिए उन्नत लड़ाकू विमानों को अपने बेड़े में शामिल किया है, साथ ही पायलट प्रशिक्षण, नेटवर्क-केंद्रित संचालन और आधुनिक एवियोनिक्स पर जोर दिया है। अमेरिकी एफ-16, चीनी जे-10सीई और जेएफ-17 ब्लॉक3 जैसे विमान इस रणनीति के केंद्र में रहे हैं। हालांकि, पाकिस्तानी विशेषज्ञ मानते हैं कि राफेल ऐसा मंच है जो उन्नत सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं, लंबी दूरी के हथियारों और बहु-भूमिका लचीलेपन का एक अद्वितीय संयोजन प्रदान करता है। इसका स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट अपनी सुरक्षा क्षमता को बढ़ाता है, जबकि मीटियोर बियॉन्ड-विजुअल-रेंज (बीवीआर) मिसाइलें हवाई युद्ध में एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी बनाती हैं। पहले 36 राफेल विमानों की सीमित संख्या के कारण भारत की तैनाती विकल्प सीमित थे, लेकिन अब 150 विमानों का विशाल बेड़ा भारतीय वायुसेना को एक साथ कई मोर्चों पर निरंतर उपस्थिति बनाए रखने में सक्षम बनाएगा। इस तरह के बदलाव से पाकिस्तान को अपने हवाई अभियानों की योजना बनाने, मिशन सौंपने और वायु रक्षा संसाधनों के आवंटन पर गंभीर रूप से पुनर्विचार करना पड़ेगा।

बंगाल में नई स्वास्थ्य बीमा योजना का ऐलान

कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के दायरे का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत योजना से वंचित लोगों के लिए नई मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने का ऐलान किया है। सरकार का दावा है कि इस योजना के तहत ऐसे परिवारों को भी सालाना 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाएगा, जो आयुष्मान भारत योजना की पात्रता शर्तों के कारण लाभ नहीं ले पा रहे हैं। सरकार के अनुसार राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू होने के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने आवेदन किया है, लेकिन केंद्र की योजना के पात्रता मानदंड और सामाजिक-आर्थिक व जाति जनगणना आधारित शर्तों के कारण कई परिवार इसके दायरे से बाहर रह गए।

पांच दिवसीय मानसून सत्र में क्या लिए जा सकेंगे पूरे सवाल ?

अनुपूरक बजट होगा पेश, 1,642 सवालों के जवाब देगी सरकार

वेब वार्ता, भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 24 जुलाई 2026 तक चलेगा। पांच दिनों के इस सत्र में सरकार कई महत्वपूर्ण विधायी और वित्तीय कार्यों को पूरा करने की तैयारी में है, जबकि विपक्ष ने भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता, पेपर लीक, किसानों की समस्याओं, स्वास्थ्य सेवाओं और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। ऐसे में सवाल किया जा रहा है कि इस सीमित दिनों वाले सत्र में लगाए गए सभी पश्नों के जवाब सरकार दे पाएगी?

विधानसभा सचिवालय के अनुसार राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से इस बार का सत्र काफी अहम माना जा रहा है। इस सत्र के लिए विधायकों द्वारा कुल 1,642 प्रश्न लगाए गए हैं। इनमें 841 तारांकित और 801 अतारांकित प्रश्न शामिल हैं। इन प्रश्नों के समयबद्ध और तथ्यात्मक उत्तर सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विभागों ने अपने-अपने नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने का काम किया है। ये अधिकारी सत्र के दौरान संबंधित मंत्रियों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएंगे, ताकि सदन में पूछे जाने वाले प्रश्नों का सटीक और प्रमाणिक जवाब दिया जा सके। बहरहाल विशेषज्ञ यही सवाल कर रहे हैं कि महज 5 दिन के इस सत्र में डेढ़ हजार से अधिक महत्वपूर्ण सवालों के जवाब सरकार क्या वाकई दे पाएगी?

जानकारी अनुसार सत्र के पहले चार दिनों यानी 20 से 23 जुलाई तक प्रतिदिन प्रश्नकाल आयोजित होगा। इसके बाद शासकीय कार्यों पर चर्चा की जाएगी और विभिन्न विभागों से जुड़े विषयों पर सदन में विचार-विमर्श होगा। इसी दौरान राज्य सरकार चालू वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट भी विधानसभा में प्रस्तुत करेगी, जिसे पारित कराने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जबकि सत्र के अंतिम दिन 24 जुलाई को भी प्रश्नकाल के साथ ही अशासकीय संकल्पों पर भी चर्चा कराए जाने की बात कही गई है।

मास्टर प्लान 2026: बड़वानी का फॉर्मेट तैयार

एमपी के 10 जिलों के विकास का खाका दिसंबर तक होगा साफ

वेब वार्ता, भोपाल

जल्द आम लोगों के सामने होंगे 10 जिलों का विकास फॉर्मेट

मध्य प्रदेश के कई शहरों में आगामी 20 से 25 वर्षों के विकास की दिशा तय करने के लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीएंडसीपी) विभाग ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। इसके तहत विभाग ने आधुनिक सैटेलाइट और ड्रोन सर्वे के आंकड़ों का इस्तेमाल करते हुए बड़वानी जिले का मास्टर प्लान जारी कर दिया है, जिसे आम जनता की आपत्तियों और सुझावों के लिए सार्वजनिक कर दिया गया है। इसके साथ ही खंडवा और रतलाम जिलों का ड्राफ्ट भी लगभग बनकर तैयार है।

इस योजना के अंतर्गत आगामी दिसंबर माह तक राज्य के करीब 10 जिलों के विकास प्रारूप आम लोगों के सामने होंगे। जिन अन्य प्रमुख जिलों के मास्टर प्लान पर तेजी से काम चल रहा है, उनमें सीहोर, विदिशा, शाजापुर, रीवा, कटनी, नरसिंहपुर और शहडोल शामिल हैं। औद्योगिक निवेश को गति देने के लिहाज से रीवा, शहडोल और कटनी को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि ये आपस में सीधे जुड़े हैं। वहीं भोपाल और देवास कॉरिडोर के मध्य स्थित होने और वहां हो रहे व्यावसायिक निमार्णों के चलते सीहोर के मास्टर प्लान को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है।

भोपाल-इंदौर में हो सकती है देरी

दूसरी ओर, प्रदेश के बड़े महानगरों जैसे भोपाल और इंदौर के मास्टर प्लान में फिलहाल कुछ समय लग सकता है।

नए सिरे से होगा तैयार

दरअसल, सरकार इन दोनों शहरों के साथ ही उज्जैन को मिलाकर पहले मेट्रोपॉलिटन रीजन घोषित करने की तैयारी में है, जिसके बाद इनके विकास का खाका नए सिरे से तैयार होगा। इसी तरह जबलपुर और ग्वालियर भी भविष्य में मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के रूप में विकसित किए जाएंगे।

मध्य प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली है खुशखबरी

सभी विभागों में 20 जुलाई तक पदोन्नति की तैयारी

वेब वार्ता, भोपाल। राज्य सरकार ने अपने सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति की प्रक्रिया 20 जुलाई से प्रारंभ हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र के पहले पूरी करने का लक्ष्य रखा है। सभी विभागों से कहा गया है कि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें जल्दी-जल्दी करके पदोन्नति आदेश जारी कर दिए जाएं।

दरअसल, सरकार चाहती है कि हाई कोर्ट में पदोन्नति नियम 2025 को लेकर कोई भी निर्णय आने से पहले प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। विभागों में पदोन्नति को लेकर बैठकें लगातार चल रही हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय ने सामान्य प्रशासन विभाग से एक जुलाई से अब तक की गईं पदोन्नतियों की रिपोर्ट मांगी हैं। उधर, विधानसभा सचिवालय में प्रथम श्रेणी के 15, द्वितीय श्रेणी के 40, तृतीय श्रेणी के 93 एवं चतुर्थ श्रेणी के 34 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया। पदोन्नति प्राप्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के प्रति आभार जताते हुए उनका सम्मान किया।

यूएई का मास्टरप्लान: नए बंदरगाह से बदलेगा खाड़ी व्यापार

वेब वार्ता, दुबई। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने होर्मुज जलडमरूमध्य को वैश्विक व्यापार के लिए एक नया और संवेदनशील मोर्चा बना दिया है। दोनों देशों के बीच रणनीतिक वर्चस्व की होड़ में, दुनिया के कई देशों की तेल आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिससे कुछ स्थानों पर किल्लत जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस गंभीर समस्या का समाधान निकालने के लिए, भारत के करीबी सहयोगी संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है, जिसके तहत अगले 18 महीनों में होर्मुज की निर्भरता को खत्म करने और तेल आपूर्ति के लिए एक नया, सुरक्षित विकल्प खड़ा करने का लक्ष्य रखा गया है।

दुबई की दिग्गज लॉजिस्टिक्स कंपनी डीपी वर्ल्ड अब होर्मुज स्ट्रेट के खतरे को स्थायी रूप से टालने की तैयारी में है। यूएई इसके लिए अपने पूर्वी तट पर एक बिल्कुल नया, आधुनिक और हाईटेक बंदरगाह तथा विशाल कंटेनर टर्मिनल बनाने की तैयारी में जुट गया है। इस रणनीतिक मास्टरप्लान का सीधा मकसद दुनिया के सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से एक जेबेल अली पर अपनी निर्भरता को कम करना है, ताकि होर्मुज के संकरे रास्ते में ईरान जब चाहे तब बाधा न डाल सके। जब से ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक करने की धमकी दी है, तब से खाड़ी

देशों का समुद्री व्यापार काफी प्रभावित हुआ है। मध्य पूर्व के सबसे बड़े और दुबई की आर्थिक शक्ति माने जाने वाले जेबेल अली पोर्ट पर व्यापारिक गतिविधियों में 90 से 95 प्रतिशत की भारी और ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है। इस विशाल पोर्ट पर अब बड़े मालवाहक जहाजों का आना-जाना लगभग पूरी तरह ठप हो चुका है। जेबेल अली सिर्फ एक बंदरगाह नहीं, बल्कि पूरी दुबई की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसलिए इस भयानक नाकेबंदी ने यूएई की चिंताएं बढ़ा दी हैं।

सुरक्षा का एक बहुत बड़ा कारण भी छिपा हुआ है

डीपी वर्ल्ड के इस नए मास्टरप्लान को लेकर दुनिया भर के कूटनीतिक और व्यावसायिक गलियारों में भारी हलचल है। इंफ्रास्ट्रक्चर विशेषज्ञों का दावा है कि अगर वैश्विक परिस्थितियां और फंडिंग योजना के अनुसार रहीं, तो यह नया पोर्ट और हाईटेक टर्मिनल मात्र 18 महीने के रिकॉर्ड समय में बनकर पूरी तरह तैयार हो सकता है। हालांकि, इसके अंतिम डिजाइन और बड़े वित्तीय इंतजामों पर अभी भी अंतिम दौर की बातचीत चल रही है। यूएई के शीर्ष अधिकारियों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस नए वैकल्पिक पोर्ट को बनाने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि जेबेल अली का महत्व खत्म हो जाएगा, बल्कि जेबेल अली वैश्विक व्यापार में अपना कद हमेशा बनाए रखेगा। जब से होर्मुज में तनाव बढ़ा है, डीपी वर्ल्ड ने मजबूरी में अपने ज्यादातर कार्गो जहाजों को जेबेल अली से हटाकर पूर्वी तट पर मौजूद फुजैरा और उसके पास के खोर फक्कन पोर्ट्स की तरफ मोड़ दिया है, जिससे वहां के समुद्र में जहाजों का भारी जाम लग गया है, जिसे दूर करना अब यूएई के लिए एक बड़ी चुनौती है। यूएई द्वारा इस नए पोर्ट को बनाने की इतनी बड़ी जल्दबाजी के पीछे सिर्फ व्यापारिक घाटा या आर्थिक नुकसान ही एकमात्र वजह नहीं है, बल्कि सुरक्षा का एक बहुत बड़ा कारण भी छिपा हुआ है।

संपादकीय

सोशल मीडिया के हमाम में

पुलिस के एक अधिकारी का निलंबन चकित करता है या एक पुलिस बैंड हारमनी ऑफ द पाइंस के प्रभारी विजय कुमार पर हुई कार्रवाई हैरान करती है। एक पुलिस अधिकारी के मशहूर होने के कारणों में कानून-व्यवस्था का पैमाना हो सकता है, लेकिन यहां जिस इंस्पेक्टर का जिक्र हो रहा है, वह म्यूजिक की शब्दावली में बैंड मास्टर है जिसके कंधों पर वर्दी का गौरव और सर्विस रूल्स की फाइल लटक रही है।

शौर्य, सूरत और सीरत में यहां यह मामला इतना भी आसान नहीं कि सोशल मीडिया में तू तू-मैं मैं से हल निकल आए या निर्णायक वोटिंग हो जाए। सरकारी नौकरी के नियम व वर्दी के सिद्धांत इतने भी नाजुक नहीं कि पुलिस बैंड को मात्र गवैया मान लें। यहां पूरी की पूरी हिमाचल पुलिस ने इस बैंड का प्रतिनिधित्व किया और इसलिए हुनरबाजी के शो में एक राज्य की वर्दी जीती थी। महफिल भले ही बैंड ने लूटी हो, लेकिन वहां मिला हर सलाम वर्दी के लिए और वर्दी के हित में था। इसलिए विजय कुमार को मिली शोहरत उसकी निजी उपलब्धि नहीं थी। जब तक शरीर पर वर्दी और वर्दी की पॉकेट में सरकारी पगार है, उसके जीवन की मर्यादाएं, शगल, शगुन और परंपराएं सरकारी दिशा-निर्देश से ही चलेंगी। ऐसे में आरोपों की खारिश तो भुगतनी ही पड़ेगी। सिविल सर्विस रूल्स उनके लिए इतने तीखे-इतने कांटेदार क्यों हुए, उसके ऊपर जांच ही कोई फैसला ले सकती है, फिर भी सोशल मीडिया के हमाम में कई वरिष्ठ अधिकारी भी अगर नापाक हुए हैं, तो कार्रवाइयों की ईमानदारी दोहरा व्यवहार नहीं कर सकती।

हमने कुछ प्रशासनिक अधिकारियों को नैतिकता और सेवा शर्तों का उल्लंघन करते देखा है, तो ये चैप्टर्स भी देखे जाने चाहिएं, ताकि सनद रहे। सार्वजनिक क्षेत्र के तहत सोशल मीडिया की फिजूलखर्ची का यह अदब है कि कई अध्यापक, साधारण कर्मचारी, मातहत अनुशासित परंपराएं भूल रहे हैं। कर्मचारियों-कर्मचारियों, अधिकारियों-कर्मचारियों और अधिकारियों-अधिकारियों के बीच सोशल मीडिया का खेल बेजा है। सोशल मीडिया के पाप भयंकर शक्ल अख्तियार न करें, इसके लिए देश-प्रदेश ही नहीं, समाज को भी नैतिक उच्चारण करना पड़ेगा। हम न तो विजय कुमार पर की गई कार्रवाई को श्रेष्ठ मानते हैं और न ही उनके आचरण को बरी करते हैं, फिर भी सबक लेने की गुंजाइश करेंगे। ऐसे मामलों में देश का कानून भी परिपक्व नहीं हुआ है। अभी अरुणाचल प्रदेश में यौन उत्पीड़न के मामले में स्कूल के शिक्षक वर्ग की शामत आई है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अब सोच यह है कि किस तरह आयु तक के बच्चे सोशल मीडिया ज्वाइन नहीं कर सकते। ऐसे में वे अभिभावक भी दोषी हैं जो दुधमुंहे बच्चे के हाथों में मोबाइल थमा कर अपने फर्ज की इतिश्री कर रहे हैं। जहां तक हिमाचल का प्रश्न है, ऐसे सबक का यथार्थ तब सिद्ध होगा, अगर सरकारी क्षेत्र के तमाम हथकंडे सोशल मीडिया की सतह से दूर रखे जाएं। इसी परिप्रेक्ष्य में पत्रकारिता के गुण-दोष भी आते हैं, जहां चंद हजार के निवेश से कोई भी अगंभीर, अप्रशिक्षित, अनियंत्रित, माकूल शिक्षा से वंचित व सामाजिक-राष्ट्रीय-प्रादेशिक सरोकारों से दूर व्यक्ति, हाथों में मोबाइल लिए संवेदना का सबक दे रहा है।

उच्च शिक्षा पर हावी होती महंगाई

समाज के वर्किंग क्लास और निम्न मध्यवर्ग में यह अहसास मजबूत हुआ है कि उनके बच्चे जीवन की दौड़ में तभी टिक सकते हैं जब वे शिक्षा प्राप्त करें। इसलिए यह समूह अब अपने बच्चों की शिक्षा के लिए हर तरह का संघर्ष कर रहा है। वह पेट काटकर, जमीन गिरवी रखकर, कर्ज लेकर भी बच्चों को पढ़ा रहा है। इसके कारण पिछले डेढ़-दो दशकों में प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा में दाखिला बढ़ा है, लैंगिक अंतर कम हुआ है। यह एक सकारात्मक संकेत है। लेकिन अगर फीस इसी तरह बढ़ती रही तो गरीब तबके को मन मारकर इस दौड़ से बाहर निकल जाना होगा। निश्चय ही उच्च शिक्षा से एक बड़े वर्ग का वंचित होना ठीक नहीं है।

हाल ही में संसदीय स्थायी समिति ने कहा है कि उच्च शिक्षा के लिए मौजूदा बजट आवंटन पर्याप्त नहीं है और शिक्षा पर खर्च बढ़ाकर जीडीपी का 6 प्रतिशत किया जाना चाहिए। समिति के अनुसार 2021-22 में भारत का शिक्षा व्यय केवल 4.12 प्रतिशत था, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के लक्ष्य से कम है। रिपोर्ट में महंगाई, नामांकन वृद्धि और शिक्षा की गुणवत्ता को देखते हुए अधिक निवेश की जरूरत बताई गई है। समिति ने चिंता जताई कि 2021-22 में भारत का कुल शिक्षा व्यय जीडीपी का केवल 4.12 प्रतिशत था। यह आंकड़ा एनईपी के लक्ष्य से काफी कम है। समिति का मानना है कि यदि भारत को वैश्विक स्तर की शिक्षा व्यवस्था विकसित करनी है तो शिक्षा पर निवेश जरूर बढ़ाना होगा। समिति ने 2018 से 2023 के बीच पुरुष और महिला छात्रों के सकल नामांकन अनुपात (ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो) का भी अध्ययन किया। रिपोर्ट में कहा गया कि इस अवधि में नामांकन अनुपात में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं देखी गई। समिति का मानना है कि मानव संसाधनों के बेहतर विकास और रोजगारोन्मुख शिक्षा के लिए उच्च शिक्षा में अधिक छात्रों को जोड़ना जरूरी है। इसी कारण उसने 2035 तक एनईपी-2020 के लक्ष्यों के अनुरूप शिक्षा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की सिफारिश की है। आज उच्च शिक्षा में बढ़ती महंगाई एक बड़ी चुनौती है, जो सामान्य मुद्रास्फीति की तुलना में कहीं अधिक तेजी से बढ़ रही है। शिक्षा का खर्च 10 से 12 प्रतिशत सालाना की दर से बढ़ रहा है जिससे उच्च शिक्षा की लागत हर 6-7 साल में दोगुनी हो जाती है। बढ़ते खर्च के कारण और इससे निपटने के तरीकों पर मंथन जरूरी है। उच्च शिक्षा इतनी महंगी क्यों हो रही है? मांग और आपूर्ति में असंतुलन : उच्च शिक्षा की भारी मांग (लगभग 20 फीसदी वार्षिक वृद्धि) और अच्छे गुणवत्ता वाले संस्थानों की सीमित आपूर्ति के कारण निजी संस्थान इसका फायदा उठाते हैं।

आधुनिक तकनीकों (लैब, सॉफ्टवेयर), अनुसंधान और बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने में आने वाली भारी लागत, शिक्षकों का वेतन और अनुपालन : उत्कृष्ट प्राध्यापकों का वेतन और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसे नियामक मानकों को पूरा करने का खर्च सीधे तौर

पर ट्यूशन फीस में जुड़ जाता है। महंगी शिक्षा के कारण अधिकांश छात्रों को भारी मात्रा में एजुकेशन लोन लेना पड़ता है, जिसकी अदायगी के लिए वे करियर की शुरूआत में ही कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। मध्यम और गरीब परिवारों पर दबाव : मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों को बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी संपत्ति गिरवी रखनी पड़ती है या अपनी बचत खत्म करनी पड़ती है। उच्च फीस और जीवनयापन के भारी खर्चों (हॉस्टल, यात्रा, कोचिंग) के कारण कई मेधावी छात्र बीच में ही पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों से देश में उच्च शिक्षा लगातार महंगी होती जा रही है। गरीब, मेहनतकश वर्ग ही नहीं, मध्यवर्ग के लिए भी हायर एजुकेशन हासिल करना आसान नहीं रह गया है। हाल तक यह माना जाता था कि कम से कम सरकारी संस्थानों में तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पढ़ाई कर ही लेगा, पर उन संस्थानों की भी बढ़ती फीस ने इस तबके की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। इस वर्ग के लिए तो प्राथमिक शिक्षा का खर्च उठाना भी कठिन होता जा रहा है। यह भारत के लिए एक बड़ी त्रासदी ही कही जाएगी, जहां दुनिया की सबसे युवा आबादी रहती है। आईआईएम (अहमदाबाद) की फीस वर्ष 2007 से 2022 के बीच 15 सालों में 4 लाख रुपए सालाना से बढकर 27 लाख रुपए सालाना पहुंच गई है जो कि 575 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। देश के प्रमुख चार आईआईएम की सालाना औसत फीस 25 लाख रुपए से ज्यादा है। जब सरकारी संस्थानों का यह हाल है तो निजी संस्थानों के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है। एक तो केंद्रीय विश्वविद्यालयों और आईआईटी-आईआईएम जैसी संस्थाओं की संख्या इतनी कम है कि कुछ चुनिंदा छात्र ही इन तक पहुंच पाते हैं। यानी उच्च शिक्षा तक पहुंचे छात्रों के एक छोटे से हिस्से का भी एक छोटा हिस्सा।

एक बड़ा हिस्सा इन संस्थानों की दौड़ से पहले ही बाहर हो जाता है। कुछ साल पहले तक फीस इत्यादि कम होने की वजह से कुछेक ग्रामीण और कस्बाई छात्र अपनी प्रतिभा और संघर्ष के बल पर ऐसे संस्थानों में किसी न किसी तरह पहुंच ही जाते थे। लेकिन अब तो इसकी संभावना बेहद कम होती जा रही है। हमारी उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम, परीक्षा और परिणामों का स्वरूप कुछ ऐसा हो गया है कि अनेक छात्रों का इन पर से भरोसा उठ चुका है। यह धारणा बन गई है कि सरकारी कॉलेजों से बस डिग्री ले लेनी है, ताकि नौकरी में जा सकें। मतलब एडमिशन लेना एक मजबूरी है। इसलिए पैसे लगाकर दाखिले की औपचारिकता पूरी की जाती है और जैसे-तैसे पढ़ाई के सत्र निपटाए जाते हैं। सच्चाई यह है कि देश भर के ज्यादातर विश्वविद्यालय और कॉलेज अब केवल नामांकन व परीक्षा लेने के केंद्र बन कर रह गए हैं। बच्चे दाखिला लेकर या तो कोचिंग संस्थानों का रुख कर रहे हैं या उस दौरान कोई छोटे-मोटे काम कर रहे हैं। अनेक कॉलेज क्लासों में अमूमन सन्नाटा पसरा रहता है। लेकिन अब तो इस पर भी आफत आ रही है। उनकी ट्यूशन फीस तो बढ़ ही रही है, नामांकन शुल्क, परीक्षा शुल्क में भी बढ़ोतरी जारी है। इसका खामियाजा लड़कियों को ज्यादा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि परिवार में शिक्षा के मद में जब कटौती की बात आती है, तो लड़कियों की पढ़ाई ही रोकी जाती है, खासकर ग्रामीण इलाकों में।

दलील दी जाती है कि लड़कियां तो बगैर शिक्षा और रोजगार के भी रह सकती हैं, क्योंकि उन्हें आगे चलकर मुख्यत: घर का ही काम संभालना है। इस समय तो अनेक प्राइवेट वित्तीय संस्थान गरीब छात्रों को उच्च शिक्षा लोन भी नहीं देते। वे कुछ ही सीमित कोर्स और संस्थाओं तक अपने लोन को सीमित रखते हैं, जहां केवल एक खास वर्ग के छात्र ही महंगी फीस देकर शिक्षा हासिल करते हैं। समाज के वर्किंग क्लास और निम्न मध्यवर्ग में यह अहसास मजबूत हुआ है कि उनके बच्चे जीवन की दौड़ में तभी टिक सकते हैं जब वे शिक्षा प्राप्त करें। इसलिए यह समूह अब अपने बच्चों की शिक्षा के लिए हर तरह का संघर्ष कर रहा है। वह पेट काटकर, जमीन गिरवी रखकर, कर्ज लेकर भी बच्चों को पढ़ा रहा है। इसके कारण पिछले डेढ़-दो दशकों में प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा में दाखिला बढ़ा है, लैंगिक अंतर कम हुआ है। यह एक सकारात्मक संकेत है। लेकिन अगर फीस इसी तरह बढ़ती रही तो गरीब तबके को मन मारकर इस दौड़ से बाहर निकल जाना होगा। निश्चय ही उच्च शिक्षा से एक बड़े वर्ग का वंचित होना भारी सामाजिक असमानता पैदा करेगा और आर्थिक विभाजन को भी गहरा करेगा। इसे कौन रोकेगा? याद रहे कि पर्याप्त निवेश के बिना विश्वस्तरीय और समावेशी शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य हासिल करना मुश्किल होगा।

डा. वरिंद्र भाटिया
कालेज प्रिंसीपल

साझा भविष्य की सबसे मजबूत नींव है युवा कौशल क्रांति

तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण तथा स्थानीय व वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के लिए प्रासंगिक अन्य कौशलों के विकास के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 15 जुलाई को ह्यविश्व युवा कौशल दिवसह्न मनाया जाता है। चूंकि यह दिन विश्वभर के युवाओं को रोजगार, काम और एंटरप्रेन्योर बनने के लिए जरूरी स्किल्स से लैस बनाने के लिए समर्पित है, इसीलिए यह दिवस मनाए जाने का काफी महत्व है। दरअसल पूरी दुनिया आज कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है, जिनमें से कई चुनौतियां खासकर युवा वर्ग को बहुत प्रभावित करती हैं। यह दिवस युवाओं और ह्यतकनीकी, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षणह्न (टीवीईटी) संस्थानों, फर्मों, नियोक्ताओं, श्रमिक संगठनों, नीति निमार्ताओं तथा विकास भागीदारों के बीच संवाद का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। यह दिन लैंगिक असमानता को समाप्त करने तथा कमजोर लोगों तक संसाधनों की पहुंच सुनिश्चित करने को बढ़ावा देने के लिए भी खास माना जाता है।

विभिन्न रिपोर्टों के मुताबिक पूरी दुनिया में 200 मिलियन से भी ज्यादा युवा या तो बेरोजगार हैं या उनके पास नौकरी तो है लेकिन वे गरीबी में जी रहे हैं। केवल 1997 और 2017 के बीच ही युवा आबादी में 139 मिलियन की वृद्धि हुई, वहीं युवा श्रम बल में 58.7 मिलियन की कमी आई। कोरोना काल के बाद तो युवा श्रम बल को लेकर स्थिति काफी बदतर हुई। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में पांच में से दो युवा श्रमिक प्रतिदिन 3.1 अमेरिकी डॉलर से भी कम पर जीवनयापन करते हैं और वैश्विक स्तर पर 4 में से 3 युवा कर्मचारी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में कार्यरत हैं, जो सभ्य काम नहीं है। वैश्विक स्तर पर अधिकांश युवा अभी भी स्थिर या संतोषजनक नौकरी पाने के लिए औसतन 13.8 महीने तक प्रतीक्षा करते हैं, जो शिक्षा से नौकरी में एक कठिन संक्रमण को दर्शाता है। चूंकि पूरी दुनिया में युवा बेरोजगारों बहुत बड़ी फौज है, इसलिए उनके लिए आने वाली चुनौतियों का सफलतापूर्वक प्रबंधन करने के कौशल से लैस होना और भविष्य में होने वाली बाधाओं को झेलने के लिए लचीलापन होना आवश्यक है। वैश्विक स्तर पर बढ़ती युवा बेरोजगारी आज की अर्थव्यवस्थाओं और समाजों के सामने विकसित और विकासशील देशों के लिए सबसे बड़ी समस्या है। इसीलिए विश्व युवा कौशल दिवस का मुख्य उद्देश्य बेरोजगारी और अल्प-रोजगार की चुनौतियों के संदर्भ में आज के युवाओं के लिए बेहतर सामाजिक-आर्थिक स्थिति प्राप्त करना है।

युवाओं को रोजगार, अच्छे कार्य और उद्यमिता के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करने के रणनीतिक महत्व को स्वीकार करने और साथ ही वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने तथा सतत विकास को आगे बढ़ाने के लिए ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 जुलाई 2014 को विश्व युवा कौशल दिवस मनाने की घोषणा की थी, तभी से यह दिवस 15 जुलाई को एक खास विषय के साथ मनाया जा रहा है। इस वर्ष इस दिवस के लिए ह्यसाझा भविष्य के लिए कौशलह्न विषय निर्धारित किया गया है, जो इस विचार को रेखांकित करता है कि भविष्य केवल तकनीकी दक्षता से नहीं बल्कि ऐसे संतुलित कौशलों से निर्मित होगा, जिनमें डिजिटल साक्षरता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हरित तकनीक, सामाजिक-भावनात्मक समझ, सहयोग, नवाचार और जिम्मेदार नागरिकता का समावेश हो।

भारत में 2015 में इसी दिन यानी 15 जुलाई को ही कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए ह्यप्रधानमंत्री कौशल विकास योजनाह्न (पीएमकेवीवाई) की शुरूआत की गई थी। इसके तहत युवाओं को मुफ्त में लघु अवधि का औद्योगिक कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे रोजगार प्राप्त कर सकें। 14 से 35 वर्ष के युवा इस मिशन के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। प्रशिक्षण के लिए तीन महीने, छह महीने या एक वर्ष के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होता है। कोर्स पूरा करने के पश्चात प्रमाणपत्र दिया जाता है, जो देशभर में मान्य है और इस कौशल प्रमाणपत्र के आधार पर आसानी से रोजगार प्राप्त किया जा सकता है। चूंकि युवा वर्ग समाज में अधिक न्यायसंगत, समान और प्रगतिशील अवसरों तथा समाधानों की मांग कर रहा है, इसलिए युवाओं के समक्ष आने वाली शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और लैंगिक समानता तक पहुंच जैसी बहुमुखी चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है और इसके लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें अपने कार्य वातावरण में अधिक रोजगार योग्य तथा अधिक उत्पादक बनाने के लिए गंभीर पहल किए जाने की भी जरूरत है।

भारत में केंद्र सरकार की ऐसी ही महत्वपूर्ण पहल है ह्यकौशल भारतह्न, जिसके जरिये सफल होने के लिए युवाओं को आवश्यक कौशल से लैस करने के प्रयास किए जाते हैं। ह्यस्किलिंग इंडियाह्न के तहत ह्यकौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालयह्न भारतीयों में ऐसे कौशल विकसित करने की पहल और योजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिससे वे राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान बढ़ा सकें। दरअसल युवा राष्ट्र निर्माण और छवि निर्माण दोनों में ही सबसे बड़े हितधारक हैं, इसलिए उनके उज्ज्वल भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने तथा देश और दुनिया को एक बड़ा कुशल कार्यबल प्रदान करने पर सरकार का फोकस है। युवाओं के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं में नेशनल अप्रेन्टसशिप प्रोमोशन स्कीम, युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने, नवविचार को प्रोमोट करने, देश में स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्टार्टअप इंडिया, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को नया कारोबार शुरू करने के लिए लोन उपलब्ध करवाने हेतु ह्यपीएम रोजगार योजना इत्यादि विभिन्न योजनाएं भी शामिल हैं।

संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक हिंसक संघर्ष शिक्षा और स्थिरता को बाधित करते हैं, ऑनलाइन वातावरण में नकारात्मकता को बढ़ावा देने वाला ध्रुवीकृत वातावरण और लगातार आर्थिक असमानता अवसरों को सीमित करती है। ये मुद्दे न केवल व्यक्तिगत भविष्य बल्कि समाज की समग्र स्थिरता को भी खतरे में डालते हैं। शांति की संस्कृति को बढ़ावा देने, जिम्मेदार वैश्विक नागरिकों का पोषण करने और सभी के लिए अधिक न्यायपूर्ण, समावेशी और टिकाऊ भविष्य बनाने के लिए सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को आवश्यक कौशल से लैस करना महत्वपूर्ण है। विश्व युवा कौशल दिवस युवाओं की क्षमता को पहचानने, उन्हें चुनौतियों का सामना करने तथा शांतिपूर्ण, समृद्ध और टिकाऊ भविष्य में योगदान देने के लिए कौशल और अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता पर जोर देता है। दरअसल तीव्र गति से विकसित होती प्रौद्योगिकी और नौकरी बाजार की निरंतर विकसित होती प्रकृति को देखते हुए युवाओं को अनुकूलनीय और बहुमुखी कौशल सैट के साथ सशक्त बनाना बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतारेस का कहना है कि न केवल आज बल्कि हर दिन शिक्षा को बदलने के लिए काम करते हुए यह सुनिश्चित करने के भी प्रयास होने चाहिएं कि युवाओं के पास वह सब कुछ हो, जो उनके लिए अधिक शांतिपूर्ण, टिकाऊ भविष्य को आकार देने और उनके कौशल को विकसित करने के लिए आवश्यक है। अब चूंकि विभिन्न उद्योगों में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस तकनीकों का तेजी से उपयोग कार्य के परिदृश्य को बदल रहा है, इसलिए भविष्य की नौकरियों के लिए युवाओं को तैयार करने हेतु उन्हें आवश्यक एआई कौशल से लैस करना बेहद महत्वपूर्ण हो गया है।

योगेश कुमार गोयल
(लेखक 36 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय वरिष्ठ पत्रकार और सागर से अंतरिक्ष तकः भारत की रक्षा क्रांति पुस्तक के लेखक हैं)

अमेरिका-ईरान टकराव और विश्व शांति की नई चुनौती

अमेरिका और ईरान के बीच लंबे तनाव के बाद बड़ी कठिनाई से बना संघर्ष विराम अपनी निर्धारित अवधि पूरी करने से पहले ही टूटने की कगार पर पहुंच गया है। ईरान द्वारा अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर किए गए ताजा हमलों और उसके जवाब में अमेरिका की भीषण बमबारी ने एक बार फिर पूरी दुनिया को युद्ध की आशंकाओं के बीच खड़ा कर दिया है। यह केवल दो देशों के बीच का सैन्य संघर्ष नहीं है, बल्कि वैश्विक शांति, आर्थिक स्थिरता और मानवीय मूल्यों के लिए गंभीर चुनौती है।

जिस समय विश्व को महामारी, आर्थिक मंदी, जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा संकट जैसी समस्याओं से मिलकर लड़ना चाहिए, उस समय महाशक्तियों का युद्धोन्माद पूरी मानवता को पीछे धकेलने का कार्य कर रहा है। होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर उत्पन्न विवाद ने इस संघर्ष को और अधिक विस्फोटक बना दिया है। विश्व के लगभग 20 प्रतिशत कच्चे तेल की आपूर्ति इसी समुद्री मार्ग से होती है। यदि यह मार्ग बाधित होता है तो केवल तेल की कीमतें ही नहीं बढ़ेंगी, बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका व्यापक दुष्प्रभाव पड़ेगा। महंगाई बढ़ेगी, उत्पादन लागत में वृद्धि होगी, आपूर्ति शृंखलाएं टूटेंगी और विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था सबसे अधिक प्रभावित होगी। युद्ध की आग कभी सीमाओं में नहीं रहती, उसकी तपिश अंतत: पूरी दुनिया को झुलसाती है।

इस संघर्ष का सबसे दुखद पक्ष यह है कि इसमें निर्दोष नागरिकों, नाविकों और आम जनजीवन को सबसे अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। हाल के घटनाक्रम में भारतीय नाविकों के प्रभावित होने और भारत के सहयोग से विकसित रणनीतिक महत्व वाले चाबहार बंदरगाह परियोजना को नुकसान पहुंचने से यह स्पष्ट हो गया है कि युद्ध किसी एक देश तक सीमित नहीं रहता। अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक विश्वास-तीनों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अमेरिका स्वयं को लोकतंत्र और विश्व व्यवस्था का संरक्षक बताता है, लेकिन उसकी विदेश नीति लंबे समय से प्रतिबंधों, सैन्य दबाव और शक्ति प्रदर्शन पर आधारित रही है। किसी भी राष्ट्र को झुकाने के लिए आर्थिक प्रतिबंध, सैन्य हमले और राजनीतिक दबाव स्थायी समाधान नहीं हो सकते। महाशक्ति होने का अर्थ केवल सैन्य सामर्थ्य नहीं, बल्कि संयम, दूरदृष्टि और विश्व समुदाय के प्रति नैतिक उत्तरदायित्व भी है। यदि शक्ति विवेक से संचालित न हो तो वही शक्ति विनाश का कारण बन जाती है।

दूसरी ओर ईरान को भी यह समझना होगा कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों को अपने रणनीतिक हितों के लिए बंधक बनाना न तो अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप है और न ही वैश्विक विश्वास के अनुकूल। किसी भी देश की सुरक्षा तब तक स्थायी नहीं हो सकती जब तक वह पड़ोसी देशों और विश्व समुदाय के साथ सहयोग, विश्वास और पारदर्शिता का वातावरण निर्मित न करे। भय और प्रतिशोध पर आधारित सुरक्षा व्यवस्था अंतत: स्वयं को ही असुरक्षित बना देती है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कार्यशैली ने इस पूरे संकट को और अधिक अनिश्चित बनाया है। एक ओर वे कठोर सैन्य कार्रवाई करते हैं, दूसरी ओर वार्ता और समझौते की बातें करते हैं। इस प्रकार के विरोधाभासी संदेश न केवल कूटनीतिक विश्वास को कमजोर करते हैं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी अस्थिरता पैदा करते हैं। महाशक्तियों के नेताओं के प्रत्येक वक्तव्य का प्रभाव केवल उनके देशों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि विश्व की अर्थव्यवस्था, निवेश, ऊर्जा बाजार और करोड़ों लोगों के जीवन पर पड़ता है। इसलिए नेतृत्व में धैर्य, स्थिरता और विश्वसनीयता अत्यंत आवश्यक है।

इतिहास गवाह है कि युद्धों ने कभी स्थायी समाधान नहीं दिया। प्रथम और द्वितीय विश्वयुद्ध से लेकर इराक, अफगानिस्तान, लीबिया और सीरिया तक, हर युद्ध ने नई समस्याएं ही पैदा की हैं। लाखों लोगों की जान गई, करोड़ों लोग विस्थापित हुए, लेकिन अंतत: समाधान फिर बातचीत की मेज पर ही खोजे गए। यदि अंत में संवाद ही करना है, तो शुरूआत भी संवाद से ही क्यों नहीं हो सकती? यही प्रश्न आज पूरी मानवता के सामने खड़ा है। भारत ने सदैव विश्व को शांति, सह-अस्तित्व और अहिंसा का मार्ग दिखाया है। गौतम बुद्ध, भगवान महावीर और महात्मा गांधी की भूमि ने यह सिखाया कि वास्तविक विजय शत्रु को पराजित करने में नहीं, बल्कि शत्रुता को समाप्त करने में है। भारत की विदेश नीति भी ह्यवसुधैव कुटुम्बकम्ह्न और ह्यविश्वबंधुत्वह्न के आदर्शों पर आधारित रही है। भारत ने हमेशा संवाद, कूटनीति और शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन किया है। यही कारण है कि भारत आज विश्वसनीय मध्यस्थ, संतुलित शक्ति और जिम्मेदार वैश्विक भागीदार के रूप में सम्मान प्राप्त कर रहा है।

वर्तमान संकट में भारत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकती है। भारत के अमेरिका, ईरान और खाड़ी देशों के साथ संतुलित संबंध हैं। भारत यदि संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों के माध्यम से सक्रिय शांति पहल करे, तो तनाव कम करने में उसकी भूमिका प्रभावी सिद्ध हो सकती है। साथ ही भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री व्यापार और विदेशों में कार्यरत भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए भी दूरदर्शी रणनीति अपनानी होगी। आज आवश्यकता किसी एक पक्ष की विजय की नहीं, बल्कि मानवता की विजय की है। हथियारों की होड़ से न तो समृद्धि आती है और न ही सम्मान। वास्तविक शक्ति मिसाइलों, बमों और युद्धपोतों में नहीं, बल्कि विश्वास, सहयोग और संवाद में निहित होती है। युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, वह केवल नई समस्याओं को जन्म देता है। अहिंसा कायरता नहीं, बल्कि आत्मबल, धैर्य और दूरदर्शिता का सर्वोच्च स्वरूप है।

विश्व समुदाय को अब यह स्पष्ट संदेश देना होगा कि किसी भी देश की मनमानी, सामरिक अहंकार और युद्धोन्माद को स्वीकार नहीं किया जा सकता। संयुक्त राष्ट्र सहित वैश्विक संस्थाओं को अधिक प्रभावी, निष्पक्ष और सक्रिय भूमिका निभानी होगी। यदि आज भी दुनिया ने युद्ध की राजनीति पर अंकुश नहीं लगाया, तो भविष्य की पीढ़ियां हमें क्षमा नहीं करेंगी। आज पूरी दुनिया की प्रार्थना यही है कि अमेरिका को शक्ति के साथ सद्बुद्धि मिले, ईरान को संयम और विवेक का मार्ग मिले तथा दोनों राष्ट्र हथियारों की भाषा छोड़कर संवाद की संस्कृति अपनाएं। शांति ही विकास का आधार है, संवाद ही स्थायी समाधान का मार्ग है और अहिंसा ही मानव सभ्यता का सबसे बड़ा अस्त्र है। यही समय की पुकार है, यही मानवता की अपेक्षा है और यही भविष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता भी।

(लेखक - ललित गर्ग)
(लेखक, पत्रकार एवं स्तंभकार)
(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

आलेख

मीलार्ड! कौन है इस अमर्यादित व्यवहार का जिम्मेदार?

यदि कोई देश की सर्वोच्च अदालत में दो शीर्ष न्यायाधीशों की उपस्थिति में सीजेआई के लिए अत्यंत आपत्तिजनक गाली देकर फाइल फेंक दे तो इस व्यवहार को क्या कहेंगे? क्या यह आम जन का न्याय व्यवस्था के प्रति आक्रोश माना जा सकता है? देश की सर्वोच्च अदालत केवल एक न्यायिक संस्था नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र के उस स्तंभ का प्रतीक है, जहां अंतिम उम्मीद लेकर आम नागरिक पहुंचता है। ऐसे में यदि उसी अदालत के भीतर ऐसी घटना घटे जिसमें एक वकील न्यायालय की कार्यवाही के दौरान मुख्य न्यायाधीश के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग करे, न्यायालय की गरिमा को चुनौती दे और गुस्से में फाइल फेंक दे, तो यह किसी एक व्यक्ति का अनुचित व्यवहार भर नहीं रह जाता, बल्कि न्याय व्यवस्था की मयार्दा और लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति समाज के बदलते दृष्टिकोण पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय में हुई घटना ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार संबंधित याचिकाकर्ता वकील ने न्यायालय में अभद्र व्यवहार किया, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के लिए अत्यंत आपत्तिजनक अपशब्द कहे और अदालत की कार्यवाही बाधित कर दी। उस समय मुख्य न्यायाधीश स्वयं न्यायालय कक्ष में उपस्थित नहीं थे तथा न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ कार्यवाही कर रही थी। स्थिति बिगड़ते ही सुरक्षा कर्मियों ने तत्काल हस्तक्षेप कर दुर्व्यवहारी को न्यायालय कक्ष से बाहर निकाला और बाद में दिल्ली पुलिस उसे पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अदालत इस पूरे घटनाक्रम को अत्यंत गंभीरता से देख रही है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान संरक्षक, नागरिक अधिकारों का रखवाला और लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्याय की अंतिम उम्मीद है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के भीतर होने वाला प्रत्येक व्यवहार केवल व्यक्तिगत आचरण का मामला नहीं रहता, बल्कि वह न्यायपालिका की प्रतिष्ठा ,बार अधिवक्ता समुदाय की जिम्मेदारी और कानून के शासन से जुड़ा प्रश्न बन जाता है। जब निचली अदालतों और अन्य संस्थाओं से राहत नहीं मिलती, तब व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट की ओर आशा से देखता है। इसलिए सर्वोच्च अदालत के प्रत्येक शब्द, आदेश, परंपरा और व्यवहार का संबंध केवल एक मुकदमे से नहीं, बल्कि देश की लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था की प्रतिष्ठा से होता है। ऐसे में अदालत कक्ष के भीतर अभद्रता, आक्रामकता और अनुशासनहीनता की कोई भी घटना गंभीर चिंता का विषय है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जो कुछ हुआ, वह न्यायालय की गरिमा के बेहद खिलाफ है । जस्टिस के. वी. विश्वनाथन और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ के समक्ष प्रबल प्रताप नाम का एक याचिकाकर्ता स्वयं अपने मामले की पैरवी कर रहा था। सुनवाई के दौरान उसने न्यायाधीशों को ही आदेश देने का प्रयास किया, मामले की फाइल और कागज हवा में फेंक दिए तथा अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। स्थिति असहनीय हो गई और सुरक्षाकर्मियों को हस्तक्षेप करते हुए उसे अदालत कक्ष से बाहर ले जाना पड़ा। याचिकाकर्ता इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश से असंतुष्ट था। उसकी शिकायत थी कि पुलिस जांच से संबंधित उसकी अर्जी को हाईकोर्ट ने निजी शिकायत के रूप में देखने का निर्देश दिया था। किसी न्यायिक आदेश से असहमति होना असामान्य नहीं है। प्रत्येक नागरिक को कानून द्वारा उपलब्ध उपायों का इस्तेमाल करते हुए आदेश को चुनौती देने का अधिकार है, लेकिन कानूनी अधिकार और अदालत में दुर्व्यवहार करने की छूट दो अलग-अलग बातें हैं। हैं। किसी व्यक्ति को न्याय की मांग करने का पूरा अधिकार है, परंतु वह न्यायाधीशों को निर्देश देने, धमकाने, अपमानित करने या अदालत की कार्यवाही बाधित करने का अधिकार नहीं देता। इस घटना में सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने उल्लेखनीय संयम दिखाया है। न्यायाधीशों ने याचिकाकर्ता की मानसिक स्थिति और हताशा को देखते हुए उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्णय लिया। अदालत ने कहा कि उसे उस व्यक्ति के प्रति सहानुभूति है और उसके व्यवहार को उसकी परेशानी और निराशा के परिणाम के रूप में देखा जाना चाहिए। याचिका को गुण-दोष के आधार पर खारिज कर दिया गया, लेकिन उसके अपमानजनक व्यवहार पर अलग से दंड नहीं दिया गया। अदालत का यह रुख न्यायिक उदारता और मानवीय संवेदनशीलता का उदाहरण अवश्य है, लेकिन इसके साथ एक बड़ा प्रश्न भी जुड़ा हुआ है। क्या ऐसी घटनाओं को केवल हताशा का परिणाम मानकर छोड़ देना भविष्य में गलत संदेश दे सकता है? सहानुभूति आवश्यक है, लेकिन न्यायालय का अनुशासन बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। यदि अदालत में फाइल फेंकने, अपशब्द कहने और न्यायाधीशों को आदेश देने जैसी घटनाएं बिना किसी संस्थागत प्रतिक्रिया के समाप्त हो जाएं, तो इससे अदालत की मयार्दा कमजोर होने का खतरा पैदा हो सकता है। विशेष रूप से तब, जब ऐसा व्यवहार करने वाला व्यक्ति विधि व्यवसाय से जुड़ा हो। वकील केवल अपने मुवक्किल का प्रतिनिधि नहीं होता, बल्कि वह न्याय व्यवस्था का एक अधिकारी भी माना जाता है। उससे अपेक्षा होती है कि वह कानून, न्यायालय और पेशेवर आचार संहिता का सम्मान करेगा। उसे अपने पक्ष को दृढ़ता से रखने का अधिकार है, लेकिन भाषा, व्यवहार और तर्क की संवैधानिक सीमा के भीतर। आवेश, अपमान और धमकी को कानूनी बहस का विकल्प नहीं बनाया जा सकता।

आपको बता दें एडवोकेट्स एक्ट, 1961 के अंतर्गत बार काउंसिल को वकीलों के पेशेवर आचरण की जांच करने और अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार है। यदि प्रारंभिक जांच में कदाचार का मामला बनता है, तो संबंधित वकील को चेतावनी देने से लेकर एक निश्चित अवधि के लिए उसकी वकालत पर रोक लगाने अथवा गंभीर मामलों में उसका नाम अधिवक्ताओं की सूची से हटाने तक की कार्रवाई की जा सकती है। अब यह जिम्मेदारी संबंधित बार कार्डोसल की है कि वह पूरे घटनाक्रम का निष्पक्ष परीक्षण करे।

ध्यान रहे ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के भीतर इस प्रकार की घटना पहली बार हुई है। फरवरी 1999 में वकील नंद लाल बलवानी ने तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ए. एस. आनंद की अध्यक्षता वाली पीठ की ओर जूता फेंका था। अदालत ने इसे घोर आपराधिक अवमानना मानते हुए उन्हें चार महीने की साधारण कैद और जुमार्ने की सजा सुनाई थी। बाद में उनके खिलाफ पेशेवर अनुशासन की कार्रवाई भी हुई। उस समय अदालत ने स्पष्ट संदेश दिया था कि न्यायिक निर्णयों से असहमति का अर्थ अदालत की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं है। अक्टूबर 2025 में भी तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अदालत में एक वकील ने नारेबाजी करते हुए उनकी ओर जूता उछालने का प्रयास किया था। उस समय भी न्यायमूर्ति गवई ने व्यक्तिगत उदारता दिखाते हुए घटना को अधिक महत्व नहीं दिया। न्यायाधीशों का यह संयम सराहनीय हो सकता है, लेकिन बार-बार होने वाली ऐसी घटनाएं न्यायालयों की सुरक्षा, प्रवेश व्यवस्था, पेशेवर मानसिक स्वास्थ्य और अनुशासनात्मक तंत्र पर पुनर्विचार की आवश्यकता बताती हैं। अदालत की अवमानना से संबंधित कानून का उद्देश्य न्यायाधीशों को व्यक्तिगत आलोचना से बचाना नहीं, बल्कि न्याय की प्रक्रिया को निर्बाध बनाए रखना है। न्यायिक निर्णयों की आलोचना लोकतंत्र में पूरी तरह स्वीकार्य है। कठोर से कठोर कानूनी आलोचना भी की जा सकती है, बशर्ते वह तथ्य, तर्क और मर्यादित भाषा पर आधारित हो। लेकिन अदालत को भयभीत करने, कार्यवाही रोकने या न्यायाधीशों को अपमानित करने वाला व्यवहार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में नहीं आ सकता। शुक्रवार की घटना ने एक बारु फिर चेतावनी दी है कि न्यायपालिका का सम्मान केवल भाषणों और औपचारिक अवसरों तक सीमित नहीं रह सकता। उसका वास्तविक सम्मान अदालत कक्ष में हमारे व्यवहार, भाषा और कानून के प्रति आस्था से प्रकट होता है।

मानते हैं कि सर्वोच्च अदालत देश के संविधान और लोकतांत्रिक गरिमा का प्रतीक है। नागरिक अधिकारों की रक्षा करना अंतत: न्याय व्यवस्था में जनता के विश्वास की रक्षा करना है।अन्यथा देश की अदालतें मछली बाजार बन जाएंगी। ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो रही है? क्या इसके लिए स्वयं न्याय व्यवस्था जिम्मेदार नहीं है जिसमें एक आम आदमी को न्याय मिलना एक पूरा जीवन की आयु खपाना पड़ता है। आज भी देश की अदालतें मुकदमों के भार से दबी हुई है? और कहीं न कहीं राजनीतिक सत्ता से तालमेल कर चल रही है? वरना क्या वजह है कि गंभीर और संगीन अपराध का सजा याफ्ता गुरमीत राम रहीम आए दिन पैरोल पर बाहर घूमता है जबकि सौ दो सौ या हजार रुपए जुमार्ना नही भरने के लिए हजारों कैदी जेल मे बंद पड़ा है। अस्सी साल का आशाराम पैरोल और जमानत नहीं पाता है। जब बीस साल अदालत की चौखट पर चक्कर काटने के बाद भी एक दर्जन से अधिक नाबालिग बच्चों की हत्या के जघन्य मामले निठारी कांड के आरोपियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया जाता है जज साहब के आवास पर बोरों में भरी करोड़ों की करेंसी जल जाती है लेकिन कोई सटीक कारवाई नहीं की जाती। ऐसे में आक्रोश की परिणिति इस तरह होना अस्वाभाविक नहीं है? यह आम आदमी की हताशा की चिंगारी है इसे समय रहते समझने की जरूरत है।

लेखक - मनोज कुमार अग्रवाल
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं पिछले 39 वर्ष से लेखन और पत्रकारिता से जुड़े हैं) (यह लेखक के व्यक्तिगतविचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

संक्षिप्त वार्ता

सीमापुरी में पर्याप्त पेयजल आपूर्ति की मांग, आंदोलन की चेतावनी

नई दिल्ली, 15 जुलाई (वेब वार्ता)। सीमापुरी के विधायक वीर सिंह धिंगान ने विधानसभा क्षेत्र में पिछले कई महीनों से पेयजल की कमी का आरोप लगाते हुए दिल्ली सरकार से पर्याप्त जलापूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पानी की कमी से क्षेत्र के लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है।

वीर सिंह धिंगान ने आरोप लगाया कि पिछले 8-9 महीनों से सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र में लगातार अघोषित जल कटौती की जा रही है, जिससे लोगों को पीने के पानी के लिए भटकना पड़ रहा है।उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह से क्षेत्र में जल्द पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराने का आग्रह किया।

दिल्ली के आजादपुर में लगेगी अटल जी की 15 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा

नई दिल्ली, 15 जुलाई (वेब वार्ता)। दिल्ली सरकार पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आजादपुर में 15 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करेगी। दिल्ली कैबिनेट ने इस आशय के प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी दी।

दिल्ली के गृहमंत्री आशीष सूद ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पोस्ट में कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी केवल एक महान राजनेता ही नहीं, बल्कि दूरदर्शी नेतृत्व, सुशासन और राष्ट्रहित की राजनीति के प्रतीक थे। उनके विचार और जीवन आज भी करोड़ों देशवासियों को देशसेवा के लिए प्रेरित करते हैं। दिल्ली सरकार द्वारा आजादपुर में अटल जी की 15 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय उनके प्रति श्रद्धांजलि है। यह स्मारक आने वाली पीढ़ियों को उनके आदर्शों और राष्ट्र के प्रति समर्पण की याद दिलाता रहेगा।

डीयू के कई कॉलेजों में ईसीए ट्रायल आज से

नई दिल्ली, 15 जुलाई (वेब वार्ता)। दिल्ली विश्वविद्यालय में ईसीए के तहत दाखिला लेने वाले छात्र छात्राओं के ट्रायल की तिथियां घोषित कर दी गई हैं। डीयू द्वारा जारी तिथियों के अनुसार गुरुवार को रामजस कॉलेज में डिबेट, माता सुंदरी कॉलेज में म्यूजिक वोकल, मिरांडा हाउस में थिएटर,भारती कॉलेज में इंडियन क्लासिक डांस सहित अनय कॉलेजों में ईसीए ट्रायल की विस्तृत जानकारी डीयू ने अपनी दाखिला वेबसाइट पर साझा की है इस बारे में अधिक जानकारी अभ्यर्थी डीयू की दाखिला वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।

धर्मेंद्र प्रधान पर जनमत संग्रह, शिक्षा मंत्री पद पर बने रहने को लेकर मांगी राय

नई दिल्ली, 15 जुलाई (वेब वार्ता)। क्रांतिकारी युवा संगठन ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पद पर बने रहने के मुद्दे पर बुधवार को जनमत संग्रह आयोजित किया। संगठन ने लोगों से अपील की कि वे धर्मेंद्र प्रधान के विरुद्ध जारी आरोप-पत्र का अध्ययन करने के बाद अपने मत का प्रयोग करें।

संगठन के अनुसार आरोप-पत्र में प्रश्नपत्र लीक की घटनाओं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन, कथित घोटालों तथा शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित करने जैसे आरोप शामिल किए गए हैं। इसी आधार पर लोगों से यह राय मांगी जा रही है कि धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री के पद पर बने रहना चाहिए या नहीं। केवाईएस ने बताया कि यह जनमत संग्रह जंतर-मंतर स्थित प्रदर्शन स्थल के साथ-साथ विभिन्न राज्यों में संगठन की इकाइयों के माध्यम से ऑनलाइन भी आयोजित किया जा रहा है। संगठन का दावा है कि अब तक प्राप्त अधिकांश प्रतिक्रियाएं शिक्षा मंत्री के पद पर धर्मेंद्र प्रधान के बने रहने के पक्ष में नहीं हैं। संगठन के दिल्ली राज्य समिति के सदस्य भीम कुमार ने बताया कि जनमत संग्रह गुरुवार शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। इसके बाद प्राप्त मतों के आधार पर परिणाम सार्वजनिक किए जाएंगे। संगठन ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर जनमत जानना और उसे सार्वजनिक करना है।

दिल्ली के कुछ हिस्सों में हुई हल्की बारिश, बादल छाए रहने की संभावना

नई दिल्ली, वेब वार्ता

राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में बुधवार तड़के हल्की बारिश हुई और मौसम विभाग ने दिनभर बादल छाए रहने का अनुमान जताया है।

सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 29.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.9 डिग्री अधिक है। मौसम केंद्र ने तड़के ढाई बजे से सुबह साढ़े पांच बजे के बीच बहुत मामूली बारिश भी दर्ज की। पालम में न्यूनतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस रहा जो एक दिन पहले की तुलना में 2.6 डिग्री कम है। लोधी रोड में न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि रिज और आयानगर में यह क्रमशः 26.4 डिग्री और 26.6 डिग्री सेल्सियस रहा।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के आंकड़ों के अनुसार, आयानगर और नजफगढ़ में मंगलवार रात साढ़े 11 बजे से बुधवार तड़के ढाई बजे के बीच एक मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। विभाग ने बताया कि दिनभर बादल छाए रहने की संभावना है। आईएमडी के एक अधिकारी ने कहा, दिनभर बादल छाए रहने के साथ बहुत हल्की बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 159 दर्ज किया गया जो मध्यम श्रेणी में आता है। सीपीसीबी के मानकों के अनुसार, एक्यूआई को शून्य से 50 के बीच अच्छा, 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बहुत खराब और 401 से 500 के बीच गंभीर श्रेणी में माना जाता है।

नगर निगम चुनाव में भाजपा का दबदबा

आम आदमी पार्टी को दोहरा झटका

नई दिल्ली, वेब वार्ता

राजधानी की नगर निगम राजनीति में बुधवार को भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी बढ़त हासिल करते हुए आम आदमी पार्टी को दोहरा झटका दिया। एक ओर विभिन्न क्षेत्रीय समितियों के चुनाव में भाजपा ने अधिकांश क्षेत्रों में जीत दर्ज की, वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के पार्षद विकास टांक ने पार्टी छोड़कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। इसे नगर निगम की राजनीति में आम आदमी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक झटका माना जा रहा है। दिल्ली नगर निगम के विभिन्न क्षेत्रीय समितियों तथा कुछ क्षेत्रों में स्थायी समिति सदस्यों के चुनाव बुधवार को संपन्न हुए। उपलब्ध परिणामों के अनुसार, कुल 10 क्षेत्रों के नतीजे घोषित किए गए, जिनमें से 8 क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने विजय प्राप्त की, जबकि 2 क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी को सफलता मिली।

इसी दिन आम आदमी पार्टी के पार्षद एवं नगर निगम के सीटी क्षेत्र के अध्यक्ष विकास टांक ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। दिल्ली भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा तथा सांसद प्रवीण खंडेलवाल की उपस्थिति में उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। भाजपा ने इसे वाल्मीकि समाज के एक युवा नेतृत्व का समर्थन बताते हुए अपने संगठन के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। चुनाव परिणामों में केशवपुरम क्षेत्र में भाजपा के उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए। यहां अध्यक्ष पद पर विनीत वोहरा, उपाध्यक्ष पद पर मीनू गोयल तथा स्थायी समिति सदस्य के रूप में सुशील निर्वाचित हुए।

मध्य क्षेत्र में भी भाजपा ने निर्विरोध जीत दर्ज की। अध्यक्ष पद पर नीतू निर्वाचित हुईं। आम आदमी पार्टी के राकेश लोहिया ने अध्यक्ष पद से अपना नामांकन वापस ले लिया था, जबकि उपाध्यक्ष और स्थायी समिति सदस्य पदों पर आम आदमी पार्टी ने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा। परिणामस्वरूप उपाध्यक्ष पद पर प्रवीण कुमार तथा स्थायी समिति सदस्य के रूप में होमचंद गोयल निर्वाचित हुए। उल्लेखनीय है कि होमचंद गोयल पहले इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी से जुड़े थे और बाद में भाजपा में शामिल हुए थे।

शाहदरा उत्तरी क्षेत्र में भी भाजपा ने जीत हासिल की। अध्यक्ष पद के लिए पंकज लूथरा तथा उपाध्यक्ष पद के लिए ब्रजेश सिंह को कुल 35 में से 20 मत प्राप्त हुए। आम आदमी पार्टी की प्रियंका शर्मा और रोशन लाल को 12 मत मिले। इस क्षेत्र में कुल 32 मत डाले गए। इसके अतिरिक्त दक्षिण, नरेला, शाहदरा दक्षिण, नजफगढ़ तथा सिविल लाइंस क्षेत्रों में भी भाजपा ने जीत दर्ज की। वहीं करोलबाग क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए, जबकि रोहिणी क्षेत्र में भी पार्टी ने विजय हासिल की। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि क्षेत्रीय समिति चुनावों में भाजपा की बढ़त और आम आदमी पार्टी के एक पार्षद का दल बदलना नगर निगम की आगामी राजनीतिक दिशा को प्रभावित कर सकता है। इन घटनाक्रमों से राजधानी की स्थानीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति और अधिक मजबूत होती दिखाई दे रही है।

एमसीडी स्थायी समिति के सदस्यों, वार्ड समिति के प्रमुखों के चुनाव के लिए तैयार

नई दिल्ली, 15 जुलाई (वेब वार्ता)। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की स्थायी समिति के चुनाव बुधवार को होंगे जो लंबे समय से रुके हुए थे। उम्मीद है कि चुनाव के नतीजों से निकाय की निर्णय लेने वाली सर्वोच्च समिति का कामकाज फिर से शुरू हो सकेगा और कई लंबित परियोजनाओं को मंजूरी मिलने की प्रक्रिया में तेजी आएगी।

एमसीडी की 12 वार्ड समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों के लिए भी मतदान होगा। यह चुनाव सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और विपक्षी आम आदमी पार्टी (आप) के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गया है। परिणाम दिन में बाद में घोषित किए जाने की उम्मीद है। स्थायी समिति 18 सदस्यों वाली एक समिति है जो पांच करोड़ रुपये से अधिक के वित्तीय फैसलों, ठेकों, नीतिगत मामलों और नगर निगम की परियोजनाओं को मंजूरी देती है। छह खाली सीट पर चुनाव लंबित रहने के कारण मार्च से यह समिति केवल 12 सदस्यों के साथ काम कर रही है।

चुनाव मूल रूप से तीन जून को होने थे लेकिन इन्हें टाल दिया गया था और बाद में इसे पुनर्निर्धारित कर चुनाव के लिए 15 जुलाई की तारीख तय की गई। यह मुकाबला ऐसे समय में हो रहा है जब आप से अलग हुए गुट इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी (आईवीपी) के सभी 16 पार्षदों के भाजपा में शामिल होने से 250 सदस्यों वाले सदन में भाजपा की स्थिति मजबूत हो गई है। अब भाजपा के पास 139 पार्षद हैं, जबकि आप की संख्या घटकर 102 रह गई है।

संख्या में बदलाव के बाद स्थायी समिति के चुनाव में भाजपा का पलड़ा भारी माना जा रहा है लेकिन कई वार्ड समिति के मुकाबलों में कड़ी टक्कर होने की उम्मीद है। स्थायी समिति की छह सीट के लिए नरेला में भाजपा के पवन कुमार का मुकाबला आप की रितु मुकेश कुमार से है, जबकि पश्चिमी क्षेत्र में भाजपा के शशि यादव का सामना आप के सुदेश कुमार से होगा। शाहदरा दक्षिण में भाजपा की मुनेश का मुकाबला आप की बीना से है।

शेष तीन सीट पर आप ने करोल बाग से राजन अरोड़ा को मैदान में उतारा है जबकि भाजपा ने केशव पुरम से सुशील और मध्य जोन से हेम चंद गोयल को नामांकित किया है। भाजपा के पास 12 वार्ड समितियों में से आठ में स्पष्ट बहुमत है जबकि आप चार में आगे है। हालांकि कुछ समितियों में खासकर सिटी एसपी, रोहिणी, मध्य और दक्षिण जोन में नतीजा कांग्रेस पार्षदों के वोट पर निर्भर कर सकता है। एमसीडी में कांग्रेस के सिर्फ नौ पार्षद हैं लेकिन उन समितियों में उनके वोट अहम साबित हो सकते हैं जहां जीत-हार का अंतर कम रहने की उम्मीद है। कांग्रेस के वार्ड पार्षदों ने कहा कि पार्टी एक संगठन के तौर पर इस मुकाबले से दूर रहेगी। जाकिर नगर की पार्षद नाजिया दानिश ने पीटीआई-भाषा से कहा, ह्यहमारे पास जोन में जरूरी संख्या नहीं है। हमारा किसी भी पक्ष का समर्थन करने का कोई इरादा नहीं है। अगर कोई पार्षद वोट देता है, तो यह उसका अपना फैसला होगा।

रिश्वत मामले में इंस्पेक्टर की जमानत याचिका खारिज

नई दिल्ली, 15 जुलाई (वेब वार्ता)। फर्जी दवाइयों के मामले में जांच प्रभावित करने के लिए तीन करोड़ रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार सिंह को राहत नहीं मिली है। राउज एवेन्यू स्थित सीबीआई अदालत ने उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश सुशांत चंगोत्रा की अदालत ने मामले की गंभीरता और जांच के शुरूआती चरण को देखते हुए जमानत देने से इनकार किया। गिरफ्तारी के समय प्रदीप कुमार सिंह दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच में तैनात थे। मामले में सीबीआई ने आईपीएस अधिकारी दीपक गहलावत को भी गिरफ्तार किया है। सीबीआई के मुताबिक, फर्जी दवाइयों से जुड़े मामले में एक व्यक्ति को राहत दिलाने के बदले आरोपियों ने तीन करोड़ रुपये की मांग की थी।

शंकराचार्य ने सोनम वांगचुक से अनशन समाप्त करने की अपील की, जनजागरण अभियान का दिया सुझाव

नई दिल्ली, वेब वार्ता

जंतर-मंतर पर 28 जून से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक की लगातार बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति को लेकर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने चिंता व्यक्त की है। उन्होंने केंद्र सरकार से तत्काल हस्तक्षेप कर उचित निर्णय लेने की अपील की है। साथ ही सोनम वांगचुक से अनशन समाप्त कर जनजागरण के माध्यम से अपनी बात देशभर तक पहुंचाने का आग्रह किया।

वीडियो संदेश जारी करते हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि यदि अनशन के कारण सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य को कोई शारीरिक या मानसिक क्षति पहुंचती है तो उसकी भरपाई संभव नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सरकार को इस विषय में तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए और आवश्यक होने पर उन्हें चिकित्सकीय देखरेख में भी लिया जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी सज्जन व्यक्ति को इस प्रकार धीरे-धीरे कष्ट झेलते देखना उचित नहीं है। शंकराचार्य ने सोनम वांगचुक से भावनात्मक अपील करते हुए कहा कि केवल अनशन से उनकी मांगों का समाधान संभव नहीं दिखता।

उन्होंने कहा कि उनकी मांगें उचित हैं और वे स्वयं उनके समर्थन में हैं, लेकिन संघर्ष के इस तरीके से सहमत नहीं हैं। उनका कहना था कि उन्होंने भी पूर्व में इस प्रकार के उपवास किए हैं, किंतु वर्तमान परिस्थितियों में इस माध्यम का अपेक्षित प्रभाव नहीं पड़ता।

2 साल में डीयू के 2 हजार से अधिक विद्यार्थियों ने सीखा साइंस ऑफ हैप्पीनेस

नई दिल्ली, वेब वार्ता। दिल्ली विश्वविद्यालय में दो वर्ष पूर्व शुरू किए गए साइंस ऑफ हैप्पीनेस कोर्स को अभी तक 2 हजार से अधिक विद्यार्थी अपना चुके हैं। इस मूल्य संवर्धन (वीएसी) कोर्स को डीयू के 17 कॉलेजों और एक विभाग द्वारा अपनाया गया है। बुधवार को डीयू कुलपति प्रो. योगेश सिंह की अध्यक्षता में इन सभी संस्थानों की एक बैठक आयोजित की गई जिसमें सभी प्रिंसिपलों और संबंधित अधिकारियों ने कोस को लेकर अपने अनुभव साझा किए। कुलपति ने कोर्स की सफलता पर खुशी जताते हुए कहा कि खुश रहना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है यह तभी संभव है, जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचें और अच्छा करें। कुलपति ने कहा, संसार एक बेहतरीन जगह है अच्छा करेंगे तो अच्छा ही होगा।

सभी प्रिंसिपलों की फीडबैक के बाद कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने कहा कि इस कोर्स के अच्छे परिणाम आ रहे हैं। पहले ऐसे कोर्सों को कोई नहीं जानता था, लेकिन अब

आधुनिक समाज में अनेकों तरह की चुनौतियां हैं। ऐसे में माइंड सेट को बदलने की जरूरत होती है। उसके लिए ऐसे कोर्सों की उपयोगिता बढ़ जाती है। कुलपति ने नशे को बड़ी चुनौती बताते हुए कहा कि इससे पूरे परिवार की खुशी चली जाती है। डीयू में ड्रग फ्री कैम्पस अभियान की शुरूआत उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन द्वारा की गई थी। हमें उसे भी गंभीरता से आगे बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए पटेल चेस्ट की भी मदद ली जा सकती है। बैठक के दौरान विभिन्न कॉलेजों के प्रिंसिपलों ने अपने-अपने अनुभव साझा किए। इस अवसर पर मिरांडा हाउस और दौलत राम कॉलेज की प्रिंसिपलों द्वारा बताया गया कि उनके कॉलेजों में माइंड लैब स्थापित किए गए हैं। इनसे स्टडी और रिसर्च में मदद मिलती है। कई अन्य कॉलेज भी ऐसे लैब स्थापित करने की योजना बना रहे हैं।

डीयू की डीन अकाडेमिक अफेयर्स प्रो. के. रत्नाबली ने बताया कि यह एक सेमेस्टर का कोर्स डिजाइन किया गया है जिसे पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे सेमेस्टर में प्रस्तुत किया जाता है। विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग में भी इस कोर्स को प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रो. रत्नाबली ने बताया कि अभी तक यह कोर्स अंडर ग्रेजुएट (यूजी) तक है, भविष्य में इसे पोस्ट ग्रेजुएट (पीजी) में स्किल बेस्ड कोर्स के पूल में मिलाने पर भी विचार किया जा रहा है।

'भारतीय लोक पार्टी' के गठन की घोषणा, सत्यनारायण यादव बने राष्ट्रीय अध्यक्ष

नई दिल्ली, 15 जुलाई (वेब वार्ता)। सामाजिक न्याय, आर्थिक सुधार और व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दों को लेकर केशव पुरम स्थित महाराणा प्रताप भवन में आयोजित बैठक में नई राजनीतिक पार्टी 'भारतीय लोक पार्टी' के गठन की घोषणा की गई। बैठक में विभिन्न राज्यों से आए कार्यकताओं और समर्थकों ने भाग लिया। बैठक को संबोधित करते हुए सत्यनारायण यादव ने कहा कि देश आर्थिक चुनौतियों, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता जैसी समस्याओं का सामना कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा व्यवस्था में सामाजिक न्याय और आर्थिक सुधार के उद्देश्यों की अनदेखी हो रही है। उन्होंने समाज के वंचित, किसान, युवा, छात्र तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों को लेकर जनजागरण अभियान चलाने की आवश्यकता बताई। बैठक में सर्वसम्मति से सत्यनारायण यादव को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, सतीश कुमार जैन को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष तथा नगीना प्रसाद (एन. जायसवाल) को राष्ट्रीय महासचिव चुना गया। इस अवसर पर सुरेन्द्र कुमार बहोत, बिजेंद्र मोहन यादव, अरविंद सिंह, रश्मि यादव, राम बहादुर यादव, मनोहर लाल मेघवाल, राहुल वर्मा, विनोद कुमार यादव, विजय यादव सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

सोशल मीडिया पर लगाए गए आरोपों पर दिल्ली पुलिस की सफाई, कहा- कानून के तहत हुई कार्रवाई

नई दिल्ली, 15 जुलाई (वेब वार्ता)। सोशल मीडिया पर थाना समयपुर बादली के पुलिसकर्मियों पर लगाए गए आरोपों को लेकर दिल्ली पुलिस ने अपना आधिकारिक पक्ष जारी किया है। पुलिस का कहना है कि उपलब्ध तथ्यों और जांच के आधार पर पुलिसकर्मियों के खिलाफ लगाए गए आरोप सही नहीं पाए गए हैं तथा पूरी कार्रवाई कानून के अनुरूप की गई।

दिल्ली पुलिस के अनुसार, मामला 10 जून 2026 को हुई मारपीट की एक घटना से संबंधित है। इस संबंध में थाना समयपुर बादली में मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान पुलिस ने सचिन, जीतू, भरत और चिंता देवी को आरोपी बनाया।

पुलिस ने बताया कि सभी आरोपियों ने अदालत में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था, लेकिन अदालत ने उनकी याचिकाएं खारिज कर दीं। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जीतू को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं और उनकी तलाश जारी है।

पुलिस के मुताबिक, सोशल मीडिया पर आरोप लगाने वाली महिला आरोपी सचिन और भरत की बहन है। पुलिस को सूचना मिली थी कि फरार आरोपी अपने घर में मौजूद हो सकते हैं। इसी सूचना के आधार पर पुलिस की एक टीम उनके घर पहुंची, लेकिन वहां कोई आरोपी नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35 की उपधारा (3) के तहत कानूनी नोटिस घर पर चस्पा कर दिया।

नहीं मिला ठोस साक्ष्य

दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर किसी भी पुलिसकर्मी द्वारा घर में जबरन प्रवेश करने की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस ने यह भी कहा कि गाली-गलौज करने, धमकी देने या अभद्र व्यवहार करने जैसे आरोप भी जांच में सही नहीं पाए गए हैं। पुलिस के अनुसार, इन आरोपों के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिला है।

उमर को हफ्ते में दो बार परिवार से वीडियो कॉल की अनुमति

नई दिल्ली, (वेब वार्ता)। कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगा मामले में आरोपी उमर खालिद को राहत देते हुए उन्हें सप्ताह में दो बार परिवार से वीडियो कॉल (ई-मुलाकात) की अनुमति दे दी है। इससे पहले उनकी यह सुविधा घटाकर एक बार कर दी गई थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी की अदालत ने कहा कि उमर पिछले छह वर्षों से सप्ताह में दो बार ई-मुलाकात की सुविधा ले रहे थे और इस दौरान उन्होंने जेल के किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया।

सुप्रीम कोर्ट में हंगामे के मामले में लॉ के दो छात्र गिरफ्तार

दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेजे गए

नई दिल्ली, वेब वार्ता। सुप्रीम कोर्ट में 10 जुलाई को हुई कथित अव्यवस्था और हंगामे के मामले में दिल्ली पुलिस ने लखनऊ यूनिवर्सिटी के लॉ के दो छात्रों को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में तिलक मार्ग थाना में सुप्रीम कोर्ट सुरक्षा स्टाफ के बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है।

पुलिस के अनुसार, यह घटना 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर-13 में एसएलपी संख्या 31367/2026 (प्रबल प्रताप एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, कमिश्नर के माध्यम से) की सुनवाई के दौरान हुई। आरोप है कि प्रबल प्रताप ने स्वयं याचिकाकर्ता के रूप में पेश होकर अदालत की कार्यवाही के दौरान जानबूझकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, उसने कोर्ट रूम के भीतर कागज फेंककर अव्यवस्था फैलाने की कोशिश की।

जानकारी के मुताबिक, जब सुप्रीम कोर्ट के सुरक्षा कर्मियों और स्टाफ ने उसे शांत रहने और अदालत की गरिमा बनाए रखने के लिए रोका, तो उसने ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी के साथ कथित तौर पर जबरदस्ती की, जिससे सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न हुई। इस घटना के बाद अदालत परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठे थे।

पुलिस ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद दोनों आरोपियों का इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज में मेडिकल परीक्षण कराया गया। मेडिकल रिपोर्ट में दोनों को तत्काल किसी मनोचिकित्सकीय उपचार की आवश्यकता नहीं बताई गई। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से आपत्तिजनक शब्दों वाले पर्चे (पैम्फलेट) भी बरामद किए हैं।

दिल्ली पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान लॉ के तीसरे वर्ष के छात्र प्रबल प्रताप सिंह (24) और दूसरे वर्ष के छात्र चंद्र भान (23) के रूप में हुई है। पुलिस अब उनसे पूछताछ कर मामले के विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि घटना से जुड़े सभी तथ्यों और संभावित कारणों की विस्तृत जांच जारी है तथा मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

दिल्ली पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाई, 500 सीसीटीवी खंगालने के बाद दो हत्यारोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली, वेब वार्ता

द्वारका डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ और द्वारका नॉर्थ पुलिस स्टेशन की संयुक्त टीम ने द्वारका नॉर्थ पुलिस थाना क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल, 12 जुलाई को द्वारका के सेक्टर-18ए में कारगिल चौक के पास वाली सड़क और नाले के बीच घास में एक अज्ञात व्यक्ति के शव से मिलने की सूचना पुलिस को मिली थी। जब पुलिस टीम ने मौके पर पहुंची, तो पाया कि आदमी का शव पड़ा था। शव की उम्र करीब 35 साल थी, उस पर टैटू बने हुए थे और सिर पर चोट का निशान था। शव के पास से पहचानने का कोई साक्ष्य नहीं मिला।

हालातों को देखते हुए दिल्ली के द्वारका नॉर्थ पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई। इसके बाद डीसीपी कुशलपाल सिंह के निर्देशों पर द्वारका जिले के स्पेशल स्टाफ और द्वारका नॉर्थ पुलिस की खास टीमों को दोषियों का पता लगाने और उन्हें पकड़ने के लिए तैनात किया गया। दोनों टीमों ने घटनास्थल का दौरा किया और घटना वाली जगह के साथ-साथ आस-पास के रास्तों के लगभग 500 सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया। द्वारका नॉर्थ पुलिस ने सभी उपलब्ध कानूनी तरीकों से पहचान की प्रक्रिया शुरू करके तुरंत कार्रवाई की। इस दौरान मृतक की पहचान दिल्ली के नजफगढ़ निवासी 38 वर्षीय अखिलेश मंडल के रूप में हुई।

लापता होने की नहीं करायी रिपोर्ट दर्ज

10 जुलाई को अनिल ठाकुर ने अखिलेश को सेक्टर-13, द्वारका बुलाया। इसके बाद, तीनों उस जगह पर गए जहां दोनों आरोपियों ने अखिलेश के साथ मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई। हत्या करने के बाद दोनों आरोपी दिल्ली के नजफगढ़ इलाके के धर्मपुरा भाग गए। आरोपी अनिल ठाकुर मृतक के परिवार को अच्छी तरह जानता था और हत्या करने के बाद वह मृतक के परिवार को गुमराह कर रहा था, इसी वजह से उन्होंने मृतक के लापता होने की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी।

अक्सर होते थे झगड़े

सीसीटीवी एनालिसिस और टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर द्वारका नॉर्थ पुलिस स्टेशन के ब्लाइंड मर्डर केस में शामिल अनिल ठाकुर (66) और राजू कुमार (28) को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान पता चला कि मृतक अखिलेश, अनिल ठाकुर के घर पर ही उसके साथ रह रहा था। शुरू में अनिल ठाकुर की सहमति से अखिलेश को वहां रहने की इजाजत दी गई थी। लेकिन अखिलेश को शराब की लत होने के कारण उनके बीच अक्सर झगड़े होते थे। इसके बाद, अनिल ठाकुर ने अपना घर बेचने का फैसला किया, जिसका मृतक ने विरोध किया।

संक्षिप्त वार्ता

नहर हादसे में जान गंवाने वाली शिवांशी के परिजनों से मिले विधायक रामपाल वर्मा,

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। शारदा नहर में डूबने से 12 वर्षीय शिवांशी की मौत के एक सप्ताह बाद बुधवार को क्षेत्रीय विधायक रामपाल वर्मा पीड़ित परिवार के घर पहुंचे। उन्होंने शोक संतप्त परिजनों को सांत्वना देते हुए आर्थिक सहायता प्रदान की और हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया।

विधायक ने प्रशासन को मुख्यमंत्री दैवीय आपदा राहत योजना के तहत पीड़ित परिवार को शीघ्र आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। उन्होंने परिवार के अन्य बच्चों की शिक्षा में भी सहयोग का आश्वासन दिया और कहा कि इस दुख की घड़ी में वह परिवार के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं। गौरतलब है कि 9 जुलाई को विकासखंड कछौना की ग्राम सभा समसपुर निवासी कन्हैया लाल की तीन बेटियां धान की रोपाई के बाद शारदा नहर में हाथ-पैर धोने गई थीं। इसी दौरान तीनों का पैर फिसल गया और वे नहर में डूबने लगीं। मौके पर मौजूद सुनील राठौर ने साहस दिखाते हुए नहर में छलांग लगाकर दो बच्चियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन 12 वर्षीय शिवांशी तेज बहाव में बह गई। करीब 28 घंटे बाद उसका शव ताजपुर गांव के पास बरामद हुआ था। मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करने वाले कन्हैया लाल की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है और बच्चों की मां का साया भी पहले ही उठ चुका है, जिससे इस हादसे ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है।

ईपीएफओ विश्वास - 2026 डैमेज संबंधी विवादों का करेगा मैत्रीपूर्ण समाधान

वेब वार्ता, कानपुर

विश्वास , 2026 योजना का उद्देश्य ई पीएफ ।बज, 1952 की धारा 1बी (या कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, 2020 की धारा 128) के अंतर्गत लगाए गए (हजार्ना) से संबंधित मामलों का मैत्रीपूर्ण एवं त्वरित निस्तारण किया जायेगा साथ ही योजना के तहत लंबित विवादों को कम करना मुख्य उद्गा। इस योजना की अवधि 1 जुलाई 2026 से 31 दिसंबर 2026 (6 माह) तक रहेगी। लंबित न्यायिक व अपीलीय मामले जहाँ धारा 14बी/128 का आदेश पारित हो चुका है तथा मामला किसी न्यायिक अथवा अर्ध-न्यायिक मंच पर लंबित है। फाइनल 14बी ऑर्डर (आरआरसी) सहित जहाँ डैमेज का आदेश पारित हो चुका है, लेकिन राशि पूरी तरह वसूल नहीं हुई है। जहाँ 14बी/128 का नोटिस जारी हो चुका है ,लेकिन अंतिम आदेश पारित नहीं हुआ है। ऐसे मामले जहाँ अभी तक नोटिस जारी नहीं किया गया है। विश्वास -2026 के अंतर्गत डैमेज की दर 2 माह तक0 .25 : प्रति माह, 2 माह से अधिक एवं 4 माह तक 0 .50 : प्रति माह, 4 माह से अधिक 1 .00 : प्रति माह योजना का लाभ .

हरदोई में खेल प्रतियोगिताओं की तैयारियों को लेकर डीआईओएस ने की समीक्षा बैठक

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। आगामी जनपदीय खेल प्रतियोगिताओं के सफल एवं सुव्यवस्थित आयोजन को लेकर बुधवार को राजकीय इंटर कॉलेज, हरदोई के सभागार में जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) डॉ. अरविन्द कुमार पाठक के निर्देशन में प्रधानाचार्यों एवं शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के संचालन, विद्यालयवार खेलों के आवंटन, खिलाड़ियों की भागीदारी और आवश्यक व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि जनपदीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता-2026 की जिम्मेदारी बी.एन. इंटर कॉलेज, मल्लावां को सौंपी गई है। प्रतियोगिता का आयोजन बी.जी.आर. इंटर कॉलेज, बिलग्राम के खेल मैदान पर कराया जाएगा। साथ ही विभिन्न विद्यालयों को अलग-अलग खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। डीआईओएस डॉ. अरविन्द कुमार पाठक ने कहा कि खेल विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिताओं के दौरान खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना सभी की जिम्मेदारी है। खेलों के माध्यम से बच्चों में आत्मविश्वास, अनुशासन, टीम भावना और संघर्ष करने की क्षमता विकसित होती है, जो उनके भविष्य के निर्माण में सहायक होती है।

नगर पालिका बोर्ड बैठक में विकास योजनाओं, बजट और जनहित के प्रस्तावों पर लगी मुहर

आय-व्यय का अनुमोदन, 2026-27 की निविदाओं को स्वीकृति

हरदोई। नगर पालिका परिषद हरदोई की बोर्ड की साधारण बैठक बुधवार को नगर पालिका कार्यालय में अध्यक्ष सुख सागर मिश्र 'मधुर' की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में नगर के विकास, वित्तीय कार्यों और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। बैठक में अधिशासी अधिकारी रामेंद्र सिंह, सभासदों तथा नामित सदस्यों ने भाग लिया।

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

बैठक में सबसे पहले सितंबर 2025 से जून 2026 तक की आय-व्यय विवरणिका प्रस्तुत की गई, जिसे सदन ने सर्वसम्मति से अनुमोदित कर दिया। इसके बाद वित्तीय वर्ष 2026-27 की सभी निविदाओं एवं ठेकों को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इन मामलों में अग्रिम कार्रवाई के लिए अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी को अधिकृत किया गया।

बैठक में मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना, नवयुग पालिका योजना, वंदन योजना, जलनिकासी योजना और उपवन योजना से संबंधित प्रस्तावों पर चर्चा की गई। साथ ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत एमआरएफ (मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी) सेंटर के निर्माण के प्रस्ताव को भी सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई।

नगर के विभिन्न वार्डों में विकास कार्यों के लिए सभासदों से प्राप्त प्रस्तावों को भी सदन ने स्वीकृति दी। निर्णय लिया गया कि शासन से धन आवंटित होने के आधार पर विकास कार्य कराए जाएंगे। इसके लिए भी अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी को अधिकृत किया गया।

बैठक में नागरिकों की मांग और जनहित को ध्यान में रखते हुए शहर सीमा के लिए एक छोटा शव वाहन तथा शवों के संरक्षण के लिए डीप फ्रीजर खरीदने के प्रस्ताव को भी सर्वसम्मति से मंजूरी प्रदान की गई।

अध्यक्ष सुख सागर मिश्र 'मधुर' ने नगर के विकास कार्यों में सहयोग के लिए प्रदेश के आबकारी एवं मद्य निषेध राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नितिन अग्रवाल का आभार व्यक्त किया। बैठक के अंत में अधिशासी अधिकारी रामेंद्र सिंह ने सभी सदस्यों एवं अधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापित किया।

बैठक में सभासद अमित त्रिवेदी, राजीव कुमार सिंह, संदीप कुमार गुप्ता, संदीप राजवंशी, अरशद हुसैन, संजय कश्यप, धर्मरूचि सिंह, अजय कुमार शर्मा, रोहित कश्यप, राजकुमार गुप्ता, सुधीर कुमार गुप्ता, अभिषेक कुमार मिश्रा, शबाना नियाजी, गीता कुशवाहा, विद्यावती, सोनी सिंह, अंशिका अग्निहोत्री, शांति देवी, मीनू सैनी, प्रतीक्षा प्रियम मिश्रा एवं सुशीला मिश्रा, नामित सदस्य संतोष कुमार पटेल, विनोद कुमार तथा अनूप सिंह मौजूद रहे। इसके अलावा अधिशासी अधिकारी रामेंद्र सिंह सहित पालिका के संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी भी उपस्थित रहे।

बाजार गई बेटी नहीं लौटी, पिता ने बहला-फुसलाकर ले जाने का लगाया आरोप

वेबवार्ता, हरदोई

संडीला थाना क्षेत्र के तिलोइया गांव निवासी एक पिता ने अपनी 18 वर्षीय पुत्री के लापता होने के मामले में कोतवाली बेनीगंज पहुंचकर पुलिस से सकुशल बरामदगी की गुहार लगाई है। पीड़ित ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया कि वह परिवार सहित चंडीगढ़ में मजदूरी करता है। 10 जुलाई 2026 की शाम करीब चार बजे उसकी पुत्री बाजार में सामान खरीदने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजनों ने काफी तलाश की, मगर उसका कोई सुराग नहीं लग सका। पिता का आरोप है कि खोजबीन के दौरान जानकारी मिली कि बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र के पाठकपुर निवासी ललित पुत्र स्वर्गीय राजाराम रैदास उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। उन्होंने बताया कि पुत्री के पास मजदूरी से जोड़े गए करीब 20 हजार रुपये भी थे। पीड़ित ने पुलिस से बेटी की सकुशल बरामदगी, निष्पक्ष जांच और आरोपित के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की मांग की है। वहीं, बेनीगंज पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच शुरू कर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

बागपत में हत्या का मुख्य आरोपी पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार

बागपत, 15 जुलाई (वेब वार्ता)। बागपत जिले के रमाला थाना क्षेत्र में एक युवक की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी। उसके कब्जे से कथित हत्या में प्रयुक्त .315 बोर का एक अवैध तमंचा और दो खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि 14 जुलाई को ग्राम किशनपुर बिराल निवासी विनय (30) के गोली लगने से घायल होने की सूचना मिली थी। घायल को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बड़ौत में उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक, मृतक के परिजनों की तहरीर पर रमाला थाने में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।

मुख्य विकास अधिकारी ने बावन में गौशाला, पशु चिकित्सालय व ब्लॉक कार्यालय का किया निरीक्षण

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। मुख्य विकास अधिकारी ने बुधवार को विकासखंड बावन के अस्थायी गौ आश्रय स्थल, पशु चिकित्सालय, कूड़ा-कचरा अपशिष्ट प्रबंधन (आरआरसी) केंद्र और ब्लॉक कार्यालय का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

गौ आश्रय स्थल की व्यवस्थाओं की सराहना

निरीक्षण के दौरान अस्थायी गौ आश्रय स्थल बावन का रखरखाव उत्कृष्ट पाया गया। यहां स्थापित आनंद बायोगैस प्लांट से सरकारी प्रतिष्ठानों को विद्युत आपूर्ति की जा रही है तथा परिसर में आटा चक्की का भी संचालन हो रहा है। मुख्य विकास अधिकारी ने इस नवाचार की सराहना करते हुए व्यवस्थाओं को लगातार प्रभावी बनाए रखने के निर्देश दिए।

मुख्य विकास अधिकारी ने आरआरसी सेंटर का निरीक्षण कर तैयार वर्मी कम्पोस्ट के विक्रय तथा छंटाई किए गए कचरे के वैज्ञानिक भंडारण की जानकारी ली। उन्होंने केंद्र के संचालन को और अधिक प्रभावी एवं व्यवस्थित बनाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।

पशु चिकित्सालय बावन में निरीक्षण के दौरान उपचार संबंधी व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। मुख्य विकास अधिकारी ने पशु चिकित्सा अधिकारी को बीमार एवं घायल पशुओं का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध उपचार सुनिश्चित करने तथा चिकित्सालय में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध रखने के निर्देश दिए। विकासखंड कार्यालय के निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने परिसर में स्थित जर्जर भवन को तत्काल निस्तारित कराने, साफ-सफाई सुनिश्चित करने, उपस्थिति पंजिका का नियमित निरीक्षण करने और अभिलेखों को अद्यतन रखने के निर्देश दिए।

अधूरे अभिलेख मिलने पर पटल सहायक को चेतावनी

निरीक्षण में स्थापना पटल के अभिलेख अधूरे मिलने पर पटल सहायक अतुल अवस्थी को कठोर चेतावनी देते हुए एक सप्ताह के भीतर सभी अभिलेख पूर्ण और अद्यतन करने के निर्देश दिए गए।

कुशीनगर में बड़ी गंडक नदी का जलस्तर दो लाख क्यूसेक के पार, बाढ़ का खतरा मंडराया

वेब वार्ता,कुशीनगर

नेपाल के तराई एवं जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार हो रही वर्षा के चलते नारायणी (बड़ी गंडक) नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बुधवार को वाल्मीकिनगर गंडक बैराज से पानी का डिस्चार्ज दो लाख क्यूसेक के पार पहुंचने के बाद प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया है। बाढ़ चौकियों को सक्रिय कर दिया गया है।नदी किनारे बसे गांवों और छितौनी तटबंध पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारी तटबंधों का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। संवेदनशील स्थलों पर कर्मचारियों की तैनाती बढ़ा दी गई है। कटानरोधी कार्यों, बोल्डरों तथा स्परों की स्थिति पर भी लगातार नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी आपात स्थिति से समय रहते निपटा जा सके।

जिला प्रशासन ने संभावित खतरे को देखते हुए नावों, राहत सामग्री, पेयजल, चिकित्सा एवं पशु चिकित्सा टीमों को आवश्यकता पड़ने पर तत्काल राहत कार्य शुरू करने का निर्देश दिया है। एसडीआरएफ एवं अन्य आपदा राहत एजेंसियों को भी सतर्क रहने को कहा गया है।

प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों से अपील की है कि वे नदी के तेज बहाव वाले क्षेत्रों में जाने से बचें। साथ ही जलस्तर में और वृद्धि होने की स्थिति में सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। बड़ी गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर कुशीनगर के साथ ही महाराजगंज और देवरिया के निचले इलाकों पर भी खतरा खड़ा होने की बात कही जा रही है।

महाराजगंज के निचलौल और सिसवा विकासखंड के गंडक तटीय गांवों में विशेष रूप से नदी के किनारे बसे शिकारपुर, भोथहा, बसही, सोहगीबरवा आदि में जलभराव और कटान की आशंका को देखते हुए प्रशासन सतर्क है। देवरिया के भी निचले इलाके के गांवों में भी संकट खड़ा हो सकता है।

बड़ी गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए कुशीनगर के खड्डा तहसील प्रशासन ने एहतियातन नारायणी नदी में नाव संचालन पर अगले आदेश तक पूरी तरह रोक लगा दी है। पनियहवा पुल पर नोटिस बोर्ड लगाकर लोगों को इसकी जानकारी दी है।

इस संबंध में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता विकास कुमार सिंह ने बताया कि नारायणी नदी का जलस्तर बीते 24 घंटे से ऊपर की ओर ही जा रहा है।नदी चेतावनी बिंदु से 38 सेमी ऊपर 95 .380 मीटर पर बहती रही।बुधवार की सुबह छह बजे डिस्चार्ज 169200 क्यूसेक,आठ बजे डिस्चार्ज 171900 क्यूसेक, दस बजे तक डिस्चार्ज 188400 क्यूसेक,दोपहर 12 बजे डिस्चार्ज 204800 क्यूसेक क्यूसेक ,दो बजे डिस्चार्ज 216400 क्यूसेक,तीन बजे डिस्चार्ज 219300 क्यूसेक दर्ज किया गया। इस दौरान भैंसहा गेज पर शाम तीन बजे जलस्तर 95 .380 मीटर दर्ज किया गया जो चेतावनी बिंदु से 38 सेमी ऊपर है। जल संसाधन विभाग के अनुसार नदी की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। ग्रामीणों को आशंका है कि डिस्चार्ज में हो रही वृद्धि के कारण रात में दियारा के गांव तक पानी आ सकता है। बड़ी गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर के बीच सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता विकास कुमार सिंह एवं अधीक्षण अभियंता जयप्रकाश सिंह ने बुधवार को छितौनी तटबंध स्थित संवेदनशील वीरभार ठोकर का स्थलीय निरीक्षण किया। अधिकारियों ने सात करोड़ की लागत से हुए बाढ़ सुरक्षा कार्यों की प्रगति का जायजा लेने के साथ संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

देवरिया के गन्ने के खेत में मिला मानव कंकाल, लापता महिला से जुड़ रहे तार

वेब वार्ता, देवरिया

गन्ने के खेत में संदिग्ध मानव कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस मौके पर पहुंची और मानव कंकाल के अवशेष को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई। मौके पर पहुंची फोरेंसिक टीम ने भी जांच कर नमूने लिए। मानव कंकाल का अवशेष बनकटा थाना क्षेत्र के सुंदरपार मिस्त्रौली गांव में मंगलवार की शाम लोगों को दिखा। पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर. शंकर ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर जानकारी ली और निर्देश दिए।

...कोई लिखित शिकातय नहीं दी गई थी

सुन्दरपार मिस्त्रौली गांव की एक महिला 26 जून से लापता बताया जा रही है। हालांकि इस संबंध में स्वजन की ओर से पुलिस को कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई थी। पुलिस इस तथ्य को भी जांच के दायरे में रखकर जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस लापता महिला के स्वजन से भी पूछताछ कर रही है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि यह कंकाल का अवशेष उसी महिला का है। साड़ी व मोबाइल आदि के पहचान कराने का प्रयास कर रही है।

ग्रामीणों खेत में कार्य कर रहे थे कि इसी दौरान कंकाल का हिस्सा दिखाई दिया। मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। इसकी सूचना पुलिस को दी। कंकाल के हिस्से को लेकर ग्रामीणों के बीच तरह-तरह की चचाएं होने लगी। पुलिस ने गहनता से छानबीन की।

घटनास्थल से एक साड़ी और एक छोटा मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। पुलिस ने दोनों वस्तुओं को कब्जे में लेकर जांच में शामिल कर लिया है। पुलिस का कहना है कि बरामद सामान, फोरेंसिक जांच और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर ही पहचान सुनिश्चित की जा सकती है।

फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर नमूने एकत्र किए। पुलिस का कहना है कि फोरेंसिक रिपोर्ट और अन्य जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि बरामद मानव अवशेष किसके हैं। थानाध्यक्ष दिनेश मौर्य ने बताया कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। अभी किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी।

पुलिस ने जांच के दौरान मिली जानकारियों के आधार पर तीन लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। उनसे विभिन्न बिंदुओं पर पूछताछ की जा रही है।

इस संबंध में एसपी अभिजीत आर. शंकर ने बताया कि घटनास्थल से मिले मानव अवशेषों की शिनाख्त और पूरे प्रकरण का पदार्फाश वैज्ञानिक जांच एवं फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर किया जाएगा। फिलहाल पुलिस सभी संभावित पहलुओं पर गंभीरता से जांच कर रही है।

देवरिया पुलिस मुठभेड़ में पशु तस्कर के पैर में लगी गोली, चार गिरफ्तार

वेब वार्ता, देवरिया। पिकअप से पशुओं को बिहार ले जा रहे तस्करों से मंगलवार की रात को पुलिस की मुठभेड़ हो गई। जिसमें एक तस्कर के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। पुलिस ने उसके साथ अन्य तीन तस्करों को भी दबोच लिया है। घायल तस्कर का उपचार चल रहा है। पुलिस ने उसके पास एक तमंचा व दो खोखा कारतूस बरामद किया है। लार पुलिस मंगलवार की रात को क्षेत्र में संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी, कि उसी दौरान एक पिकअप आता हुआ दिखाई दिया। जिसे रोकने का प्रयास करने पर वह चनुकी पुल की तरफ भागने लगा।

पुलिस इसकी सूचना कंट्रोल रूम को देने के साथ ही इसकी जानकारी भाटपाररानी पुलिस को दी। जिसके फुलवरिया चौराहे पर वाहनों की चेकिंग कर रही भाटपाररानी पुलिस सक्रिय हो गई और चनुकी पुल की तरफ तस्करों के पिकअप को रोकने का प्रयास की, लेकिन पिकअप चालक अपने आप को घिरता हुआ देखकर पिकअप को लेकर सोहगरा की तरफ मुड़ गया।

पिकअप चालक बैरियर को गिराते हुए भागने की कोशिश कर रहा था कि वाहन में एक इ्रम के फंस जाने से पिकअप रूक गई, जिसके बाद पुलिस ने पिकअप से तीन तस्करों को दबोच लिया गया। वहीं एक तस्कर पुलिस पर फायर झोंक दिया, पुलिस के जवाबी फायरिंग में भाग रहे तस्कर के दाहिने पैर में गोली लगी, जिससे वह गिर गया।

पुलिस ने उसे आनन- फानन उपचार के लिए सीएचसी भाटपाररानी भेजवाया, जहां उसका उपचार चल रहा था। पूछताछ में तस्करों ने बताया कि छुट्टा पशुओं को इकट्ठा कर उनको तस्करी के लिए बिहार लेकर जा रहे थे। तस्करों ने अपना नाम मो. फैसल पुत्र मरगूब आलम निवासी रामनगर थाना लार, चंदन चौरसिया पुत्र महेंद्र निवासी कुईया थाना भलुअनी व अनवन अंसारी पुत्र अहमद अंसारी निवासी मटियरा जगदीश थाना लार बताया। वहीं मुठभेड़ में घायल तस्कर ने अपना नाम मो. मुन्ना पुत्र मो. मुमताज निवासी हरिहास टोला थाना हुसैनगंज जिला सिवान बिहार बताया। पुलिस ने पिकअप से आठ गोवंशीय पशुओं को बरामद किया है। वहीं तस्कर मुन्ना के पास तमंचा व कारतूस बरामद किया है।

इस संबंध में सुनील कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, दक्षिणी ने बताया कि चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध पिकअप वाहन दिखाई दिया, जिसे रोकने का प्रयास किया गया तो वह चनुकी पुल की तरफ भागने लगा। पुलिस के घेराबंदी के बाद अपने घिरता देखकर एक व्यक्ति ने पुलिस पर फायर झोंक दिया, जबाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी है, उसका उपचार चल रहा है। उसके साथ तीन अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

निर्माणाधीन मकान में खेल बना काल, रस्सी गर्दन में कसने से 12 वर्षीय छात्र की मौत

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। पाली थाना क्षेत्र के खनिकलापुर गांव में खेल-खेल में एक मासूम की जान चली गई। निमार्णाधीन मकान में लटक रही रस्सी से खेलते समय रस्सी 12 वर्षीय छात्र आस्तिक मिश्रा की गर्दन में कस गई, जिससे उसका दम घुटने लगा। गंभीर हालत में उसे मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने लखनऊ रेफर कर दिया। लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई।

स्कूल से लौटने के बाद खेलने गया था आस्तिक

खनिकलापुर गांव निवासी रंजन मिश्रा का पुत्र आस्तिक मिश्रा गांव के उच्च प्राथमिक विद्यालय में कक्षा सात का छात्र था। मंगलवार को वह स्कूल से घर लौटने के बाद घर के पास बन रहे एक निमार्णाधीन मकान में खेलने चला गया। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि खेलते-खेलते ऐसा दर्दनाक हादसा हो जाएगा।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार निमार्णाधीन मकान में लटक रही रस्सियों से खेलते समय एक रस्सी अचानक आस्तिक की गर्दन में फंसकर कस गई। दम घुटने से वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। परिजन और ग्रामीण उसे तत्काल मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर बताते हुए लखनऊ के हायर सेंटर रेफर कर दिया। परिजन एंबुलेंस से आस्तिक को लखनऊ लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। यह खबर गांव पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया और पूरे गांव में मातम छा गया।

पोस्टमार्टम के बाद पुलिस जांच में जुटी

सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला दुर्घटना का प्रतीत हो रहा है। पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है।

बलिया में दहेज हत्या के आरोप में पति और जेठ के खिलाफ मुकदमा दर्ज

वेब वार्ता, बलिया। बलिया जिले के भीमपुरा थाना क्षेत्र में दहेज के लिए 22 वर्षीय विवाहिता की कथित रूप से गला दबाकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने उसके पति और जेठ के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है। एक पुलिस अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, मऊ जिले के कोपागंज थाना क्षेत्र के लिलारी गांव के निवासी आशीष की तहरीर पर मंगलवार को भीमपुरा थाने में अवराई कला पाही गांव के विजेंद्र और विनोद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई।

महत्वपूर्ण ख़बर

जापान को समुद्र में मिला सोना, पर निकालना है बड़ी चुनौती

■ टोक्यो। जापान के वैज्ञानिकों ने समुद्र की गहराई में दुनिया के सबसे समृद्ध स्वर्ण भंडारों में से एक मानी जा रही खोज की है। यह सोना सामान्य रूप में दिखाई नहीं देता, बल्कि चट्टानों के भीतर परमाणु स्तर और बेहद सूक्ष्म कणों के रूप में मौजूद है। इस वजह से वैज्ञानिक इसे अदृश्य सोना भी कह रहे हैं। हालांकि यह खोज समुद्री खनन के क्षेत्र में नई संभावनाएं लेकर आई है, लेकिन इसे निकालने के सामने तकनीकी, आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियां भी कम नहीं हैं। यह खोज टोक्यो से करीब 350 किलोमीटर दक्षिण में स्थित हिगाशी-आओगाशिमा नामक डूबे हुए ज्वालामुखीय क्रेटर में हुई है। यहां वैज्ञानिकों को सक्रिय हाइड्रोथर्मल वेंट्स मिले हैं, जो समुद्र की गहराई से गर्म और धातुओं से भरपूर तरल पदार्थ बाहर निकालते हैं। इसी प्राकृतिक प्रक्रिया के दौरान सोने का निर्माण भी हो रहा है।

थाईलैंड के सुपरमार्केट में मिलता है केले के पत्तों में सामान

■ बैंकॉक। प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या निपटने थाईलैंड के सुपरमार्केट ने प्रभावी कदम उठाया है, जो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने प्लास्टिक पैकेजिंग पर रोक लगाते हुए केले के पत्तों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। अब फल, सब्जियां और अन्य सामान केले के पत्तों में लपेटकर ग्राहकों को दिया जा रहा है, जिससे प्लास्टिक के कचरे को कम करने की दिशा में एक बड़ी उम्मीद जगी है। थाईलैंड के कई सुपरमार्केट चेन ने प्लास्टिक बैग और रैप की जगह केले के पत्तों को अपनाया है। केले के पत्ते बड़े, मजबूत और प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होते हैं। इन्हें आसानी से साफ किया जा सकता है और इनमें सामान पैक करने के बाद इन्हें सीधे खाद में बदला जा सकता है।

भारतीय मूल के अनिल मेनन अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना

आठ महीने चलेगा वैज्ञानिकों का मिशन

नई दिल्ली। भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन मंगलवार को कजाकिस्तान से सोयूज एमएस-29 अंतरिक्ष यान के जरिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) के लिए सफलतापूर्वक रवाना हो गए हैं। उनके साथ दो रूसी अंतरिक्ष यात्री, प्योत्र डुब्रोव और अन्ना किकिना भी इस आठ महीने लंबे मिशन का हिस्सा हैं। यह अंतरिक्ष यान भारतीय समयानुसार रात 8 बजकर 17 मिनट पर बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित हुआ और पृथ्वी के दो चक्कर लगाने के बाद, रात 11 बजकर 56 मिनट पर स्वतः स्टेशन के प्रिचाल मॉड्यूल से जुड़ गया। यह अनिल मेनन की पहली अंतरिक्ष यात्रा है, जबकि उनके रूसी सहयात्री दूसरी बार अंतरिक्ष मिशन पर गए हैं।

प्रक्षेपण के दौरान अनिल मेनन की अंतरिक्ष यात्री पत्नी अन्ना विल्हेम समेत उनके परिवार के सदस्य और नासा के प्रशासक जेरेड आइजैकमैन बैकोनूर कॉस्मोड्रोम में मौजूद थे, जिन्होंने इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनकर उनका उत्साह बढ़ाया। अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचने के बाद, ये तीनों यात्री नासा के अंतरिक्ष यात्रियों (जेसिका मीर, जैक हैथवे और क्रिस विलियम्स), यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की अंतरिक्ष यात्री सोफी एडेनोट, और रोस्कोस्मोस के अंतरिक्ष यात्री सर्गेई कुद-स्वेर्चकोव, सर्गेई मिकाएव और आंद्रेई फेद्यायेव के साथ मिलकर मिशन को आगे बढ़ाएंगे। यह अंतरराष्ट्रीय सहयोग अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य लगभग आठ महीने तक अंतरिक्ष में रहकर वैज्ञानिक अनुसंधान करना और नई प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करना है, जिसका लक्ष्य मानव अंतरिक्ष अन्वेषण को आगे बढ़ाना और पृथ्वी पर जीवन को लाभ पहुंचाने वाली तकनीकों का विकास करना है। तीनों की अप्रैल 2027 में पृथ्वी पर वापसी निर्धारित है। रूस की अंतर्राष्ट्रीय मानवीय सहयोग एजेंसी की प्रमुख येलेना रेमिजोवा ने बताया कि इस रॉकेट के साथ भारतीय स्कूली बच्चों द्वारा बनाई गई चित्रकृतियां भी अंतरिक्ष में भेजी जा रही हैं, जो एक प्रतीकात्मक और प्रेरक कदम है।

अनिल मेनन का जन्म अमेरिका के मिनियापोलिस में यूक्रेनी और भारतीय मूल के प्रवासी माता-पिता के घर हुआ था। वह पेशे से इमरजेंसी मेडिसिन फिजिशियन हैं और अमेरिकी स्पेस फोर्स में कर्नल के पद पर कार्यरत हैं। अमेरिकी वायुसेना में अपनी सेवा के दौरान उन्होंने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के तहत अफगानिस्तान में अग्रिम मोर्चे पर काम किया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने हिमालयन रेस्क्यू एसोसिएशन के साथ जुड़कर माउंट एवरेस्ट पर पर्वतारोहियों को चिकित्सा सहायता प्रदान की है। उन्होंने रोटरी एम्बेसडोरियल स्कॉलर के रूप में भारत में एक वर्ष बिताया था, जहाँ उन्होंने पोलियो टीकाकरण अभियान का अध्ययन और उसमें सहयोग किया।

वांगचुक के अनशन को समाप्त करने लगाई जनहित याचिका

नई दिल्ली। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के दिल्ली के जंतर-मंतर पर 18 दिनों से चल रहे अनशन को समाप्त कराने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। इस याचिका में अदालत से अपील की गई है कि सोनम वांगचुक को तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान की जाए और उनकी जान बचाने के लिए उन्हें जबरन खाना खिलाकर उनका अनशन खत्म कराया जाए।

याचिकाकर्ता राकेश कुमार सैनी, जो एक एक्टिविस्ट के साथ ही वकील हैं, ने यह कदम वांगचुक के तेजी से बिगड़ते स्वास्थ्य को देखते हुए उठाया है। उन्होंने अदालत से केंद्र और दिल्ली सरकार को निर्देश देने की मांग की है कि वांगचुक को अस्पताल ले जाया जाए और उन्हें दबाव डालकर पोषक तत्व, विटामिन और खनिज तरल के रूप में दिए जाएं, जो मानव शरीर के जीवित रहने के लिए आवश्यक हैं।

सोनम वांगचुक कॉकरोच जनता पार्टी के मंच पर नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर 28 जून से अनशन पर बैठे हैं। वकील सैनी ने अपनी याचिका में चिंता व्यक्त की है कि यदि सोनम वांगचुक अनशन के दौरान मर जाते हैं, तो यह देश और दुनिया के लिए एक अत्यंत शर्मनाक बात होगी। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वह वांगचुक के साथ किसी खतरनाक अपराधी, आतंकवादी या देश के गद्दार जैसा व्यवहार कर रही है और उन्हें एक मशहूर सामाजिक और पर्यावरण कार्यकर्ता की चिंता नहीं है। सैनी ने जोर देकर कहा कि सरकार कम से कम इतना तो कर सकती है कि उन्हें उचित मेडिकल सहायता दी जाए, भले ही वह जबरन ही क्यों न हो, ताकि उनकी जान बचाई जा सके। यह महत्वपूर्ण है कि सोनम वांगचुक के इस अनशन को लेकर सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच अभी तक किसी तरह की बातचीत या मध्यस्थता शुरू नहीं हुई है। हालांकि, देश के विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं ने अब वांगचुक तक पहुंचना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी सहित कई दलों के नेता जंतर-मंतर पर वांगचुक से मिलने पहुंचे हैं।

ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल जैसे प्रमुख नेताओं ने सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों के जरिए भी सोनम वांगचुक से अनशन खत्म करने की अपील की है, जिससे इस मुद्दे की गंभीरता और राजनीतिक संवेदनशीलता और बढ़ गई है। याचिका पर अदालत का फैसला और सरकार की अगली प्रतिक्रिया अब सबकी निगाह में होगी।

एआई अब स्मार्टफोन उपयोग का अभिन्न हिस्सा बना

68 फीसदी उपभोक्ता नया स्मार्टफोन खरीदते समय एआई को दे रहे ज्यादा प्राथमिकता

नई दिल्ली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) अब केवल स्मार्टफोन का एक अतिरिक्त फीचर नहीं है, बल्कि उपभोक्ताओं के खरीदारी के फैसले को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक बन रहा है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक 68 फीसदी उपभोक्ता नया स्मार्टफोन खरीदते समय एआई फीचर्स को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। वहीं 82 फीसदी लोगों का मानना है कि डेटा प्रबंधन में पारदर्शिता और गोपनीयता का भरोसा भी खरीदारी के फैसले में अहम भूमिका निभाता है।

रिपोर्ट के मुताबिक 61 फीसदी उपभोक्ताओं का मानना है कि ऑन-डिवाइस एआई प्रोसेसिंग स्मार्टफोन की गति और प्रतिक्रिया क्षमता को बेहतर बनाती है। इसके साथ ही यह उपयोगकताओं के डेटा को ज्यादा सुरक्षित रखने में भी मदद करती है। यही कारण है कि अब उपभोक्ता ऐसे स्मार्टफोन को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिनमें एआई तकनीक बेहतर प्रदर्शन और सुरक्षा के साथ उपलब्ध हो।

सर्वेक्षण में शामिल 78 फीसदी लोगों ने बेहतर परफॉर्मेंस को स्मार्टफोन की सबसे अहम विशेषता बताया है, जबकि 70 फीसदी उपभोक्ताओं ने एआई से लैस कैमरा फीचर्स को अपनी प्राथमिकता माना है। वहीं 59 फीसदी लोगों का कहना है कि मजबूत एआई क्षमताएं उनके खरीदारी के फैसले को प्रभावित करती हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि एआई ने अब डिजाइन, कीमत और बैटरी लाइफ जैसे पारंपरिक मानकों को भी पीछे छोड़ना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक यदि समान कीमत वाले दो स्मार्टफोन में से किसी एक का चयन करना हो तो 60 फीसदी लोग ऐसे डिवाइस को चुनना पसंद करेंगे, जिसमें दमदार हार्डवेयर और आधुनिक एआई फीचर्स हों। वहीं 25 फीसदी लोग एआई को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, जबकि केवल 15 फीसदी उपभोक्ता ऐसे हैं जो आज भी हार्डवेयर को ही सबसे अहम मानते हैं।

ट्रंप की धमकी

पुल और पावर प्लांट तबाह कर देंगे, मचेगा हाहाकार

वॉशिंगटन। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है, जिससे वैश्विक स्तर पर हाहाकार मचने की आशंका गहरा गई है। दोनों देशों के बीच हुआ युद्धविराम समझौता पूरी तरह टूट चुका है और अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर वह जल्द से जल्द बातचीत की मेज पर नहीं लौटता, तो अगले सप्ताह से अमेरिकी सेना ईरान के बुनियादी ढांचे, जिसमें पुल और पावर प्लांट शामिल हैं, को पूरी तरह तबाह कर देगी। ट्रंप ने स्पष्ट कहा है कि ईरानियों के पास अब डील करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है।

ट्रंप ने एक साक्षात्कार में अपने कड़े रुख को स्पष्ट करते हुए कहा, अगला हफ्ता उनके लिए बहुत बुरा होने वाला है क्योंकि अगले हफ्ते पावर प्लांट्स का नंबर आएगा। अगले हफ्ते पुलों की बारी आएगी। हम उनके सभी पावर प्लांट्स और सभी पुलों को उड़ा देंगे, जब तक कि वे समझौता नहीं कर लेते। उन्होंने यह भी जोड़ा कि अमेरिकी सेना के ये हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक वे खुद बहुत हो गया न कह दें। ट्रंप के इस बयान ने मध्य पूर्व में पहले से ही तनावपूर्ण माहौल को और अधिक गंभीर बना दिया है।

यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब अमेरिकी सेना लगातार चौथे दिन ईरान के सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले कर रही है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने जानकारी दी है कि ईरान के सभी बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में नाकेबंदी को दोबारा पूरी तरह लागू कर दिया गया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अमेरिका ने 20 से अधिक युद्धपोत और सैकड़ों लड़ाकू विमान भी तैनात कर दिए हैं, जिससे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज एक बार फिर जंग का अखाड़ा बन गया है। इस बीच, पहले अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसके जवाब में ईरान ने बहरीन और जॉर्डन जैसे देशों पर हमला कर दिया था, जिसने क्षेत्रीय अस्थिरता को और बढ़ा दिया। अमेरिका के इस आक्रामक रवैये पर ईरान ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। ईरान के उप-विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने अमेरिका पर इस्लामाबाद समझौता तोड़ने का आरोप लगाते हुए कहा है कि अमेरिका ने फिर से नाकेबंदी लागू करके और शर्तों से पीछे हटकर इस समझौते को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। ईरान का साफ कहना है कि वे अमेरिका की इस आर्थिक और सैन्य नाकेबंदी के दबाव में किसी भी तरह की बातचीत के लिए वापस नहीं लौटेंगे। ऐसे में वैश्विक तेल और ऊर्जा बाजार पर एक बार फिर गहरा संकट मंडराने लगा है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ने की आशंका है।

ट्रंप के नए ऐलान से भारत के ऊर्जा बाजार में भूचाल की आशंका

नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक हालिया ऐलान ने पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार में नई हलचल मचा दी है। उन्होंने होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले मालवाहक जहाजों पर 20 फीसदी शुल्क लगाने और ईरानी बंदरगाहों की समुद्री नाकेबंदी फिर से शुरू करने की घोषणा की है। यह फैसला ऐसे संवेदनशील समय में आया है, जब अमेरिका, ईरान और इजरायल के बीच तनाव लगातार चरम पर है, जिससे पश्चिम एशिया में अस्थिरता का खतरा बढ़ गया है। इसका सबसे बड़ा असर उन देशों पर पड़ सकता है, जो खाड़ी देशों से तेल और गैस आयात करते हैं, और इनमें भारत सबसे प्रमुख देशों में से एक है।

जापान 80 साल बाद कर रहा है सबसे बड़े खुफिया तंत्र का पुनर्गठन

टॉक्यो। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान अपनी खुफिया प्रणाली में एक अभूतपूर्व और बड़े पैमाने पर बदलाव करने जा रहा है। प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची की सरकार एक नई केंद्रीय खुफिया एजेंसी की स्थापना कर रही है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य देश की विभिन्न खुफिया एजेंसियों को एक साथ जोड़ना और उनके बीच सूचना साझाकरण को मजबूत करना है। इस महत्वपूर्ण पहल में जापान को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी जैसे प्रमुख देशों से विशेषज्ञ सलाह और तकनीकी सहायता मिल रही है। इस पुनर्गठन का मुख्य कारण चीन, रूस और उत्तर कोरिया से बढ़ते भू-राजनीतिक खतरे, साइबर हमलों की बढ़ती संख्या, जासूसी गतिविधियों में वृद्धि और गलत सूचनाओं के प्रसार जैसी आधुनिक चुनौतियों का सामना करना है।

इस नई एजेंसी का प्रारंभिक बजट लगभग 407 मिलियन डॉलर (लगभग 3,500 करोड़ रुपये) रखा गया है, और शुरुआत में इसमें सैकड़ों अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे, जिनमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ और विदेशी मामलों के जानकार प्रमुख होंगे। यह एजेंसी जापान सरकार के विभिन्न विभागों में खुफिया जानकारी से जुड़े लगभग 33 हजार अधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित करेगी। वर्तमान में, जापान में पुलिस, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और अन्य सरकारी संस्थाएं अपनी-अपनी खुफिया जानकारी अलग-अलग तरीकों से जुटाती हैं। हालांकि, इन एजेंसियों के बीच सूचना साझा करने की व्यवस्था अपेक्षाकृत कमजोर है, जिसके कारण अक्सर महत्वपूर्ण जानकारी समय पर संबंधित विभागों तक नहीं पहुंच पाती। नई एजेंसी इसी कमी को दूर करने के लिए डिजाइन की गई है। इसका काम विभिन्न विभागों से प्राप्त होने वाली खुफिया जानकारी को एक जगह इकट्ठा करना, उसका गहन विश्लेषण करना और आवश्यकतानुसार उसे संबंधित एजेंसियों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना होगा। पिछले कुछ वर्षों में जापान अपनी सुरक्षा व्यवस्था को लगातार मजबूत कर रहा है और सरकार का मानना है कि आज के दौर में केवल सैन्य शक्ति ही पर्याप्त नहीं है। साइबर सुरक्षा को बढ़ाना, संवेदनशील तकनीक की चोरी को रोकना और विदेशी जासूसी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखना भी उतना ही आवश्यक हो गया है, जिसके लिए इस नए एकीकृत खुफिया तंत्र की आवश्यकता महसूस की गई है।

अमेरिका जापान को अपनी साइबर सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करने, तकनीकी चोरी को रोकने और विदेशी एजेंटों पर नजर रखने के तरीकों पर मार्गदर्शन दे रहा है।

अब शहीद दिवस के बहाने दो खेमों में बंटी दिख रही टीएमसी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजनीति में 21 जुलाई की तारीख एक ऐतिहासिक और भावनात्मक महत्व रखती है, जिसे हर साल अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिन 1993 में हुई एक दुखद घटना की याद दिलाता है, जब युवा कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी ने वामपंथी सरकार के खिलाफ निष्पक्ष चुनाव और फोटो पहचान पत्र की अनिवार्यता की मांग को लेकर कोलकाता स्थित सचिवालय राइटर्स बिल्डिंग की ओर एक विशाल मार्च का नेतृत्व किया था। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध गोलीबारी की थी, जिसमें युवा कांग्रेस के 13 कार्यकर्ताओं की जान चली गई थी और सैकड़ों घायल हुए थे। इस घटना ने ममता बनर्जी की राजनीतिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित किया और बाद में 1998 में उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर तृणमूल कांग्रेस का गठन किया, जिसके बाद से यह दिन टीएमसी के सबसे बड़े राजनीतिक कार्यक्रम के रूप में मनाया जाता है।

हालांकि, इस साल 21 जुलाई का यह दिन तृणमूल कांग्रेस के लिए एक नई चुनौती और आंतरिक कलह का गवाह बन गया है। पार्टी दो गुटों में बंट चुकी है, जिससे यह पहला मौका होगा जब दो प्रतिद्वंद्वी गुट इस महत्वपूर्ण दिन पर अलग-अलग कार्यक्रमों की तैयारी कर रहे हैं। ऋतब्रत बनर्जी की अगुवाई वाले

बागी धड़े ने कहा है कि यदि पार्टी की संस्थापक ममता बनर्जी चाहें तो वे 21 जुलाई को उनके द्वारा आयोजित शहीद दिवस रैली में एक सलाहकार के रूप में शामिल हो सकती हैं, हालांकि उन्हें औपचारिक रूप से आमंत्रित करने पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। बागी गुट ने ममता बनर्जी को पार्टी अध्यक्ष पद से हटाकर अरूप रॉय को नया अध्यक्ष चुन लिया है और समानांतर राज्य व जिला समितियों का गठन कर खुद को मजबूत करने का दावा किया है।

उन्होंने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाकर खुद को असली टीएमसी के रूप में मान्यता देने की मांग भी की है। इतना ही नहीं, टीएमसी के 28 लोकसभा सांसदों में से लगभग 20 सांसद पार्टी से अलग होकर एनसीपीआई में विलय कर चुके हैं और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के साथ हाथ मिला लिया है, जिससे ममता बनर्जी के लिए पार्टी का नाम और निशान बचाने की चुनौती खड़ी हो गई है।

रैलियों का स्थान भी दोनों गुटों के बीच जंग का अखाड़ा बन गया है। बागी खेमे को उनके पारंपरिक आयोजन स्थल धर्मतल्ला में रैली करने की अनुमति नहीं मिली, जिसके बाद इस गुट ने मेयो रोड पर गांधी प्रतिमा के पास कार्यक्रम आयोजित करने के लिए पुलिस की मंजूरी हासिल कर ली है। दूसरी ओर, ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले खेमे ने धर्मतल्ला में जगह न मिलने के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया है और अभी तक अपने अंतिम कार्यक्रम की घोषणा नहीं की है। कांग्रेस भी इस दिन शहीद स्मारक पर जाकर मारे गए कार्यकताओं को श्रद्धांजलि अर्पित करती है, लेकिन उनके कार्यक्रम टीएमसी की तुलना में काफी सीमित होते हैं।

थाईलैंड में भारतीयों के लिए वीजा-मुक्त प्रवेश जारी, पर...

बैंकॉक। थाईलैंड ने भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए बिना वीजा के प्रवेश जारी रखने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिससे भारतीय पर्यटकों को बड़ी राहत मिली है। हालांकि, इस नीति में एक अहम बदलाव किया गया है, अब भारतीय नागरिक बिना वीजा के थाईलैंड में अधिकतम 30 दिनों तक ही रुक पाएंगे। यह निर्णय थाई सरकार द्वारा भारतीय पर्यटकों की संख्या में आई भारी गिरावट के बाद लिया गया है, जब वीजा-फ्री एंट्री पर रोक लगाने संबंधी एक प्रस्ताव सामने आया था। भारत थाईलैंड के पर्यटन के लिए एक प्रमुख बाजार है, जहाँ से बड़ी संख्या में लोग हर साल घूमने जाते हैं।

थाईलैंड कैबिनेट ने मंगलवार को अपनी साप्ताहिक बैठक में भारतीय यात्रियों के लिए 30 दिन की वीजा-फ्री एंट्री को मंजूरी दे दी। पर्यटन मंत्री सुरसक पंचरोएनवोराकुल ने स्पष्ट किया कि इस कदम का मुख्य उद्देश्य भारतीय पर्यटकों के लिए यात्रा को आसान बनाना और देश के पर्यटन उद्योग को सहारा देना है। उन्होंने कहा कि इसलिए कैबिनेट ने भारतीय पर्यटकों के लिहाज से 30 दिन की वीजा-फ्री एंट्री को मंजूरी दी। यह थाईलैंड के लिए एक बड़ा बाजार हैं। पर्यटन मंत्री ने यह भी कहा कि अगर भविष्य में इस नीति से कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो सरकार इसकी समीक्षा कर सकती है। यह दिखाता है कि थाईलैंड अपने पर्यटन क्षेत्र को लेकर कितना संवेदनशील और रणनीतिक है। पहले भारतीय यात्रियों को बिना वीजा के थाईलैंड में 60 दिनों तक रहने की अनुमति थी।

लेकिन मई में थाई कैबिनेट द्वारा वीजा-मुक्त देशों की सूची को 93 से घटाकर 54 करने और 30 दिन की अवधि तय करने का प्रस्ताव आया था। भारत के साथ-साथ, थाईलैंड ने क्रोएशिया, बुल्गारिया, साइप्रस, माल्टा और मालदीव जैसे अन्य देशों के यात्रियों के लिए भी 30-दिन की वीजा-फ्री एंट्री को मंजूरी दी है। उप-सरकारी प्रवक्ता प्लॉयटाले लक्समीसांगचन ने बताया कि इस नए फैसले के बाद 30-दिन की वीजा-फ्री एंट्री के लिए योग्य देशों की संख्या बढ़कर 60 हो गई है, जिसमें यूरोपीय संघ के सभी 27 सदस्य देश भी शामिल हैं। प्लॉयटाले ने यह भी कहा कि यह अपडेट की गई नीति थाई पासपोर्ट धारकों के लिए शेंगेन वीजा छूट हासिल करने के थाई प्रयासों को भी समर्थन दे सकती है, जिससे अंतरराष्ट्रीय संबंधों में मजबूती आएगी। ये वीजा नीति में बदलाव ऐसे समय में आ रहे हैं जब प्रधानमंत्री अनुतिन चर्णविराकुल की सरकार उन विदेशी देशों पर कड़ी निगरानी रखना चाहती है जिन पर थाईलैंड के वीजा-फ्री सिस्टम का गलत तरीके से इस्तेमाल करके गैरकानूनी गतिविधियां करने का आरोप है।

सरकार स्थानीय व्यवसायों की चिंताओं का भी जवाब दे रही है, खासकर पर्यटन स्थलों पर। पर्यटन थाईलैंड के लिए एक प्रमुख आर्थिक स्रोत है; पिछले साल थाईलैंड ने 33 मिलियन विदेशी पर्यटकों से लगभग 50 बिलियन डॉलर कमाए थे और इस साल 4 जुलाई तक 16 मिलियन से अधिक अंतरराष्ट्रीय पर्यटक यहाँ पहुंच चुके हैं। इस प्रकार, यह नीति थाईलैंड की अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के हितों को साधने का प्रयास करती है।

प्रदेश के बुनियादी ढांचे और जन-कल्याण के लिए 10 हजार 800 करोड़ रुपए की स्वीकृति

नगरीय क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास के लिए 8 हजार 445 करोड़ रुपए की स्वीकृति

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में सम्पन्न हुई। मंत्रि-परिषद की बैठक में मध्यप्रदेश के बुनियादी ढांचे और जन-कल्याण के लिए 10 हजार 800 करोड़ रुपये के विभिन्न विकास प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। राज्य सरकार ने शहरों के कायाकल्प के लिए नगरीय अधोसंरचना विकास मद में 8 हजार 445 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। इसके साथ ही कैबिनेट ने किसानों के हित में मूंग उपार्जन के लिए 1,587 करोड़ रुपये की निःशुल्क शासकीय प्रत्याभूति और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए कुण्डलिया परियोजना को निरंतर रखने जैसे कई दूरगामी और ऐतिहासिक निर्णयों पर मुहर लगायी है।

मंत्रि-परिषद ने राजगढ़ में जल संसाधन विभाग की कुण्डलिया वृहद सिंचाई परियोजना को 16वें केन्द्रीय वित्त आयोग की अवधि 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक निरन्तर संचालन के लिए 245 करोड़ 45 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। राजगढ़ जिले में निर्मित यह एक वृहद सिंचाई परियोजना है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य बांध निर्माण कर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के माध्यम से राजगढ़ और आगर-मालवा जिले के 1,39,600 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित करना है। मंत्रि-परिषद ने रबी वर्ष 2023-24 विपणन वर्ष 2024-25 में भारत सरकार की प्राईस सपोर्ट स्कीम अन्तर्गत लक्ष्य से अधिक उपार्जित मूंग के लिए 1,587 करोड़ रुपए की निःशुल्क शासकीय प्रत्याभूति उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया है। निर्णय अनुसार पंजाब नेशनल बैंक से ली गई साख सीमा में 19 जुलाई 2026 से 18 जनवरी 2027 तक 6 माह की अवधि के लिए शेष राशि 396 करोड़ रुपए की निःशुल्क शासकीय प्रत्याभूति और भारतीय स्टेट बैंक से ली गई साख सीमा में 3 जुलाई 2026 से 2 जुलाई 2027 तक 1 वर्ष की अवधि के लिए शेष राशि 1,191 करोड़ रुपए की निःशुल्क शासकीय प्रत्याभूति उपलब्ध कराई जायेगी।

मंत्रि-परिषद ने टेक-होम राशन के उत्पादन एवं प्रदाय की व्यवस्था मध्यप्रदेश राज्य आजीविका फोरम से वापस लेते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग को तत्काल हस्तांतरित किये जाने का निर्णय लिया है। तत्कालिक रूप से अन्तरिम व्यवस्था के रूप में स्व सहायता समूह से पूरक पोषण आहार प्रदाय के लिए विभाग को अधिकृत किया गया है। अन्तरिम व्यवस्था तत्काल प्रारंभ किए जाने के साथ ही भारत सरकार के नवीन दिशा निर्देश जारी होने एवं नवीन निर्देश अनुसार व्यवस्था स्थापित होने तक के लिए टेक होम राशन की व्यवस्था, अल्प कालीन निविदा के माध्यम से किए जाने के लिए विभाग को अधिकृत किया गया है। भारत सरकार के नवीन दिशा निर्देश जारी होने के बाद विभाग स्थायी व्यवस्था स्थापित करेगा।

नगरीय क्षेत्रो में अधोसंरचना विकास के लिए 8 हजार 445 करोड़ रुपए की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने वाणिज्य कर विभाग के तहत पालिका अधिनियम अंतर्गत पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क के अधिभार से प्राप्त राशि का निधि में अंतरण से संबंधित योजना के आगामी 5 वर्षों तक संचालन के लिए 8 हजार 445 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है।

पालिका अधिनियम अंतर्गत मुदांक शुल्क के साथ म.प्र. नगर पलिका/नगर निगम अतिरिक्त शुल्क के रूप में उद्गहीत की गई राशि को नगरीय विकास विभाग को अंतरित किया जाता है। इस राशि का उपयोग नगर निगम, नगर पलिका तथा नगर परिषद द्वारा नगरीय क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन तथा ऐसी परियोजनाओं के लिए निकायों द्वारा लिए गये ऋण पुनर्भुगतान के लिए किया जाता है। मंत्रि-परिषद ने वाणिज्यिक कर विभाग के अंतर्गत संचालित तीन स्थापना योजनाओ को आगामी 5 वर्षों की अवधि यानि वित्तीय वर्ष 2026-27 से वर्ष 2030-31 तक के लिए निरंतर संचालन के लिए कुल राशि 521 करोड़ 4 लाख रुपये की स्वीकृति दी है। स्वीकृति अनुसार मुख्यालय संचालन के लिए 60 करोड़ 81 लाख रुपए जिला कार्यालय संचालन के लिए 434 करोड़ 81 लाख रुपए और परिक्षेत्रीय कार्यालय के संचालन के लिए 25 करोड़ 42 लाख रुपए स्वीकृत किए गए है। इन योजनाओं के तहत कर्मचारियों के वेतन-भत्ते, कार्यालय व्यय, व्यावसायिक सेवाओं का भुगतान और मशीन/फर्नीचर/वाहनों का संधारण किया जाता है।

महत्वपूर्ण ख़बर

शहरों को हरा-भरा और प्रदूषण मुक्त बनाएगी नमो हरित-नगर योजना

■ भोपाल। मध्यप्रदेश के शहरों को स्वच्छ, सुंदर और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए राज्य सरकार ने एक महत्वाकांक्षी कदम उठाया है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा आगामी 5 वर्षों के लिए 100 करोड़ के बजट के साथ "नमो हरित-नगर योजना" को संचालित किया जाएगा। योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में हरियाली बढ़ाना, खाली पड़े क्षेत्रों को पार्क के रूप में विकसित करना और सुंदर 'नगर वन' (अर्बन फॉरेस्ट) विकसित करना है।

भारतीय संस्कृति और सेवा भाव ही सशक्त समाज की आधारशिला

■ भोपाल। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह ने सामाजिक न्याय विभाग के सभागार में राज्य स्तरीय कार्यशाला "क्रिएटिंग अ वेल फंक्शनिंग केयर इकॉनोमी" का शुभारंभ किया।

मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास" के मंत्र तथा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश सरकार समाज के प्रत्येक कमजोर एवं वंचित वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

विभाग सामाजिक सुरक्षा, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, वरिष्ठ नागरिक कल्याण तथा पुनर्वास सेवाओं को अधिक प्रभावी, सुलभ एवं तकनीक आधारित बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति, परंपराएं और पारिवारिक मूल्य हमारी सबसे बड़ी शक्ति है।

सिरदर्द से परेशान महिला फांसी पर झूली

■ ग्वालियर। भितरवार नगर में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मोहनगढ़ के उप प्रबंधक की पत्नी ने बीती रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला लंबे समय से सिरदर्द (माइग्रेन) की गंभीर बीमारी से पीड़ित थीं और उनका इलाज चल रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।

मृतका की पहचान कविता राजपूत (42), पत्नी देवेंद्र सिंह राजपूत के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार, मंगलवार रात परिवार के सदस्य खाना खाने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान कविता अपने कमरे में चली गईं और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया।

अब स्नातक एवं स्नातकोत्तर की कक्षाओं में विद्यार्थी 31 जुलाई तक ले सकेंगे प्रवेश

भोपाल। उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए द्वितीय चरण की कॉलेज लेवल काउंसलिंग (सीएलसी) की अंतिम तिथि बढ़ा दी है।

अब विद्यार्थी प्रदेश के शासकीय, अनुदान प्राप्त अशासकीय और अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में 31 जुलाई तक प्रवेश ले सकेंगे।

इस संबंध में आयुक्त उच्च शिक्षा श्री प्रबल सिपाहा ने मंगलवार को आदेश भी जारी कर दिए हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार द्वितीय चरण की सीएलसी की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2026 थी, जिसे बढ़ाकर अब 31 जुलाई 2026 कर दिया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित अन्य सभी शर्तें, नियम एवं दिशा-निर्देश पूर्ववत लागू रहेंगे।

मध्यप्रदेश राज्य हॉकी अकादमी के चार खिलाड़ी भारतीय टीम में, मस्कट में दिखाएंगे दम

भोपाल। मध्यप्रदेश राज्य हॉकी अकादमी के खिलाड़ियों ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। पुरुष वर्ग में आयुष रजक (गोलकीपर) एवं करण गौतम तथा महिला वर्ग में महक परिहार (गोलकीपर) एवं नौशीन नाज (फॉरवर्ड) का भारतीय टीम में चयन यूथ हॉकी5२ एशियन चैंपियनशिपझ2026 के लिए हुआ है। यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता 20 से 25 जुलाई 2026 तक मस्कट, ओमान में आयोजित होगी।

पुरुष वर्ग की भारतीय टीम में आयुष रजक और करण गौतम का चयन प्रदेश की मजबूत हॉकी संरचना एवं उत्कृष्ट प्रशिक्षण व्यवस्था का प्रमाण है। वहीं महिला वर्ग में महक परिहार और नौशीन नाज की जगह भारतीय टीम में बनना यह दशार्ता है कि मध्यप्रदेश की बेटियां भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

प्रदेश के लिए गौरव, देश के लिए उम्मीद

चारों खिलाड़ियों का भारतीय टीम में चयन खेल एवं युवा कल्याण विभाग की खेल प्रतिभाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता का सशक्त उदाहरण है। यह उपलब्धि प्रदेश के उभरते खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्त्रोत है और विश्वास दिलाती है कि समर्पण, अनुशासन और निरंतर प्रशिक्षण से विश्व मंच तक पहुंचना संभव है। भारतीय टीम में चयनित इन खिलाड़ियों ने हाल ही में जापान के काकामिगाहारा में आयोजित व-18 एशिया कप-2026 में भी अपने शानदार प्रदर्शन से देश और मध्यप्रदेश का गौरव बढ़ाया था। पुरुष वर्ग में आयुष रजक और करण गौतम उस भारतीय टीम का हिस्सा रहे, जिसने फाइनल में शानदार जीत दर्ज कर एशिया का स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं महिला वर्ग में महक परिहार और नौशीन नाज ने भारतीय टीम को कांस्य पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई। विशेष रूप से नौशीन नाज ने पूरे टूर्नामेंट में 12 गोल दागकर टूनार्मेंट की टॉप स्कोरर बनने का गौरव हासिल किया। व-18 एशिया कप में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद अब यही खिलाड़ी मस्कट में आयोजित होने वाली यूथ हॉकी5२ एशियन चैंपियनशिप-2026 में भारतीय टीम से एक बार फिर स्वर्णिम प्रदर्शन की उम्मीदों के साथ उतरेंगे। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने भारतीय टीम में चयनित प्रदेश के सभी खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।

अंतरिक्ष दीर्घा में विज्ञान से संबंधित कृतियां विश्व स्तरीय : मुख्यमंत्री

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भोपाल स्थित आंचलिक विज्ञान केंद्र में अंतरिक्ष अन्वेषण दीर्घा का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंचे विद्यार्थियों ने अंतरिक्ष दीर्घा का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव और केन्द्रीय मंत्री श्री शेखावत ने अनेक प्रादर्श देखे और उनकी सराहना की। प्रदेश में अपने तरह की इस अनोखी अंतरिक्ष अन्वेषण दीर्घा के भोपाल जिला प्रशासन भी सहभागी है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आंचलिक विज्ञान केन्द्र में केंद्रीय मंत्री श्री शेखावत का स्वागत करते हुए कहा कि उन्होंने अंतरिक्ष अन्वेषण दीर्घा के शुभारंभ के लिए भोपाल आकर हमारा उत्साहवर्धन किया है। उन्होंने दीर्घा का सूक्ष्मता से अवलोकन किया है। इस क्षेत्र में उनका मार्गदर्शन भी मिल रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में मंत्रालय कार्य कर रहे हैं। भविष्य की दृष्टि से विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने जिस तरह अपने कदम बढ़ाए हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी से लेकर अन्य सभी क्षेत्रों में अद्भुत कार्य हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह भी महत्वपूर्ण है कि आंचलिक विज्ञान केन्द्र भोपाल में अंतरिक्ष अन्वेषण दीर्घा की स्थापना कम व्यय से हुई है और इसमें अधिकतम जानकारी देने की व्यवस्था की गई है। बच्चों की विज्ञान संबंधी जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए अलग-अलग प्रकार की कृतियां स्थापित की गई हैं, जो विश्व स्तरीय हैं। यह दीर्घा प्रदेश के गौरव और गरिमा को बढ़ाने का कार्य करेगी।

लोकार्पण अवसर पर भोपाल महापौर श्रीमती मालती राय, नगर निगम सभापति श्री किशन सूर्यवंशी, मध्यप्रदेश आंचलिक विज्ञान केन्द्र के निदेशक श्री साकेत सिंह कौरव और मध्यप्रदेश विज्ञान और

प्रौद्योगिक परिषद के महानिदेशक श्री अनिल कोठारी और बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित थे।

केंद्रीय मंत्री श्री शेखावत ने कहा कि मध्यप्रदेश देश का दिल है। पर्यटन से लेकर संस्कृति के संरक्षण में प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के विरासत और विकास के सपने को पूरा करने के लिये मध्यप्रदेश में जहां धरातल पर संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन का कार्य हो रहा है, वहीं अंतरिक्ष विज्ञान तक देश के साथ प्रदेश की पहुंच भी बढ़ रही है। विद्यार्थियों को अंतरिक्ष विज्ञान के नवीनतम ज्ञान और शोध से जोड़ने के प्रयास किए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपने नेतृत्व में मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री श्री मोदी के मंत्र को साकार करने की दिशा में अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है।

केंद्रीय मंत्री श्री शेखावत ने कहा कि आंचलिक विज्ञान केंद्र में अंतरिक्ष अन्वेषण दीर्घा के रूप में भोपाल को बड़ी सौगात मिली है। यह मध्यप्रदेश के लिए विशिष्ट दिन है। इस दीर्घा में भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में ऐतिहासिक काल से लेकर अब तक की प्राप्त उपलब्धियों की यात्रा का वर्णन और वर्तमान में देश और मध्यप्रदेश अंतरिक्ष क्षेत्र में क्या प्रयास कर रहे हैं, इसे विस्तार से दीर्घा में प्रदर्शित किया गया है। इंटरैक्टिव तरीके से विद्यार्थी यहां आकर गहनता से विषय को समझ सकें, इसकी व्यवस्था की गई है। इस दीर्घा को स्कूली बच्चों के साथ आमजन के लिए भी खोला गया है। यह प्रयास मध्यप्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई स्पेस पॉलिसी को मजबूती प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम भी है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के मार्गदर्शन में इस क्षेत्र को आमजन के लिए खोला गया है। भारत ने इस क्षेत्र में तीव्र प्रगति दर्ज की है। मध्यप्रदेश ने अपनी स्पेस पॉलिसी बनाई है। अंतरिक्ष अन्वेषण दीर्घा बनने के बाद निश्चित ही मध्यप्रदेश की स्पेस पॉलिसी के लक्ष्य को प्राप्त करने का ठोस प्रयास है। इस तरह अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में मध्यप्रदेश के महत्वपूर्ण योगदान के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव बधाई के पात्र हैं। नई शिक्षा नीति में भी स्पेस टेक्नोलॉजी को प्रमुखता से शामिल किया गया है। आंचलिक विज्ञान केंद्र, भोपाल में स्थापित ह्यहॉल ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन (अंतरिक्ष अन्वेषण गैलरी)ह्ण देश की अत्याधुनिक एवं अनुभवात्मक विज्ञान गैलरियों में से एक है। केन्द्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (एनसीएसएम) और जिला प्रशासन भोपाल के सहयोग से विकसित यह गैलरी आगंतुकों को ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर आधुनिक अंतरिक्ष अभियानों तक की वैज्ञानिक यात्रा का सजीव अनुभव कराती है।

उच्च शिक्षण संस्थानों को गांवों से जोड़ेगा उन्नत भारत अभियान

भोपाल। उच्च शिक्षा को समाज और ग्रामीण विकास से जोड़ने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की सहभागिता उन्नत भारत अभियान में सुनिश्चित की जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सभी पारंपरिक विश्वविद्यालयों, शासकीय एवं अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों और निजी विश्वविद्यालयों को उन्नत भारत अभियान के पोर्टल पर पंजीयन कर सक्रिय भागीदारी करने के निर्देश दिए गए हैं। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित उन्नत भारत अभियान का उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों और शिक्षकों को ग्रामीण समुदायों से जोड़कर समावेशी विकास को बढ़ावा देना है।

जिला न्यायालय के आदेश पर चलित न्यायालय लगाया गया

भोपाल। दिनांक-14.07.2026 दिन मंगलवार को जिला न्यायालय के आदेश पर चलित न्यायालय लगाया गया। अभियान का नेतृत्व चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अग्नीन्ध्र कुमार द्विवेदी ने किया। उनके सहायतार्थ प्रियंक दुबे, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भोपाल, विजय कुमार पाठक, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल, भारत सिंह रघुवंशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल, शरद जायसवाल, न्यायिक मजिस्टेज्ट

प्रथम श्रेणी भोपाल, यातायात पुलिस की ओर से 01 एसीपी, 03 निरीक्षक, सूबेदार-02 कुल-35 का बल व थाना एमपी नगर थाना प्रभारी एवं सहयसेगी स्टॉफ की संयुक्त टीम ने वाहनों की सघन जांच की।

डीबी मॉल के सामने चले अभियान के दौरान हुटर लगाये हुए वाहन, सायरन,ब्लैक फिल्म व अन्य धाराओं कुल-137 वाहनों पर चालानी कार्यवाही की गई।

मुख्यताः ब्लैक फिल्म, हुटर व सायरन वाले वाहन निशाने पर रहें। अभियान के दौरान अवैध रूप से हूटर, सायरन और लाल-नीली बत्ती का उपयोग करने वाले वाहनों पर कार्यवाही की एवं वाहनों से मौके पर ही अवैध हुटर और सायरन हटवाकर जप्त किये।

नगरीय पुलिस भोपाल ने आम जनता से अपील की है कि अपने व अन्य नागरिकों के जीवन, शरीर व वाहनों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए यातायात नियमों का पालन करना सुनिश्चित करें तथा यातायात व्यवस्था में सहयोग प्रदान करें । किसी प्रकार की असुविधा होने पर यातायात दूरभाष नं. 0755-2677340, 2443850 हेल्प लाईन न-7587602055 पर सम्पर्क करें।

डायल-112 की त्वरित कार्रवाई से पानी में डूब रही महिला को मिला जीवनदान

भोपाल। मध्यप्रदेश पुलिस की आपातकालीन सेवा डायल-112 ने एक बार फिर अपनी त्वरित प्रतिक्रिया और मानवीय संवेदनशीलता का परिचय देते हुए नर्मदापुरम में पानी में डूब रही एक महिला का जीवन बचाया। पुलिसकर्मियों की सूझबूझ, साहस और समय पर दिए गए सीपीआर (उॅ१िङ्कस्न४ॅङ्कललॅ१८ फी२४२२३ङ्कल्ल) के कारण महिला की सांसें वापस लौटीं और उसे सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया गया।

13 जुलाई को डायल-112 को सूचना प्राप्त हुई कि नर्मदापुरम के पोस्ट ऑफिस घाट पर एक महिला पानी में डूब रही है। सूचना मिलते ही डायल-112 की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। वहां एक महिला पानी में पेट के बल अचेत अवस्था में मिली। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डायल-112 में तैनात प्रधान आरक्षक श्री राकेश भिलाला ने बिना समय गंवाए महिला को सुरक्षित पानी से बाहर निकाला। महिला की हालत गंभीर होने पर थाना कोतवाली में पदस्थ उप निरीक्षक सुश्री दीपिका लोखंडे को तत्काल मौके पर बुलाया गया। उन्होंने अपनी व्यावसायिक दक्षता और सूझबूझ का परिचय देते हुए महिला को तत्काल सीपीआर दिया, जिससे उसकी सांसें पुनः चलने लगीं।

प्रदेश में 30 जुलाई तक चलेगा नशा मुक्ति अभियान

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि 'नशे से दूरी है जरूरी 2.0 जागरूकता अभियान' ने सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत समाज को जागृत करने का कार्य किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में मध्यप्रदेश ने नक्सलवाद को डेडलाइन से पहले खत्म कर दिया गया है।

नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ नरमी नहीं, पेश आएं सख्ती से

प्रदेश से अब लाल सलाम को आखिरी सलाम कर दिया गया है। राज्य सरकार पुलिस विभाग में पदोन्नति के साथ सभी अच्छे कार्यों के लिए साथ खड़ी है। नशे का कोई भी प्रकार एक व्यक्ति और समाज को नष्ट करता है। वर्तमान दौर में नशे की कई प्रकार की चुनौतियां हैं। हमारी सरकार ने नशा मुक्त मध्यप्रदेश बनाने की दिशा में आगे बढ़ते हुए 19 धार्मिक स्थलों के आसपास नशा और शराबबंदी लागू की है। नशा मुक्ति अभियान में धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं भी अहम भूमिका निभा रही हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव रवीन्द्र भवन में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान की पूर्व संध्या पर आयोजित शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नशा मुक्त मध्यप्रदेश बनाने और नशा न करने की शपथ दिलवाई।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पहले कहा जाता था कि अगर किसी को बर्बाद करना है तो उसे नशे की लत लगा दो, पूरा परिवार अपने आप खत्म हो जाएगा। राज्य सरकार हर तरह के नशे के खिलाफ कठोर कदम उठा रही है। इसमें समाजिक जागृति की भी आवश्यकता भी है। प्रदेश की पुलिस नशे के अवैध कारोबार में लिप्त संगठित गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है।

मध्यप्रदेश में वित्तीय संव्यवहारों को सुगम बनाने की बड़ी पहल

भोपाल। शासकीय वित्तीय संव्यवहारों को अधिक सुचारू, पारदर्शी और त्रुटिहीन बनाने की दिशा में राज्य शासन ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आयुक्त, कोष एवं लेखा के विशेष दिशा-निर्देशों के तहत, राज्य के वित्त विभाग के एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (क्कटकर) सॉफ्टवेयर से जुड़ी तकनीकी समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिये 16 और 17 जुलाई 2026 को दो दिवसीय विशेष का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य वित्तीय संव्यवहारों में आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को आ रही तकनीकी जटिलताओं और बाधाओं को ऑन-द-स्पॉट दूर करना है।

जेलों की सुरक्षा एवं व्यवस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए महानिदेशक डॉ. कपूर ने किया जेल का आकस्मिक निरीक्षण

भोपाल। प्रदेश की जेलों में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, मध्यप्रदेश डॉ. वरुण कपूर द्वारा 13 जुलाई 2026 को देवास जिले की सब जेल सोनकच्छ का आकस्मिक निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान डॉ. कपूर ने जेल की पाकशाला, गोदाम, बैरकों सहित विभिन्न व्यवस्थाओं का गहन अवलोकन किया तथा सुरक्षा, स्वच्छता एवं बंदियों के रखरखाव से संबंधित व्यवस्थाओं में आवश्यक सुधार के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने जेल प्रशासन को आवश्यक मरम्मत एवं आधारभूत

सुविधाओं के उन्नयन के लिये प्रस्ताव शीघ्र जेल मुख्यालय भेजने के निर्देश भी दिए। महानिदेशक डॉ. कपूर ने निरीक्षण में केवल बंदियों की समस्याओं का ही नहीं, बल्कि जेल कर्मचारियों की समस्याओं एवं आवश्यकताओं का भी गंभीरता से संज्ञान लिया। उन्होंने कर्मचारियों के लिए नवीन आवासों का शीघ्र निर्माण कराए जाने तथा आवश्यकतानुसार बजट उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। साथ ही जेल परिसर में आवश्यक सुधार एवं मरम्मत कार्यों को प्राथमिकता के साथ संपादित करने पर बल दिया। निरीक्षण में जिला जेल देवास के जेल अधीक्षक श्री विद्याभूषण प्रसाद, सब जेल सोनकच्छ के सहायक जेल अधीक्षक श्री बुद्धिविलास आरख सहित समस्त जेल अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। महानिदेशक जेल डॉ. वरुण कपूर ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान के अंतर्गत जेल परिसर में वृक्षारोपण भी किया तथा सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अधिकाधिक पौधारोपण कर उनके संरक्षण का संदेश दिया।

महत्वपूर्ण ख़बर

महिला क्रिकेट को नई दिशा देने घरेलू स्तर पर लाल गेंद के मुकाबले शुरू करें

- चेन्नई। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान शांता रंगास्वामी ने कहा है कि महिला क्रिकेट को एक नई दिशा देने और खिलाड़ियों के कौशल को निखारने के लिए अधिक से अधिक टेस्ट मैचों का आयोजन किया जाना चाहिये। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) से घरेलू स्तर पर लाल गेंद की क्रिकेट को पूरी तरह से दोबारा शुरू करने की मांग की है। इस पूर्व कप्तान के अनुसार बेहतर तकनीक वाले खिलाड़ियों को तैयार करने में लाल गेंद के क्रिकेट का महत्व सबसे अधिक है। रंगास्वामी ने कहा, जब मैं बीसीसीआई की शीर्ष परिषद की सदस्य थी, तो मैंने अक्सर महिला क्रिकेट में लंबी अवधि के प्रारूप की प्रतियोगिताओं के आयोजन पर जोर दिया था। पिछले साल इसे फिर से शुरू किया गया, पर यह केवल अंतरक्षेत्रीय स्तर पर और वह भी नॉकआउट प्रारूप में ही सीमित रही जो पर्याप्त नहीं है। उन्होंने बीसीसीआई से कहा है कि वह अंडर-19, अंडर-23 और सीनियर टीमों के लिए पहले की तरह ही टेस्ट मेचों की प्रतियोगिताओं को शुरू करे।

अफगान महिला शरणार्थी क्रिकेटरों के लिए डेवलपमेंट पाथवे प्रोग्राम जारी रहेगा : आईसीसी

एडिनबर्ग। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने अपने एक अहम फैसले में अफगान महिला शरणार्थी क्रिकेटरों के लिए डेवलपमेंट पाथवे प्रोग्राम को जारी रखने की घोषणा की है। इस ऐतिहासिक फैसले के साथ ही आईसीसी बोर्ड ने एक विशेष टास्क फोर्स का भी गठन किया है, जिससे साल 2030 तक इन महिला खिलाड़ियों को आईसीसी के क्वालिफिकेशन पाथवे में शामिल करने के लिए भविष्य की योजना बनायी जा सके। जिम्मेदारी सौंपी गई है।

आईसीसी की इस सालान बोर्ड बैठक में स्वतंत्र निदेशक डॉ. रोज रिवाज और आईसीसी मुख्य कार्यकारी समिति की सदस्य सारा कीन को भी स्पेशल टास्क फोर्स में शामिल किये जाने पर सहमति बन गयी। ये दोनों ही बीसीसीआई, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर काम करेंगे। इस टास्क फोर्स का मुख्य उद्देश्य महिला क्रिकेट कार्यक्रम की लगातार निगरानी करना है, जिससे खिलाड़ियों को अधिक से अधिक अवसर मिल सकें।

डॉ. रॉस रिवाज ने इस अवसर पर कहा, टास्क फोर्स को एक स्पष्ट और टिकाऊ रोडमैप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसका लक्ष्य संरचित कोचिंग, सार्थक प्रतिस्पर्धी अवसरों और सही हाई-परफॉर्मेंस पाथवे के माध्यम से अफगान महिला शरणार्थी क्रिकेटरों के लगातार विकास में सहायता करना है। डॉ. रिवाज ने साथ ही कहा कि यह कार्यक्रम क्रिकेट के माध्यम से अवसर पैदा करने की आईसीसी की प्रतिबद्धता को दशार्ता है। उन्होंने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को उद्देश्य, ईमानदारी और दीर्घकालिक स्थिरता के साथ पूरा करने के लिए टास्क फोर्स के अन्य सदस्यों और डिलीवरी पार्टनर्स के साथ मिलकर काम करने की अपनी उत्सुकता व्यक्त की।

यह समर्थन केवल प्रशिक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें उनके घरेलू इलाकों में क्रिकेट और स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग (एसएंडसी) कोच के साथ-साथ फिजियोथेरेपी की सुविधा भी शामिल है। धीरे-धीरे, खिलाड़ियों के लिए खेल के समय को भी बढ़ाया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और कनाडा जैसे देशों में रहने वाली खिलाड़ियों को अपने स्थानीय क्रिकेट वातावरण में एकीकृत किया जाएगा, जहाँ उन्हें नियमित प्रशिक्षण और खेलने के पर्याप्त अवसर मिलते रहेंगे। इसके अतिरिक्त, इस कार्यक्रम के तहत खिलाड़ियों को एक समूह के रूप में प्रशिक्षण लेने और मुकाबले में भाग लेने के अवसर मिलते रहेंगे, जैसा कि पिछले 12 महीनों में भारत और इंग्लैंड के सफल दौरों के दौरान देखा गया था।

बीडब्ल्यूएफ विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप अगले माह, भारतीय दल की अगुवाई करेंगी सिंधु

नई दिल्ली। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन (बीडब्ल्यूएफ) विश्व चैंपियनशिप 17 से 23 अगस्त तक नई दिल्ली में होगी। इसमें 10 सदस्यीय भारतीय बैडमिंटन टीम की अगुवाई ओलंपिक पदक विजेता पी वी सिंधु करेगी। बीडब्ल्यूएफ ने इस टूनार्मेंट के लिए क्वालिफिकेशन सूची जारी कर दी है, जिसमें भारत के कुल 10 खिलाड़ियों को पांच स्पधार्ओं में उतरने का अवसर मिला है। इन खिलाड़ियों में सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की देश की शीर्ष पुरुष युगल जोड़ी भी शामिल है।

सिंधु को बीडब्ल्यूएफ के नियमों के तहत मेजबान देश की प्रतिनिधि के तौर पर महिला एकल ड्रॉ में जगह मिली है। यह क्वालिफिकेशन सूची 28 अप्रैल की वर्ल्ड बैडमिंटन रैंकिंग पर आधारित है, जिसमें पुरुष और महिला एकल में 64-64 खिलाड़ी और प्रत्येक युगल स्पर्धा में 48-48 जोड़ियां शामिल हैं। नियमानुसार, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में प्रत्येक वर्ग में भारत के दो खिलाड़ियों को सीधे प्रवेश मिला है। वहीं पुरुष एकल वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी करेंगे, जिन्होंने अपनी रैंकिंग के बल पर प्रवेश हासिल किय है। वहीं, महिला एकल में सिंधु के साथ उभरती खिलाड़ी उन्नति हुड्डा को भी जगह मिली है।

सीए ने जारी किया बीबीएल 2026-27 सत्र का कार्यक्रम

12 दिसंबर को चेन्नई में खेला जाएगा पहला मैच

मेलबर्न। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) ने घरेलू बिग बैश लीग (बीबीएल) 2026-27 सत्र का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है। महत्वपूर्ण बात ये है कि इस सत्र का शुरूआती मुकाबला भारत में खेला जाएगा। सत्र की शुरूआत 12 दिसंबर, 2026 को हो रही है और इसका खिताबी मुकाबला 26 जनवरी, 2027 को खेला जाएगा पर सबसे अहम बात ये है कि लीग के 15 साल के इतिहास में ये पहली बार होगा टूनार्मेंट की शुरूआत भारत में खेले गये मैच से होगी। ये मैच चेन्नई में खेला जाएगा। ये दिखाता है कि वैश्विक क्रिकेट परिदृश्य में भारत का प्रभाव बढ़ता जा रहा है।

लीग का पहला और ऐतिहासिक मुकाबला चेन्नई के प्रतिष्ठित एमए चिदंबरम क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इस उद्घाटन मैच में डिफेंडिंग चैंपियन पर्थ स्कॉर्चर्स और मेलबर्न रेनेगेड्स के बीच टक्कर होगी। यह मैच न केवल बीबीएल के लिए एक नई शुरूआत का प्रतीक होगा, बल्कि भारतीय दर्शकों को अपनी धरती पर एक विदेशी टी-20 लीग का रोमांचक मुकाबला देखने का अवसर मिलेगा। इसके लिए मेलबर्न रेनेगेड्स को घरेलू टीम का दर्जा दिया गया है जिससे इस आयोजन की भव्यता नजर आती है।

यह फैसला सीए की एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत वे दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बाजार भारत में अपनी लीग की पैठ बनाना चाहते हैं। भारत में क्रिकेट के प्रति दीवानगी और दर्शकों की विशाल संख्या को देखते हुए। सीऐ को उम्मीद है कि उसे अच्छा खासा राजस्व मिलेगा। इस मैच के सफल होने पर भविष्य में वह और भी मैचों का आयोजन भरत में कर सकता है। चेन्नई में यह शुरूआत मैच बीबीएल की वैश्विक पहुंच और ब्रांड वैल्यू को निश्चित रूप से नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। यह कदम वैश्विक टी-20 लीग के बढ़ते प्रतिस्पर्धात्मक माहौल में बीबीएल को प्रासंगिक और आकर्षक बनाए रखने में भी मदद करेगा।

इस ऐतिहासिक घोषणा का महत्व सिर्फ क्रिकेट तक ही सीमित नहीं है। यह घटना भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच गहरे होते राजनयिक और सांस्कृतिक संबंधों को भी दशार्ती है। हाल ही में स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया दौरे में मेलबर्न क्रिकेट मैदान में बीबीएल के पहले मैच के भरता में आयोजित किये जाने की घोषणा की थी।

आगामी बीबीएल सीजन में प्लेऑफ और फाइनल सहित कुल 44 मैच खेले जाएंगे, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों के साथ-साथ अब भारतीय दर्शक भी शुरू से ही इस लीग से जुड़ पाएंगे। चेन्नई में होने वाला यह मैच सिर्फ एक खेल आयोजन नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक आदान-प्रदान और क्रिकेट के जुनून का एक उत्सव होगा। यह बीबीएल के इतिहास में एक नया अध्याय लिखेगा और क्रिकेट प्रेमियों को 2026-27 के सीजन का बेसब्री से इंतजार रहेगा।

बीबीएल 2026-27 का पूरा शेड्यूल

तारीख	मैच	वेन्यू
12 दिसंबर 2026	मेलबर्न रेनेगेड्स बनाम पर्थ स्कॉर्चर्स	एम. ए. चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई
15 दिसंबर 2026	ब्रिस्बेन हीट बनाम सिडनी सिक्सर्स	द गाबा, ब्रिस्बेन
16 दिसंबर 2026	सिडनी थंडर बनाम एडिलेड स्ट्राइकर्स	मनुका ओवल, कैनबरा
17 दिसंबर 2026	होबार्ट हरिकेंस बनाम ब्रिस्बेन हीट	बेलेरिव ओवल, होबार्ट
18 दिसंबर 2026	मेलबर्न स्टार्स बनाम एडिलेड स्ट्राइकर्स	मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, मेलबर्न
19 दिसंबर 2026	सिडनी थंडर बनाम सिडनी सिक्सर्स	सिडनी शोग्राउंड स्टेडियम, सिडनी
20 दिसंबर 2026	पर्थ स्कॉर्चर्स बनाम होबार्ट हरिकेंस	पर्थ स्टेडियम, पर्थ
21 दिसंबर 2026	मेलबर्न स्टार्स बनाम ब्रिस्बेन हीट	जंक्शन ओवल, मेलबर्न
22 दिसंबर 2026	सिडनी सिक्सर्स बनाम मेलबर्न रेनेगेड्स	सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, सिडनी
23 दिसंबर 2026	एडिलेड स्ट्राइकर्स बनाम सिडनी थंडर	एडिलेड ओवल, एडिलेड
24 दिसंबर 2026	मेलबर्न रेनेगेड्स बनाम होबार्ट हरिकेंस	जंक्शन ओवल, मेलबर्न
26 दिसंबर 2026	सिडनी सिक्सर्स बनाम ब्रिस्बेन हीट	सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, सिडनी
26 दिसंबर 2026	पर्थ स्कॉर्चर्स बनाम मेलबर्न स्टार्स	पर्थ स्टेडियम, पर्थ
27 दिसंबर 2026	सिडनी थंडर बनाम मेलबर्न रेनेगेड्स	सिडनी शोग्राउंड स्टेडियम, सिडनी
28 दिसंबर 2026	ब्रिस्बेन हीट बनाम एडिलेड स्ट्राइकर्स	द गाबा, ब्रिस्बेन
29 दिसंबर 2026	होबार्ट हरिकेंस बनाम मेलबर्न स्टार्स	बेलेरिव ओवल, होबार्ट
30 दिसंबर 2026	पर्थ स्कॉर्चर्स बनाम सिडनी थंडर	पर्थ स्टेडियम, पर्थ
31 दिसंबर 2026	एडिलेड स्ट्राइकर्स बनाम मेलबर्न स्टार्स	एडिलेड ओवल, एडिलेड
1 जनवरी 2027	मेलबर्न रेनेगेड्स बनाम सिडनी सिक्सर्स	मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, मेलबर्न
1 जनवरी 2027	ब्रिस्बेन हीट बनामहोबार्ट हरिकेंस	द गाबा, ब्रिस्बेन
2 जनवरी 2027	सिडनी थंडर बनाम पर्थ स्कॉर्चर्स	सिडनी शोग्राउंड स्टेडियम, सिडनी
3 जनवरी 2027	सिडनी सिक्सर्स बनाम एडिलेड स्ट्राइकर्स	मनुका ओवल, कैनबरा
4 जनवरी 2027	मेलबर्न स्टार्स बनाम मेलबर्न रेनेगेड्स	मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, मेलबर्न
4 जनवरी 2027	पर्थ स्कॉर्चर्स बनाम ब्रिस्बेन हीट	पर्थ स्टेडियम, पर्थ
5 जनवरी 2027	होबार्ट हरिकेंस बनाम सिडनी थंडर	बेलेरिव ओवल, होबार्ट
6 जनवरी 2027	एडिलेड स्ट्राइकर्स बनाम मेलबर्न रेनेगेड्स	एडिलेड ओवल, एडिलेड
7 जनवरी 2027	मेलबर्न स्टार्स बनामसिडनी सिक्सर्स	मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, मेलबर्न
8 जनवरी 2027	ब्रिस्बेन हीट बनाम पर्थ स्कॉर्चर्स	द गाबा, ब्रिस्बेन
9 जनवरी 2027	होबार्ट हरिकेंस बनाम एडिलेड स्ट्राइकर्स	ऑरोरा स्टेडियम, लॉन्सेस्टन
10 जनवरी 2027	सिडनी सिक्सर्स बनाम पर्थ स्कॉर्चर्स	सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, सिडनी
10 जनवरी 2027	मेलबर्न रेनेगेड्स बनाम ब्रिस्बेन हीट	जंक्शन ओवल, मेलबर्न
11 जनवरी 2027	सिडनी थंडर बनाम मेलबर्न स्टार्स	मनुका ओवल, कैनबरा
12 जनवरी 2027	एडिलेड स्ट्राइकर्स बनाम होबार्ट हरिकेंस	एडिलेड ओवल, एडिलेड
13 जनवरी 2027	पर्थ स्कॉर्चर्स बनाम मेलबर्न रेनेगेड्स	पर्थ स्टेडियम, पर्थ
14 जनवरी 2027	मेलबर्न स्टार्स बनाम होबार्ट हरिकेंस	मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, मेलबर्न
15 जनवरी 2027	सिडनी सिक्सर्स बनाम सिडनी थंडर	सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, सिडनी
16 जनवरी 2027	एडिलेड स्ट्राइकर्स बनाम पर्थ स्कॉर्चर्स	एडिलेड ओवल, एडिलेड
16 जनवरी 2027	मेलबर्न रेनेगेड्स बनाम मेलबर्न स्टार्स	मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, मेलबर्न
17 जनवरी 2027	होबार्ट हरिकेंस बनाम सिडनी सिक्सर्स	बेलेरिव ओवल, होबार्ट
17 जनवरी 2027	ब्रिस्बेन हीट बनाम सिडनी थंडर	द गाबा, ब्रिस्बेन
19 जनवरी 2027	क्वालिफायर	स्थान तय होना बाकी (टीबीसी)
20 जनवरी 2027	नॉकआउट	स्थान तय होना बाकी (टीबीसी)
23 जनवरी 2027	चैलेंजर	स्थान तय होना बाकी (टीबीसी)
26 जनवरी 2027	फाइनल	स्थान तय होना बाकी (टीबीसी)

बल्लेबाज हनूमा ने गंभीर पर अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को ही अवसर देने का आरोप लगाया

मुम्बई। भारतीय टीम से बाहर चल रहे बल्लेबाज हनुमा विहारी ने टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर पर जमकर निशान साधा है। हनुमा ने कहा है कि गंभीर अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को वरीयता देते है। इसी कारण आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में भारतीय टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पायी। हनुमा ने कहा कि खराब फॉर्म के बाद भी ऑलराउंडर शिवम दुबे और वॉशिंगटन सुंदर को लगातार अवसर दिये जा रहे है। इसका कारण है कि उनके कुछ पसंदीदा खिलाड़ी हैं जिन्हें वह लगातार अवसर देना चाहते हैं। फिर चाहे वे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हों यहा नहीं। इस क्रिकेटर ने टीम में कुछ खिलाड़ियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, शिवम न तो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, न ही बल्लेबाजी फिर भी हर मैच में नजर आ रहे हैं।। साथ ही कहा कि वाशिंगटन सुंदर अभी भी टीम में क्यों बने हुए हैं जबकि पिछले कुछ समय में एक बार भी वह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाये हैं। हनुमा री ने टीम में लगातार बदलावों को लेकर भी गंभीर की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि अनुभवी संजू सैमसन को आयरलैंड में दो अवसर देन के बाद बाहर कर दिया गया, और फिर वैभव सूर्यवंशी के साथ भी यही हुआ। इससे टीम में असुरक्षा की भावना बढ़ी है। उन्होंने कहा, अगर आप प्रदर्शन नहीं करते हैं, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। आपको खिलाड़ियों को लंबा अवसर देना चाहिए। अगर आप वैभव को शामिल कर रहे हैं तो उसे कम से कम उसे पांच या छह मैच दें और फिर तय करें कि वह काफी अच्छा है या नहीं। मुझे नहीं लगता कि यह सही रवैया है। खिलाड़ियों के लिए सुरक्षा जरूरी है। स्पिनरों के चयन पर भी उन्होंने सवाल उठाए, चाहे वह वरुण चक्रवर्ती हों, अक्षर पटेल या रवि बिश्नोई। उन्होंने पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव की कप्तानी के दौर से तुलना करते हुए कहा कि तब भी बदलाव होते थे, पर बहुत कम।

कारोबार

ईरान पर अमेरिका का बड़ा आर्थिक प्रहार, तेल निर्यात नेटवर्क से जुड़े 50 से अधिक ठिकाने बैन

नई दिल्ली। वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव के बीच अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपने आर्थिक हमलों को और तेज कर दिया है। अमेरिकी वित्त विभाग के 'ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल' (ओएफएसी) ने ईरान के अवैध तेल परिवहन और प्रतिबंधों को दरकिनार करने वाले एक बड़े नेटवर्क पर कड़ा प्रहार किया है। इस कार्रवाई के तहत ईरान के ऊर्जा क्षेत्र के दिग्गज मोहम्मद हुसैन शमखानी के नियंत्रण वाले समुद्री व्यापार नेटवर्क से जुड़े 50 से अधिक लोगों, कंपनियों और जहाजों को प्रतिबंधित सूची (ब्लैकलिस्ट) में डाल दिया गया है। होर्मुज जलडमरूमध्य में व्यापारिक जहाजों पर हाल ही में हुए हमलों और बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका का यह कदम वैश्विक ऊर्जा बाजार और समुद्री सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

अमेरिकी वित्त विभाग द्वारा घोषित इन दंडात्मक उपायों में मुख्य रूप से मोहम्मद हुसैन शमखानी के व्यापक समुद्री व्यापार तंत्र को निशाना बनाया गया है। इस कार्रवाई के अंतर्गत कुलः छह लोगों को ब्लैकलिस्ट किया गया है, जिनमें असगर अघिली देहकोर्डी और बेहजाद मोघदास जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। 24 कॉरपोरेट कंपनियों और 20 समुद्री जहाजों पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, ये सभी आरोपी वित्तीय ब्रोकरों, लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस, समुद्री प्रबंधकों और विदेशों में स्थित शेल कंपनियों के एक बेहद जटिल नेटवर्क के जरिए व्यापारिक प्रतिबंधों को बाईपास कर रहे थे। इस कार्रवाई के बाद, इन प्रतिबंधित पक्षों की अमेरिकी कानूनी अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी संपत्तियों या कानूनी हितों को तत्काल प्रभाव से ब्लॉक कर दिया गया है।

अमेरिका ने यह सख्त कदम क्यों उठाया है?

अमेरिकी प्रशासन का साफ तौर पर मानना है कि ईरान का यह अवैध तेल नेटवर्क उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ बना हुआ है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के अनुसार, ₹ईरानी शासन धोखे और फरेब पर जीवित है, और शमखानी का यह नेटवर्क उसके सबसे अधिक मुनाफा कमाने वाले इंजनों में से एक है।₹ बेसेंट ने जोर देकर कहा कि इन प्रतिबंधों का मुख्य उद्देश्य उस वित्तीय जीवन रेखा को काटना है जो अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय समुद्री परिवहन के लिए खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों को हवा देती है। यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब होर्मुज जलडमरूमध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमले बढ़े हैं, जिसका आरोप वाशिंगटन ने सीधे तौर पर तेहरान पर लगाया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने कहा कि यह कार्रवाई शमखानी के अवैध शिपिंग और प्रतिबंधों से बचने वाले नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए तैयार की गई है, जिसके पैसे से व्यापारिक जहाजों पर हमलों की फंडिंग की जाती थी।

अब आगे क्या हो सकता है?

वाशिंगटन की इस चौतरफा कार्रवाई से यह साफ है कि वह ईरान पर अधिकतम आर्थिक दबाव बनाने की नीति पर कायम रहेगा। अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक, प्रतिबंधित नेटवर्क में ईरानी नागरिकों के साथ-साथ विदेशी नागरिक और विदेशी कंपनियां भी शामिल थीं, जो इस अवैध व्यापार को बढ़ावा दे रही थीं। अब देखना यह होगा कि इस कड़े आर्थिक प्रहार के बाद ईरान की क्या प्रतिक्रिया होती है और क्या इससे होर्मुज जलडमरूमध्य में व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित हो पाती है या फिर तनाव और अधिक भड़कता है।

शेयर बाजार में फिर आई तेजी, सेंसेक्स में 500 अंक का उछाल; निफ्टी 24000 के पार

नई दिल्ली। शेयर बाजार में एक बार फिर से तेजी लौट आई है. बुधवार को बाजार ग्रीन जोन में ओपन हुआ. खुलते ही बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली. सेंसेक्स और निफ्टी50 में भी जोरदार उछाल देखा गया. बता दें कि मंगलवार को सेंसेक्स 561 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ लेकिन आज यानी बुधवार को सेंसेक्स 137 अंक के उछाल के साथ 77192 अंक पर खुला. उसके बाद इसमें जबरदस्त तेजी देखने को मिली. जबकि निफ्टी50 आज 33 अंक की तेजी के साथ 24085 के स्तर पर ओपन हुआ, कुछ ही देर में निफ्टी 150 अंकों के उछाल के साथ ट्रेड करता दिखा.

बुधवार के शुरूआती कारोबार में फाइनेंशियल सर्विसेज और बैंकिंग शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली. इसके साथ ही निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी ऑटो, निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और रियल्टी सेक्टर्स में भी अच्छी तेजी दर्ज की गई. जबकि फाइनेंशियल सर्विसेज में सबसे ज्यादा 1.08 प्रतिशत का उछाल दर्ज किया गया. वहीं दूसरी ओर ऑटो सेक्टर में 0.90 प्रतिशत और बैंकिंग सेक्टर 0.83 फीसदी की बढ़त के साथ कारोबार करते दिख. इस उछाल के बीच कळ सेक्टर में आज भी सुस्ती देखने को मिली. बुधवार के शुरूआती कारोबार में निफ्टी कळ करीब 1.51 प्रतिशत टूटकर कारोबार करता दिखा.

कारोबारी सत्र के तीसरे दिन यानी बुधवार को एशियाई बाजार भी बढ़त के साथ ओपन हुए. शुरूआती कारोबार में सभी बाजार में शानदार उछाल देखा गया. इस दौरान जापान का बेंचमार्क 225 इंडेक्स 0.6 फीसदी तेजी के साथ कारोबार करता दिखा. जबकि टॉपिक्स में 0.53 फीसदी की तेजी देखी गई. वहीं दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 6.5 फीसदी की जबरदस्त तेजी देखने को मिली.

जबकि दक्षिण कोरिया के स्मॉल-कैप कोस्डैक में 4.9 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई. बुधवार के शुरूआती कारोबार में हांगकांग का हैंगसेंग भी 0.52 फीसदी की तेजी के साथ 24340.73 के स्तर पर पहुंच गया. उधर अमेरिका में जून महीने की हेडलाइन रिटेल महंगाई दर (उढक) गिरकर 3.5 फीसदी हो गई, जो 3.8 प्रतिशत अनुमान से काफी कम है. बता दें कि इस गिरावट के चलते फेडरल रिजर्व द्वारा जुलाई में ब्याज दरें बढ़ाए जाने की संभावना को भी काफी कम कर दिया है. एशियाई बाजारों के साथ अमेरिकी बाजार में भी शानदार रिकवरी देखी गई. बेंचमार्क से जुड़े यूएस स्टॉक फ्यूचर्स भी उछाल के साथ ट्रेड करता दिखा. वहीं डाऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्यूचर्स में 13 अंक यानी 0.02 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली. एसएंडपी 500 फ्यूचर्स में भी 0.11 प्रतिशत और नैस्डैक 100 फ्यूचर्स में 0.37 फीसदी की तेजी दर्ज की गई.

बता दें कि अमेरिका में जून महीने की रिटेल महंगाई (उढक) के आंकड़े अनुमान से काफी कम आए हैं. ऐसे में ब्याज दरों में बढ़ोतरी न होने की उम्मीद से टेक और सेमीकंडक्टर शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है.

गडकरी की सलाह

आप चाहें तो 100 फीसद पेट्रोल ज्यादा दाम में खरीद लें

नई दिल्ली। देशभर में ई20 यानी 20 फीसदी एथनॉल मिले हुए पेट्रोल के इस्तेमाल को लेकर जारी चचाओं और सोशल मीडिया पर फैल रही चिंताओं के बीच, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो उपभोक्ता एथनॉल मिश्रित ईंधन का उपयोग नहीं करना चाहते हैं, वे पेट्रोल पंपों पर 100 फीसदी पेट्रोल भी खरीद सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें अधिक कीमत चुकानी होगी। यह बयान ऐसे समय आया है जब ई20 ईंधन देश के लगभग हर फ्यूल स्टेशन पर उपलब्ध है और इसे लेकर वाहन मालिकों के मन में विभिन्न सवाल उठ रहे हैं। गडकरी इससे पहले भी कह चुके हैं कि एथनॉल मिले हुए ईंधन के चलते वाहन खराब होने की कोई समस्या सामने नहीं आई है, जिससे सरकार के एथनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम पर उनका भरोसा कायम है।

सोशल मीडिया पर ईंधन की गुणवत्ता को लेकर प्रसारित हो रहीं चिंताओं को दूर करने और ग्राहकों को आश्वस्त करने के लिए, सार्वजनिक

क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों – इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड – ने देश भर में अपने खुदरा पंपों पर ईंधन गुणवत्ता की जांच तेज कर दी है। इन कंपनियों ने ग्राहकों से अपील की है कि वे ईंधन गुणवत्ता से जुड़ी किसी भी शिकायत को सीधे पेट्रोल पंप या कंपनी के ग्राहक सेवा माध्यमों से दर्ज कराएं और सोशल मीडिया पर प्रसारित अपुष्ट पोस्टों पर भरोसा न करें। यह कदम सरकार और तेल कंपनियों की ओर से उपभोक्ताओं को ई20 ईंधन की सुरक्षा और गुणवत्ता के प्रति आश्वस्त करने का प्रयास है।

इस बीच, आईआईटी कानपुर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में इंजन रिसर्च लैबोरेटरी के परियोजना वैज्ञानिक ध्रुव राज करणा ने भी ई20 ईंधन को लेकर चल रही अफवाहों का खंडन किया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि बड़े पैमाने पर हुए अध्ययन में यह सामने आया है कि ई20 से गाड़ियों के इंजन को नुकसान, जंग लगने या किसी अन्य तकनीकी समस्या होने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। करणा ने यह भी स्पष्ट किया कि संस्थान के अध्ययनों में ई 20 के कारण गाड़ियों के माइलेज में कोई खास कमी नहीं पाई गई है। उनके अनुसार, माइलेज में कोई भी बदलाव दरअसल ईंधन के बजाय गाड़ी चलाने की आदतों, सड़क की स्थिति और गाड़ी के रखरखाव से ज्यादा प्रभावित होता है। शोधकताओं के मुताबिक, अब तक किए गए परीक्षणों में इंजन के टिकाऊपन या गाड़ी की रफ्तार और माइलेज पर ई20 ईंधन का कोई गलत असर नहीं देखा गया है, जो इस नई ईंधन नीति के प्रति वैज्ञानिक समर्थन को दशार्ता है।

सोयाबीन की उन्नत उत्पादन तकनीक

अ. बुवाई के समय किये जाने वाले कार्य

बीज– विभिन्न जातियों के बीज आकार के हिसाब से उपयोग करना चाहिये। छोटे दाने वाले किस्मों (जे. एस. 97–52) की बीजदर 60–70 कि.ग्रा., मध्यम दाने वाली किस्मों (जे.एस. 335, जे. एस. 93–05) की बीजदर 70–75 कि.ग्रा. तथा बढ़े दाने वाली किस्मों (जे. एस. 95–60) की बीज दर 90–100 कि.ग्रा. रखना चाहिये। बीज को फफूंदनाशक दवा कार्बोक्सिन–थायरम (बीटावैक्स पावर) की 2 ग्राम मात्रा द्वारा अथवा ट्राइकोडर्मा विरिडी की 5–8 ग्राम मात्रा के प्रति कि.ग्रा. का उपचार करना आवश्यक है ताकि बीज एवं मृदा जनित बीमारियों से बीज की रक्षा जा सकें।

फफूंदनाशक दवा से उपचार के पश्चात् 5 ग्राम राइजोबियम व 5 ग्राम पी.एम.बी. से बीज को निवेशित करना चाहिये। राइजोबियम जीवाणु, पौधों में जड़ ग्रंथियों की संख्या बढ़ाने में सहायक होते हैं जिससे भूमि में लगभग 20 कि.ग्रा. नत्रजन प्रति हे. वायुमंडल से स्थिर की जाती है तथा पी.एस.बी. कल्चर जमीन में स्थिर स्फुर को घुलनशील अवस्था में लाकर पौधों को उपलब्ध करवाता है।

बुवाई

अच्छे अंकुरण के लिये बोने के समय खेत में 10 सेमी. गहराई तक उपयुक्त नमी होनी चाहिये। बोआई हेतु किस्म के अनुसार कतार से कतार की दूरी 30–45 से.मी. व पौधे से पौधे की दूरी 6–8 से.मी. रखें। बीज को 3.5 से.मी. से अधिक गहराई पर नहीं बोना चाहिये सोयाबीन की 9 लाइनों के बाद एक लाइन की जगह निरीक्षण पट्टी के रूप में छोड़ें। कुल मिलाकर एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में कुल 4–4.5 लाख पौधों की संख्या जरूर होनी चाहिए।

मेढ़नाली पद्धति से सोयाबीन की खेती-

मेढ़वाली पद्धति से सोयाबीन की बुवाई करने से वर्षा की अनिश्चितता से होने वाली हानि की संभावना को कम किया जा सकता है। मेढ़नाली पद्धति में बीजाई मेढ़ो पर की जाती है तथा दो मेढ़ों के मध्य लगभग 15 से.मी. गहरी नाली बनाई जाती है तथा मिट्टी को फसल की कतारों की तरफ कर दिया जाता है। बीज की बीजाई मेढ़ पर होने से अति वर्षा या तेज हवा के समय पौधों के गिरने की संभावना कम हो जाती है तथा अतिरिक्त पानी का निकास हो जाता है। यदि फसल अवधि में अवर्षा या लम्बे अंतराल से वर्षा न होने की स्थिति में नमी की कमी नही हो पाती, क्योंकि खेत की नालियो में नमी की उपलब्धता ज्यादा लम्बे समय तक बनी रहती है। साधारण सीडड्रिल में एक छोटी सी लोहे की पट्टी लगाकर बुबाई का कार्य किया जा सकता है अथवा साधारण सीडड्रिल द्वारा समतल बुवाई करने के पश्चात कतारों के बीच देशी हल चलाकर नाली का निर्माण किया जा सकता है। बुवाई पश्चात् एवं अंकुरण के बाद नाली को अंत मे मिट्टी द्वारा बॉध दिया जाता है जिससे वर्षा के पानी का भूमि में अधिक से अधिक संरक्षण हो। वर्तमान सीडड्रिल के आगे मेढ़वाली (रीज एवं फरो पद्धति) यंत्र का उपयोग करके सीधे बुआई की जा सकती है।

सिंचाई– सोयाबीन में पुष्पन अवस्था व फली अवस्था पर नमी की कमी होने पर सिंचाई करें।

उर्वरक समूह उर्वरक की मात्रा

1.	डी.ए.पी.	100 कि.ग्रा. . पोटाश 30 कि.ग्रा(प्रति हे.)
2.	एन.पी.के	(12:32:16) 150 किग्रा
3.	यूरिया	40 कि.ग्रा. सुपर फास्फेट 350 कि.ग्रा. पोटाश 30 कि.ग्रा.

जहॉ सोयाबीन के पश्चात् गेहूँ की फसल ली जाती है वहॉ 3 वर्षो में एक बार 20 कि.ग्रा. जिंक सल्फेट प्रति हे. के मान से भूमि में अंतिम जुताई के समय अवश्य मिलाना चाहिये। रासायनिक उर्वरकों को कूड़ों में लगभग 5–6 से.मी. की गहराई पर डालना चाहिये। रासायनिक उर्वरकों को बीज के साथ मिलाकर बोनी नहीं करनी चाहिये।

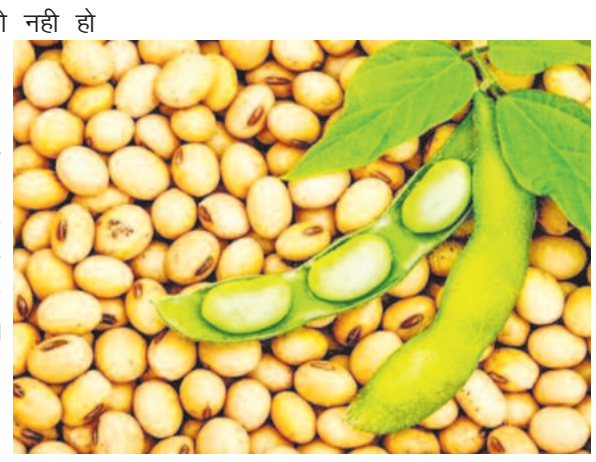

खरपतवार नियंत्रण

सोयाबीन की फसल में खरपतवारों को नष्ट न करने से उत्पादन में 25–70 प्रतिशत तक की कमी हो सकती है। खरपतवार, फसल के लिये भूमि में निहित पोषक तत्वों में से 30–60 कि.ग्रा. नत्रजन, 8–10 कि.ग्रा. स्फुर एवं 40–60 कि.ग्रा. पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से भूमि से शोषित करते है, जिससे पौधों की विकासगति धीमी पड़ जाती है और उत्पादन स्तर गिर जाता है इसके अतिरिक्त खरपतवार फसल को नुकसान पहुँचाने वाले अनेक प्रकार के कीड़े व बीमारियों के रोगाणुओं को भी आश्रय देते हैं। खरपतवार व सोयाबीन फसल की प्रतिस्पर्धा अवधि 20–35 दिन रहती है अतः इससे पूर्व नींदा नियंत्रण आवश्यक है।

- प्रथम निदाई बुवाई के 20–25 दिन बाद व दूसरी निंदाई 40–45 दिन की अवस्था पर करें। अथवा
- बोनी के बाद तथा अंकुरण के पूर्व एलाक्लोर 50 ई.सी. 4 लीटर या पेंडीमिथालीन 30 ई.सी. 3 लीटर को 600–700 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर के मान से भूमि में छिड़काव करें। तत्पश्चात् 25–30 दिन की अवस्था पर निदाई करें।

पोषक तत्व प्रबंधन

अंतिम बखरनी के समय खेत में अच्छी पकी हुई गोबर की खाद का कम्पोस्ट 5–10 टन उपलब्धानुसार प्रति हे. के मान से मिलाना चाहिये। मध्यम उर्वरता वाली भूमि में सोयाबीन की खेती हेतु 20 कि.ग्रा. नत्रजन, 60 कि.ग्रा. स्फुर, 20 कि.ग्रा. पोटाश 20 कि.ग्रा. सल्फर व सूक्ष्म मात्रा में मैग्नीशियम, जस्ता, लोहा की आवश्यकता होती है जिसकी पूर्ति निम्न में से किसी एक उर्वरक समूह से की जा सकती है।

धान रोपाई के परंपरागत तरीकों में बीज को नर्सरी में बोया जाता है फिर पौधे को धीरे से निकाल कर साफ करके गुच्छा बनाकर जुताई किए गए मिट्टी में बोया जाता है। हाथ से रोपाई करने का काम बहुत मुश्किल एवं थकाने वाला काम होता है। धान के रोपाई में कई घंटे तक झुककर काम करने से कई महिला एवं पुरूष के परिस्थिति कई पीढ़ी से किसानी काम का दर्दनाक हिस्सा है।

स्वचालित धान रोपाई यंत्र

आज के समय में खेती मजदूरों के फैक्ट्रियों एवं दूसरे कामों में जाने के कारण रोपाई के समय में मजदूरों में काफी कमी आ गई है। नया तकनीक और किसानी काम में विकास के कारण हाथ रोपाई की जगह अब मशीन रोपाई ले रही है। और इसके लिये धान रोपाई मशीन एक अच्छा उपाय है। मशीन रोपाई के लिए पहला कदम चटाई नुमा नर्सरी तैयार करना होता है जो कि अच्छे परिणाम के लिये बहुत जरूरी है। मशीन रोपा में एक एकड़ खेत के बोवाई करने में आमतौर में 15 से 20 कि.ग्रा. अच्छा बीज काफी होता है। वहीं हाथ से रोपाई करने में 30 कि.ग्रा. बीज लग जाता है। अगर किसान भाई सिस्टम ऑफ राईस इन्टेन्सीफिकेशन 'श्री विधि' को अपनायेंगे तो बीज की खपत और कम हो जायेगी। बुवाई के पहले अंकुरित बीज का महत्व बहुत है। एक साफ बर्तन में साफ पानी लेकर बीज को डालकर धीरे–धीरे हिलायें। खाली और आधे भरे धान को बाहर निकालकर उसमें से अच्छे बीज को बोरी में भर लें। फिर बोरी को 24 घंटे तक पानी में डुबोकर रखें। उसके बाद बोरी को हल्का गर्म और छाया वाली जगह में रखें उसके ऊपर पैरा को 24 घंटे के लिये ढंक दें। अंकुरित होने का समय तापमान पर निर्भर होता है। जब बीज अंकुरित हो जाये और जड़ का शुरूआती चिन्ह दिखें तब बुवाई के लिये बीज तैयार है। जड़ को लंबा नहीं होने देने चाहिए नहीं तो वह बोरी से बाहर आकर एक–

दूसरे से उलझ जायेगी।

मशीनी बोवाई में 1 एकड़ की बुवाई करने के लिए 1.2 मी. चौड़ा और 10 मी. लंबा दो बीज की क्यारी लगती है। नर्सरी के क्यारी को ठीक तरीके से समतल कर लें क्योंकि बीज बुवाई में सभी तरह बराबर मोटाई रहना चाहिए। पानी देने और निकालने के लिये नाली बना देना चाहिए आमतौर पर गोबर खाद या वर्मी कम्पोस्ट 1:3 के अनुपात में मिट्टी में मिलाया जाता है अगर चिकनी मिट्टी हो तो इसमें एक भाग रेत एक भाग गोबर खाद या वर्मी कम्पोस्ट तीन भाग मिट्टी में अच्छी तरह मिलाया जाता है इस मिश्रण में कंकड, पत्थर नहीं रहना चाहिए।

रोपाई के पहले खेत की तैयारी

रोपाई करने के लिये खेत अच्छी तरह से तैयार करना जरूरी है खेत में कंकड पत्थर नहीं हो धान रोपाई मशीन से काम करने के लिए लगभग 10 से 12 से.मी. की गहराई से जुताई होना चाहिए। चिकनी मिट्टी में पावर टिलर या रोटावेटर फिट किये हुए ट्रैक्टर से मताई करनी चाहिए, मताई के बाद खेत के पानी को निकाल लेना चाहिए और 24 से 36 घंटा बाद रोपाई के लिए खेत तैयार हो जाता है। ऐसा करने से खेत में मजबूती आती है जिससे यह मशीन का वजन सह सकता है। मशीन को खेत में उतारने के समय खेत से.मी. पानी होना चाहिए जिससे मशीन की उंगली में पौधे नहीं चिपकते, इसका मतलब यह है कि पानी उंगली को धोने के काम में आता है। जब खेत तैयार होता है तो रोपाई से बस 6 से 12 घंटे से पहले नर्सरी बेड से पानी निकाल लें, क्यारी में से पौधा उठाकर रोपाई से सिडलिंग डिब्बा में सावधानी से रख दें जिस दिन बेड से पानी निकाल लें, क्यारी में से पौधा उठाकर रोपाई से सिडलिंग डिब्बा में सावधानी से रख दें जिस दिन बेड से पौधा निकालें रोपाई उसी दिन करना जरूरी है। किसान भाई अब हम हाथ के रोपाई और मशीनी रोपाई के अंतर को देखते हैं।

अब हम धान रोपाई मशीन के विशेष गुणों में नजर डालते हैं। यह अपने आप चलने वाला बैठकर चलाने वाला मशीन है जो एक ही बार में 8 क्यारी में एके साथ रोपाई कर सकता है। हल्का वजन, 4 एच.पी. डीजल इंजन, खेती के काम करने के लिये लोहे के पहिए और सड़क के लिए टायर होता है। यह मैट और ट्रे नर्सरी दोनों में काम आता है। रोपाई मशीन आसानी से इस्तेमाल होता है, इसमें पौधे से पौधे को हम

10 से.मी. से 23 से.मी. तक बदल सकते है और क्यारी से क्यारी की दूरी 23.8 से.मी. होती है। अच्छा परिणाम के लिये यह ध्यान जरूरी है कि नर्सरी की क्यारी समतल हो। क्यारी में कंकड़ पत्थर नहीं होना चाहिए और ऊंचाई 2 से.मी. से ऊपर न हो। क्यारी को कभी सूखने नहीं देना चाहिए। नर्सरी में यूरिया न छिड़कें, मताई की गहारई ज्यादा न रहे बस 0 से 15 से.मी. हो और खेत समतल रहें।

इन सब बातों को ध्यान में रखकर धान रोपाई मशीन इस्तेमाल करने वालों के लिए एक बचत का सौदा है। मैट नर्सरी उगाना और धान रोपाई मशीन चलाना स्त्री और पुरूष के लिये दोनोंके लिए आसान है। ये हैरानी की बात नहीं है कि अनुसंधानिक वैज्ञानिकों और परीक्षण संस्थानों धान रोपाई मशीन एक मजदूर दोस्त और मेहनत कम करने वाला मशीन है इसके लिये कृषि विभाग द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा है और इसकी खरीदी के लिये कृषि यंत्र व उपकरण योजनांतर्गत अनुदान उपलब्ध है।

मिट्टी, गोबर खाद एवं रेती को जाली से छान लेना चाहिए ताकि कंकड, पत्थर ना रहें। तैयार क्यारी के ऊपर रख दें, मिट्टी के मिश्रण को फ्रेम के सतह तक सभी तरफ समान रूप से फैला दें। फ्रेम इस्तेमाल करने का मकसद यह है कि बीज की बचत करना और पौधों को चादर को आसानी से निकाल लेना और बीज बेड की ऊंचाई 2 से.मी. समान रूप से बनाये रखना। अगर ऊंचाई होगी तो रोपाई ठीक तरीके से नहीं हो पायेगी। अंकुरित बीज के नस्ल अनुसार 120 से 150 ग्रा. हर खंड में समान रूप बुवाई कर देनी चाहिए। अंकुरित बीज का बहुत ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि कोमल जड़ टूटना नहीं चाहिए। फ्रेम निकालने की ये प्रक्रिया तब तक करनी चाहिए जब तक की पूरी क्यारी की बुवाई न हो।

बीज की क्यारी को पैरा या पतला आलू बोरी से ढंक दें ताकि यह बारिश के बूंद और चिड़िया से सुरक्षित हो जाये। मौसम के अनुसार 3 से 4 दिन तक दिन में 2 से 3 बार रोज केन से बीज बेड से पानी दें।

बीज के बेड को कभी भी सूखने न दें चौथे दिन जांच कर लें कि इसका उगना काफी अच्छा है और क्या नर्सरी हरी भरी लग रही हैं, इसमें 2 से 2.5 से.मी. का पौधा दिखना चाहिए। अब धान के पैरा को हटाकर इसमें पानी भर दें, पानी का स्तर बीज के बेड से 2 से.मी. ऊपर या पौधे के आधी ऊंचाई तक ही रखें। नर्सरी में निगरानी रखें अगर बीमारी या कीटाणु का हमला हो तो तुरंत इसका रोकथाम करना चाहिए। बुवाई के 17 से 18 दिन में पौधा 12.5 से 15 सेमी. के ऊंचाई में होगा, आम तौर में जब इसका 3 से 4 पत्ता निकल जाये तो समझना चाहिए कि यह रोपाई करने के लिये तैयार है।

स्वामी, प्रकाशक : अली आदिल खान द्वारा साईं प्रिंटिंग प्रेस डी 85 सेक्टर 8, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर 201301 से मुद्रित और एच 41 ए, अबुल फजल एनक्लेव, जामिया नगर, दक्षिण पूर्व दिल्ली 110025 से प्रकाशित। संपादक : अली आदिल खान
RNI No.: DELMUL/2012/47011 | Email:timesofpedia@gmail.com | समाचार चयन एवं प्रकाशन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार तथा समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन होंगे।